हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

23 अगस्त, 1988

खण्ड 2 अंक 2

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 23 अगस्त, 1988

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(2)26
विभिन्न विशयों को उठाया जाना	(2)28

ध्यानकर्शण प्रस्ताव–	
हरियाणा में वर्श तथा बाढत्र से फसल तथा सम्पति को हुई हानि संम्बंधी	(2)30
वर्श 1983–84 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगो पर चर्चा तथा मतदान	(2)31
बिल्ज–	
(i) दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1988	(2)61
(ii) दि पंजाब टाउनि ाप्स (स्ट्रीट लाइटिंग एण्ड वाटर सप्लाई) फीस हरियाणा रिपील बिल, 1988	(2)73

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 23 अगस्त, 1988

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ में 9:30 बजे हुई। अध्यक्ष (सरदार हरमोहिन्दर सिंह चट्ठा) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एंव उत्तर

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, अब सवाल होंगे।

Setting up of Primary Health Center/Sub-Centre at Rai

***607. Shri Maha Singh:** Will the Minister for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Primary Health Centers/Sub-Centres in Rai constituency of district Sonipat; and

(b) if so, the time by which the said Centres/Sub-Centrs are likely to be opened?

स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती कमला वर्मा):

(क) नहीं।

(ख) प्र न पैदा नहीं होता।

श्री महा सिंहः अध्यक्ष महोदय गवर्नमैंट के नौमर्ज बने हुए हैं कि इतनी आबादी के पीछे इतने पी0एच0सीज0 होंगे या सब–सैन्टर्ज होंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंता हूं कि क्या हल्का राई ये नौर्म्ज लागू नहीं होते?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, मै इन्हे बताना चाहूंगा कि हल्का राई में नौर्म्ज के अनुसार ही पी0 एच0 सी0 और सब–सैन्टर्ज वगैरा बन चुके हैं। अब वहां पर एक कम्यूनिटी हैल्थ सैन्टर बनना हैं, जो बड़खालसा में बनना विचारधीन हैं। वह भी इस साल के अन्त तक हम बना देंगे।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ण्क यसल के अर्से के दौरान इन्होंनें कितने पी0 एच0 सी0 और उप केन्द्र नए खोले हैं? दूसरा सवाल यह हैं कि इनके खोले जाने का क्या माप दण्ड हैं, आया कोई क्षेत्र या उस क्षेत्र की आबादी को ध्यान में रखा जाता है या जनता की मांग पर कोई पी0 एच0 सी0 या सब–सैन्टर वगैरा खोला जाता हैं? इसके साथ ही साथ यह भी बताने का कश्ट करें क जहां पर ये सभी नौर्म्ज पूरे होते हैं, क्या वहां पर सरकार तुरन्त ही यह सब–सैन्टर या पी0 एच0 सी0 वगैरा खोलने का विचार रखती है?

श्रीमति कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, जून 1987 के बाद हम अब तक 9 फीसदी हैल्थ सैन्टर्ज, 19 पी0एच0सीज0 और 201

सब–सैन्टर्ज नए बना चुके हैं। इनका दूसरा सवाल नौमर्ज का हैं। सरकार के नौर्म्ज के मुताबिक 5 हजार की आबादी पर एक सब–सैन्टर 25 हजार से 30 हजार की आबादी पर एक पी0 एच0 सी09 और 1 लाख से अधिक की फण्डज होते जाते हैं उसी हिसाब से हम यह काम रकते जाते है। अब 7 वी पंचवर्शीय योजना मे बजट व निर्धारित लक्ष्यों को दृश्टिगत रखते हुए हम यह काम कर रहे हैं और उसी आधार पर नए उप केन्द्र या पी0 एच0 सी0 बनाते जा रहे हैं।

श्री भागी रामः स्पीकर साहब, इन्होंनें इस सवाले के ''ख'' भाग का जवाब लिखा हैं कि प्र न पैदार नहीं होता। आप जितने भी जवाब पढ़ेगें, उनमें यह लिखा मिलेगा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता, इससे काम लने वाला नहीं हैं अगर इस समय वह काम नहीं हो सकता तो कब तक हो जाएगा यह बता दें? यह तो ना लिखे कि सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, राई क्षेत्र में नीर्म्ज के अनुसार सब केन्द्र पी0 एच0 सी0 याह कम्युनिटी हैल्थ सैन्टर बन चुके हैं, इसलिए जवाब में लिख गया हैं कि प्र न ही पैदा नहीं होता।

श्री महां सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि हल्के की कितनी पापुले ान हैं, वहां पर कितनी पी0 एच0 सीज0 या सब–सैन्टर्ज आदि हैं?

श्रीमती कमला वर्माः अध्यक्ष महोदय, राई हल्के में 4 पी0 एच0. सीज0, 32 सब सैन्टर्ज एक आयुर्वेदिक डिस्पैन्सरी और 2 ई0 एस0 आई0 डिस्पैसरीज खोली जा रही हैं। इसके अलावा, बड़खालसा में पंचायत बिल्डिंग बना कर दे रही हैं जहां पर कम्यूनिटी हैल्थ बना रहे हैं। उम्मीद हैं कि इस साल के अन्त तक सैन्टर चालू हो जाएगा।

श्री भगवान सहाय रावतः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां पर सारे नौर्म्ज पूरे हो चुके हैं, जैसे मेरे हल्के के औरंगाबाद और नांगल जाट दो गांव हैं, वहां पर सारे नौर्म्ज पूरे है लेकिन इस के बावजूद भी वहां पर अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ हैं?

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अभी मंत्री महोदया ने अपने जवाब में बताया था कि अब तक हमने 9 पी0एच0सी0 नए खोले है। पिछले बजट सै ान में पी0 एच0 सी0 खोलने का टारगैट 30–40 के लगभग हैं। चालू साल के 6 महीने बीत चुके हैं और इन 6 महीनों में अभी तक 9 पी0 एच0 सी0 ही पूरे किए गए हैं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या चालू साल के

समाप्त होने तक टारगैट रखा गया हैं, उसे पूरा कर दिया जायेगा?

श्रीमति कमला वर्मा: हमारे काम में कोई कमी नहीं हैं। हम साल के अन्त तक अपना टारगैट पूरा कर लेंगे।

डा0 बृज मोहन: अध्यक्ष महोदय, जगाधरी में 25 बैड्ज का सिविल हस्पताल हैं। वहां की आबादी बहुत अधिक होने की वजह से लोगों को बहुत अधिक परे ाानी का सामना करना पड़ रहा हैं। मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या उस हस्पताल को 25 बैडज से अधिक बढ़ाने की कृपा करेंगी?

श्री अध्यक्ष: यह सवाल जगाधरी का नहीं हैं।

श्री महा सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो संख्या इन्होनें राई हल्के की बताई हैं कि इतने पी0 एच0 सी0 सब–सैन्टर या डिस्पैंसरीज हैं, क्या उसके बारे में ये लिख कर मुझे दे देंगी?

श्रीमती कमला वर्मा: बिल्कुल लिख कर दें दूगी।

Persons registered with Employment Exchanges

***624. Dr. Brij Mohan**: Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state-

(a) the total number of persons registered with the Employment Exchanges in the State during the period from 16th February, 1988 to date, Employment Exchange-wise, separately; anf

(b) the total number of Graduated, Post Graduates, Medical Graduates, Engineering Graduates & Law Graduates registered, separately, in the Employment Exchanges in the State?

श्रम तथा रोजगार मंत्री (श्री बलवीर सिंह):

(क) दिनांक 1–2–88 से 31–1–88 तक राज्य के रोगार कार्यलयों में पजीकृत कुल प्रार्थियों का रोजगार कार्यलय अनुसार ब्योरा सदन के पटल पवर रखा जाता हैं।

(ख) दिनांक 30–6–88 को राजय के रासेजगार कार्यालयों के सजींव रजिस्टर पर कुल स्नातक, स्नातकोत्तर, चिकित्सा स्नातक, इंजीनियरिग स्नातक एवं कानून स्नातक प्रार्थियों की सूचना इस प्रकार हैं–

क्रमांक	श्रेणी	संख्या
1	स्नातक	21961
2	स्नातकोत्तर	5517
3	चिकित्सा स्नातक	1000
4	इंजीनियरिंग स्नातक	366
5	कानून स्नातक	233

ब्योरा

क्रमाक	श्रेणी	संख्या
1	**2**	**3**
1	मंडल रोजगार कार्यालय, अम्बाला	5925
2	नगर रोजगार कार्यालय पंचकूला	3396
3	मंडल रोजगार कार्यालय, यमुनानगर	4703
4	ग्रामीण रोजगार कार्यालय बराड़ा	643
5	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, छछरौली	847
6	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कालका	1352
7	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, मोरनी	287
8	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, नारायणगढ़	1188
9	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, रायपुररानी	650

10	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, संढ़ौरा	339
11	जिला रोजगार कार्यालय, कुरूक्षेत्र	1487
12	यू0 इ0 बी0, कुरूक्षेत्र	82
13	नगर रोजगार कार्यालय, कैथल	2063
14	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, गुहला	670
15	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, लाडवा	577
16	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पिहोवा	655
17	ग्रामीण रोजगार कार्यालय,पुण्डरी	1078
18	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, रादौर	557
19	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, भााहबाद	1147
20	जिला रोजगार कार्यालय, करनाल	3155
21	जिला रोजगार कार्यालय, पानीपत	3354
22	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, असन्ध	674
23	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, इंन्द्री	684
24	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, घरोण्डा	1629

25	ग्रामीण रोजगार कार्यालय,नीलाखेड़ी	934
26	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, नीसिंग	332
27	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, समालखा	721
28	मंडल रोजगार कार्यालय, रोहतक	2856
29	यू0 इ0 बी0, रोहतक	209
30	नगर रोजगार कार्यालय, बहादुरगढ़	1778
31	नगर रोजगार कार्यालय, झज्जर	1204
32	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, बेरी	678
33	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कलानौर	697
34	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कोसली	402
35	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, महम	994
36	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, मातनहेल	447
37	जिला रोजगार कार्यालय, सोनीपत	2447
38	नगर रोजगार कार्यालय, गन्नौर	2229

39	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, गन्नौर	884
40	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, खरखौदा	669
41	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, राई	424
42	जिला रोजगार कार्यालय, जींद	2866
43	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, जुलाना	609
44	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कलायत	694
45	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पिल्लूखेड़ा	479
46	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, सफीदों	686
47	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, उचाना	698
48	नगर रोजगार कार्यालय, नरवाना	1325
49	मंडल रोजगार कार्यालय, भिवानी	2896
50	नगर रोजगार कार्यालय, चरखी दादरी	2241
51	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, बवानीखेड़ा	922
52	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, लोहारू	495

53	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, सिवानी	678
54	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, तो ाम	566
55	जिला रोजगार कार्यालय, गुड़गांवा	2738
56	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, फिरोजपुर झिरका	381
57	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, नूंह	762
58	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पटौदी	444
59	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, पुनहाना	575
60	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, स	680
61	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, तावडू	540
62	मंडल रोजगार कार्यालय, फरीदाबाद	4255
63	नगर रोजगार कार्यालय, बल्लबगढ़	1005
64	नगर रोजगार कार्यालय, पलवल	1225
65	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, हथीन	768
66	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, होडल	1287

67	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, तिगांव	264
68	जिला रोजगार कार्यालय, नारनौल	1460
69	जिला रोजगार कार्यालय, रिवाड़ी	1771
70	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, बावल	258
71	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, जाटूसाना	606
72	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, महिन्द्रगढ़	1650
73	मंडलरोजगार कार्यालय, हिसार	5168
74	यू0 इ0 बी0 हिसार	136
75	रोजगार कार्यालय, फतेहाबाद	1668
76	नगर रोजगार कार्यालय, हांसी	2421
77	नगर रोजगार कार्यालय, टोहना	947
78	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, आदमपुर	628
79	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, रतिया	497
80	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, उकलाना	615

81	जिला रोजगार कार्यालय, सिरसा	2420
82	नगर रोजगार कार्यालय, डबवाली	1068
83	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, एलनाबाद	520
84	ग्रामीण रोजगार कार्यालय, कालांवाली	322

* आंकड़े जून, 1988 तक

नोटः– पंजीकृत प्रार्थियों बारे सूचना मासिक आधार पर एकत्रित की जाती हैं।

डा0 बृज मोहनः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उन्होनें ग्रेजुएट्स की जो लिस्ट यहां पर दी हैं, उसमें मैडिकल ग्रेजुऐट्स, इन्जीनियरिंग ग्रेजुऐट्स और ला ग्रेजुऐट्स की संख्या मिला कर दी गई हैं या कि अलग–अलग दी गई हैं?

श्री बलवीर सिंहः ग्रेजुऐटस की संख्या मिलाई नहीं है। बल्कि इनकी संख्या अलग–अलग दी गई हैं।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय ने जो आंकड़े दिये हैं, उनमें लगभग 21–21 हजार ग्रेजुएट्स, साढ़ें

पांच हजार पोस्ट ग्रेजुऐट्स, एक हजार मैडिकल ग्रेजुऐट्स, इन्जीनियरिंग ग्रेजुऐट्स और ला ग्रेजुऐट्स सारे मिला कर लगभग 30000 बनते हैं। जब तक इन्हें रोजगार नहीं मिलता तब तक इनको क्या बेरोजगारी भत्ता देने बारे सरकार विचार कर रही हैं?

श्री बलवीर सिंहः यह सैपरेट क्वै चन हैं इसके लिए अलग से नोटिस दें।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जब चुनाव हुए थे तो क्या सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने घोशणा पत्र मे बेरोजगारों को रोजगार देने के बारे में कोई घोशणा की गई थी?

श्री बलवीर सिंहः बेरोजगारों के लिए जो वायदा किया था, वह आते ही इस सरकार ने पूरा कर दिया हैं। इन्टरव्यू के लिए जाते समय या वहां से लौटते समय का किराया सरकार ने मुआफ कर दिया हैं और बेरोजगारो को यह सहुलियत दे दी गई हैं कि जब वे साक्षात्कार के लिए जांए तो उन्हें किराया नहीं देना पड़ेगा।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, क्या बेरोजगार मंत्री महोदय बताएंगे कि जो वायदा आपने किया था वह पूरा कर दिया हैं कि इन्टरव्यू पर आने जाने के लिए किराया नहीं लगेगा, क्या इस सहूलियत को वापिस लेने का तो कोई विचार नहीं हैं?

श्री बलबीर सिंहः जी नहीं, यह सहूलियत वापिस नहीं ले रहे हैं।

श्री रतन लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह नूछना चाहूंगा कि जिन कैटेगरीज के नाम रोजगार कार्यलयों में दर्ज हैं, उनमें से कितने बेरोजगार हरिजन जाति से सम्बन्ध रखते हैं?

श्री बलवीर सिंहः इसके लिये जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं, उनके अनुसार 107283 प्रार्थियों ने हमारे यहां रोजगार प्राप्त करने के लिए नाम दर्ज करवांए हैं इनमें से 190806 अनुसूचति जाति 3465 पिछड़े वर्ग तथ 728 अपंग प्रार्थी हैं।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूंगा कि इन्होनें अभी जो आंकड़े दिये हैं, इस अवधि के दौरान कितने लोंगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया हैं?

श्री बलवीर सिंहः स्पीकर सर, 1–2–88 से 31–7–88 तक 6700 प्रांर्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। इनमें से 1905 अनुसूचित ाति, 601 पिछड़े वर्गो से सम्बन्धित तथा 232 अपंग प्रार्थी हैं जिन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया गया हैं।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया हैं कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं अतः मैं इनसे जानना चाहूंगा कि नौकरियों के लिए आवेदन पत्रों के साथ जो पैसा

पोस्टल आर्डर के रूप में लिया जाता हैं, क्या इस कुप्रथा को बन्द करने के बारे में सरकार विचार कर रही हैं?

श्री बलवीर सिंहः यह मांग विचारधीन हैं।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, जो लेगा हरियाणा में कहीं इन्टरव्यू देने के लिए आते हैं, वे बसों में फ्री आते जाते हैं। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो लोग दिल्ली इन्टरव्यू देने के लिए आते हैं, क्या उन्हेकं भी बसों में फ्री आने जाने की सुविधा देने पर विचार किया जायेगा।

श्री बलबीर सिंहः जो लोग हरियाणा प्रदे ा में इन्टरव्यू देने के लिए जाते हैं, उन्ही के लिए बसों का किराया माफ किया गया हैं। दूसरों प्रदे ाों में ज5ोन वाले नौजवानों के लिये किराया माफ करने के बारे सरका के विचारधीन कोई बात नहीं हैं।

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों से दर्ज नामो की कुल कितनी तादाद हैं और पांच साल से दस साल तक के नामों की कितनी तादादा हैं? इनमें से अब तक कितने लोगों को रोजगार नहीं दे पाये हैं?

श्री बलवीर सिंहः इस सवाल का मूल प्र न से सम्बन्ध नहीं हैं।

डा0 बृज मोहनः स्पीकर साहब मंत्री महोदय ने जो सूची दी हैं, उसमें 100 चिकित्सा ग्रेजुएट्स बताये हैं जिनके नाम ऐम्पलायमेंट ऐक्सचेजों में दर्ज हैं, जब कि हमारे प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज बिना डाक्टर्ज के खाली पड़े हुए हैं। क्या कारण हैं कि उन्हें प्राइमरी हैल्थ सैन्टरों में लगाया नहीं जाता?

श्री बलवीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का भी मूल प्र न से सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जो निजी क्षेत्र के उद्योग लगे हुए हैं, उनमें भी रोजगार कार्यालयो की मार्फत ही रोजगार लोगों को मिले, इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही हैं?

श्री बलवीर सिंहः स्पीकर साहब, मेरे साथी ने सवाल किया हैं कि रोजगार कार्यालयों के तहत ही नौकरी मिले, वह तो पहले ही मिल रही हैं और आगे भी मिलेगी। लेकिन अपने साथी को यह बताना चाहूंगा कि जिन लोगों के दिल में यह बात हैं कि रोजगार महकमा ही नौकरी देता हैं, बड़ी भारी भूल है।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मंत्री महोदय ने सदन के पटल पर रखी हैं, उसके मुताबिक हर साल लाखों के करीब बेरोजगार सेना बढ़ रही हैं । मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अग तक कुल कितने लोगों के नाम हरियाणा स्टेट रोजगार कार्यलयों में दर्ज हैं?

अध्यक्ष महोदय इन्होनें वायदा किया था कि बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे लेकिन अब यह कह रहे हैं कि दे नहीं पायेगें इसलिए मै यह जानना चाहूंगा कि स बेरोजगारी कन्ट्रोल करने के लिए सरकार के विचारधीन कोई योजना हैं जिससे यह बेरोजगारी कन्ट्रोल की जा सके? मंत्री जी ने बताया था कि इनकी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से पांच छः हजार लोगों को रोजगार मुहैया किया जा ुचुका हैं।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर सर, महेन्द्र प्रताप सिंह जो माननीय सदस्य हैं और कल से कांग्रेस लैजिसलेचर पार्टी के नेता भी बन गये हैं। (ब्यवधान व भाोर) ये यहां पर भाायद दूसरी बारी मैम्बर बन कर आये हैं इसलिये कमे से कम इनको सवला पूछने का तो ज्ञान हो जाना चाहिए कि सवाल कैसे पूछा जाता हैं। जब हम इनको रोकेंगे और कहेंगे कि इंटररैलेवैन्ट हैं, तो कहेंगे कि हम तो 60–65–80 इकट्ठे हो रहे हैं और ये चार हैं, इनको बोलने नहीं देते। इसलिए मैं गुजारि ा करूंगा कि इनको रैलेवैन्ट, ब्रीफ और कंसीड्रेट होना चाहिये ताकि ये आराम से सवाल पूछ सकें और हमें इनको रोकना न पड़े।

Mr. Speaker: No mroe supplementary on this question please.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः मैंने तो अभी सवाल पूरा पूछा ही नहीं हैं। (व्यवधान व भाोर)

Mr. Spaeaker: Mahender Partap ji, please sit down. No more supplementary now.

Allotment of Surplus\Custodian Land

***638. Shri Rattan Lal Kataria:** Will the Minister for Revenue be pleased to state the area os surplus.custodian land allotted to the person area of land out of that for which actual possession was given to the yearwise, separately?

Mr. Speaeker: Extension has benn asked for in respect of the question which has been granted. The Communication received from the Minister concerned reads as under:-

''विधायी कार्य

परम अग्रता/तिथि बद्ध

विशयः– विधान सभा तारांकित प्र न सं0 बाबत अतिरेक/कस्टोडियन भूमि अलाटमैंट, जो श्री रतन लाल कटारिया, एम0 एल0 ए0 द्वारा पूछा गया के बारे में सूचना उपलब्ध करने सम्बन्धी।

हरियाणा विधन सभा तारांकित प्र न सं0 638 जो श्री रतन लाल कटारिया एम0एल0 ए0 द्वारा पूछा किया गया हैं, का उत्तर दिनांक 23 अगस्त 1988 को हरियाणा विधान सभा अधिवे ान में देय है। जहां तक विशय लिखित तारांकित प्र न के अतिरेक भूमि की अलाटमैंट, बारे वांछित उत्तर उपलब्ध किये जाने का सम्बन्ध हैं, इस बारे यह वर्णित हैं कि इस मामले में गत 10

वर्शा की जिलावार सूचना मांगी हैं। जो राज्य मुख्यालय पर उपलब्ध न होने के कारण सभी उपायुक्तों से मंगवाई हैं। इस प्रकार उक्त प्र न का उत्तर तैयार करने में काफी समय लगने की सम्भावना हैं। अतः उनसे अनुरोध हैं कि उक्त प्र न का उत्तर तैयार करने हेतु रूल्ज आफ प्रोसीर एण्ड कण्डक्ट औफ बिजनैस इन दी हरियाणा विधान सभा के नियम 41 के परंतुक (2) के अनुसार कम से कम 15 दिन की बढ़ौतरी दी जाये।

ह0

राजस्व मंत्री हरियाणा

सेवा में

अध्यक्ष,

हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़

अ ाः क्रमांक 2885—ए0 आर0 1—88/8515 चण्डीगढ़ दिनांक 21—8—88

पू0 क्रमांक 2885—ए0 आर0/1—88/26995 चण्डीगढ़ दिनांक 21—8—88

एक प्रति प्रधान सचिव , मुख्य मंत्री हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ प्रेशित हैं।

ह0

राजस्व मंत्री हरियाणा।''

Complaint aganst unauthorsied Constuction

***598. Shri Ranjit Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the total number of complainsts, if any received against the unauthorised construction in District Grugaon, Faridabad , Bhiwani and Panipat in District Karnal during the last two years together with the action taken theron?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): 53. Out of these 28 complainsts have been disposed off. Action in respect of the remaining complaints has been initated.

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा हैं कि अबैध निर्माण की ि ाकायत इन तीनों जिलों में 53 मिली हैं। 28 को तो निपटा दिया गया और भोश जो 35 हैं, वे अभी लम्बित है। उनके बारे में वे ऐक ान इनीि ायेट करेंगे। मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री महोदय ये यह जानना चाहता हूं कि 28 मामले जो आपने निपटाये हैं, उसका ब्यौरा क्या है और बाकी लम्बित है वे क्यो लम्बित हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, यह जो सवाल है, इसके द्वारा भाायद माननीय सदस्य की इन्टै ान पूछने की यह थी कि भाहरों में जो अन–अयोराइज्ड कंस्ट्रक ान हैं, उसके बारे मे यह ब्योरा लेना चाह रहे थे। दरअसल यह सवाल लोकल सैल्फ गवर्नमैंट मंत्री के पास होना चाहिए था। मैंने जो ब्योरा दिया है सैल्फ हुड्डा का दिया हैं क्योंकि सवाल मेरे नाम से डाल दिया गया। हुड्डा में जो ऐक ान लिया जा रहा हैं, वह मैंने बता दिया हैं।

श्री मंगल सैनः ज्वायंट रिस्पौंसिबिलिटी हैं, आप बता दें।

Mr. Speaeker: Therw is of course joint responsibility, but the facts of that department have to be procured.

Shri Magal Sein: Sr, the Hon'ble Minister must have consulted them also.

श्री वीरेन्द्र सिंहः मेरे पास हुड्डा के बारे में जो इन्फर्मे ान है, वह मैंने सदन के सामने रख दी हैं और हुड्डा द्वारा जो ऐक ान लिया जाता हैं, वह डाक्टर साहब को बता देता हूं। हम नोटिस सर्व करते है। कई केसिज में एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज करवाते हैं। नोटिस सर्व करे डिमोलि ान भी हो जाती हैं। इस प्रकार से इनका निपटारा किया जाता हैं। यह जो 53 केसिज मैंने बताये हैं, इनमें से कई में डिमोलि ान भी हो सकती

है, कईयों में एफ0 आई0 आर0 पैंडिग हैं, बाकी में नोटिस दिये गये है।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने यह बताया हैं कि काफी केसिज में हम ने नोटिस दिये है। कई बार लोग स्टे ले आते हैं। क्या गवर्नर इसको रोकने के लिये कोई प्रभावी कदम उठाने जा रही हैं ताकि यह लम्बी ऐक्सरसाईज जल्दी खत्म हो जाये?

श्री वीरेन्द्र सिंहः सर, इसी सत्र में हम एक दो बिल ऐसे ला रहे हैं जो हमारी समझ में कड़े स्टैप्स हैं। सरकार यह उम्मीद करती हैं कि उससे अन–अथोराईज्ड कंस्ट्रक ान रूकेगी।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, वीरेन्द्र सिंह जी ने बताया हैं कि मेरे पास तो हुड्डा का महकमा हैं और यह सवाल विधन सभा सचिवालय ने वैस ही मेरे नाम से डाल दिया हैं। ऐसा कहकर उन्होंने आपके ऊपर ओनस डाला हैं। स्पीकर साहब वे तो इनोसैन्ट है और कुछ जानते नहीं है। उनके लायक दोस्त सम्पत सिंह जी यहां बैठे हैं, अगरवे चाहें तो जवाब दे सकते हैं। हंसी अध्यक्ष महोदय, इन्होनें कहा हैं कि नोटिस जारी किया जाता हैं, एफ0 आई0 आर0 दर्ज की जाती हैं तथा औरकई बाते ंकी जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हुड्डा ने रेजिडैंि ायल सैक्टर्ज बनाए है लोगों को रहने के लिये लेकिन वे कौमि र्ियल सैन्टर बन गए हैं, क्या उनको तोड़ने से पहले एफ0 आर0 लौज कराई गई थी?

फरीदाबाद के अन्दर तो वहां के ऐडमिनिस्ट्रेटर ने मनमाने ढंग से काम किया हैं। भाोर एवं व्यवधान) क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब हुड्डा ने रैजीडैि ायल सैक्टर्ज बनाए तो क्या प्लान करने वालों ने यह विज्यूलाइज किया था कि लोग यहां पर रहेंगें और उनके लिए दुकानें चाहिए? अगर किसी बच्चे को स्कूल जाने के समय रबड़ चाहिए तो रबड़ लेने के लिए क्या टाउनि ाप जाएगा? क्या यह सारी चीजें इन–ब्यू थीं अगर थी तो ऐसी बातें क्यों हुई कि उन जगहों पर कोई मार्किट नहीं हैं और लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए रैजीडैंि ायल हाउसिज खुल गई?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मंगल सैन ने ऐडमिनिस्ट्रेटर फरीदाबाद की चर्चा की। फरीदाबाद कोम्पलैक्स और हुड्डा दो अलग–अलग चीजें हैं।

श्री मंगल सैनः मुझें इसका पता हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, बच्चेकं के बारे में इन्होंनें जो ऐकसपरटाईज हासिल की हैं, उसके लिए मैं इनको मुबारिकबाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा के रैजोडैि ायल सैक्टर में दुकान खोल लेना बिल्कुल गैर कानूनी बात है और अगर कोई खोलेगा तो कानून के तहत उनको डैमोलि ा किया जाएगा। उनको वहां पर दुकान खोलने दी जाएगी। स्पीकर साहब, डा0 मंगल सैन ने कहा हैं कि वहां पर कई गल्त काम हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर उस बारे में काल अटैन् ान मो ान आएगी

या कोई डिस्क ान होगी तो सरकार उसका जवाब देगी और ठोस जवाब देगी और सारी चीजें इसी हाउस में बेनकाब करेंगे।

श्री कुन्दन लाल भाटियाः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया हें कि अनअथोराइज्ड कालोनीज लोगों ने बना ली हैं और लोग मकानों में दुकानें चलाते हैं। स्पीकर साहब, हुड्ड ने अपने औफिस खेले हुए हैं, ट्रेजरी आफिस वहां पर हैं। वे जगह खाली नहीं की गई हैं। आज तक वहां पर दफ्तर की बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। वहां पर स्कूल की बिल्डग पर कब्जा कर रखा हैं और स्कूल की जगह पर थाने खोले हुए हैं क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा हैं।

श्री अध्यक्षः आप भाशण न दीजिए। सवाल पूछिए।

श्री कुन्दन लाला भाटियाः स्पीकर साहब, जो थाने खोले हुए हैं वे स्कूल के अन्दर खोले हुए हैं और अस्पताल भी रहने वाले मकानों में खोले हुए हैं। अगर सरकार ने वहां पर इन संस्थाओं के लिए जगह छोड़ी हुई हैं ता बिल्डिंग क्यों नहीं बनाई गई हैं, और स्कूल, थाने और अस्पताल स्कूल की बिल्डिंग में क्यो खोले हुए है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मुझे तो इनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई हैं।

श्री अध्यक्षः भाटिया जी, आपने कई सवाल जोड़ दिए हैं। आप एक सवाल करिए।

श्री कुन्दल लाल भाटियाः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हुड्डा के आफिस स्कूल की बिल्डिग में क्यों खोले हुए हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह भाटिया जी ने सही फरमाया कि दफ्तर स्कूल की बिल्डिग में खुले हुए हैं। वे इसलिए खुले हुए हैं कि जब सैक्टर बनाए गए तो दफ्तर की बिल्डिग नहीं बनी थी। अब बिल्डिंग बन रही हैं और अब स्कूलन की बिल्डिंग को जल्दी ही वैकेट किया जाएगा।

श्री जगन नाथः स्पीकर साहब, इस सवाल के अन्दर भिवानी जिले का भी थोड़ा बहुत मैन् ान किया गया हैं। कुल 53 केसिज थे जिनमें से 28 का निपटारा हो चुका हैं। भिवानी का एक केस श्री भीम सिंह से संबंधित हैं जोकि बंसीलाल जी के पास आया, श्री बनारसीदास जी के पास भी आया और अब चौधरी देवी लला जी के पास भी आया हैं। एक ही व्यक्ति का वह केस हैं और फाईल यूं ही इधर से उधर घूम रही हैं। अगर उस केस में कोई दोश दिखायी देता हैं तो उसको फाईनेलाइज करके खत्म क्यों नही कर देते? यूं ही फाईल को इधर से उधर घुमाने का क्या लाभ हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यह पता नहीं किस किस की बात कर रहे हैं। इसके लिए तो सैपरेट नोटिस चाहिए।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे लाय मंत्री महोदय ने कहा कि अगर कोई काल अटैन्ान मो ान आयेगा, इस सम्बन्ध में कोई चर्चा होगी तो उसका ठोस जवाब दिया जायेगा और सभी को बेनकाब किया जायेगा। एस बात की मुझें खु ाी होगी कि वे यहां पर सब का पर्दा फा ा करेंगे और बेनकाव करेंगे। मै उनको कहना चाहता हूं कि पीग अखबार ने तो पहले ही सब को बेनकाब कर रखा हैं। क्या मंत्री महोदय इस बारे में जरा स्थिति स्पश्ट करेंगे?

श्री अध्यक्षः डाक्टर साहब, आप इस हाउस के सब से पुराने सदस्य है। आप क्लीयर सवाल पूछिये। यह कोई सवाल नहीं हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर सर, मै आपके माध्यम से मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। गुडगांव के सैक्टर 14 के अन्दर हुड्डा की एक कालोनी हैं। लोगों ने वहां पर प्लाट्स लेकर मकान बनाये हुए हैं और बहुत सारा पैसा भी जमा करवाया हैं लेकिन अब उस कालोनी को गिराया जा रहा हैं। क्या सरकार उनको गिराने की साजि ा कर रहे हैं? भाोर एवं व्यवधान

श्री वीरेन्द्र सिहः I object to this. इस तरह कि साजि ा और फिर यह सरकार करे, यह कहना दुःखदायी बात हैं। (ाोर)

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, जब इन्होनें कहा कि पर्दा फा ा किया जाएगा, तभी मैंने यह पूछा हैं (ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर सर, मैं अब यही कहूगा कि यह झूठा प्रचार हैं और इसको बेनकाब किया जाएगा। पर्दा फा ा किया जाएगा।

श्री मंगल सैनः साजि ा तो सरकार ही कर रही हैं।(ाोर)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, डाक्टर आवे ा में आकर यह बस कुछ कह रहे हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि गुडगांव में सैक्टर 14 की हुड्डा की कालोनी को गिराने का हुड्डा का या सरकार का कोई हुक्म नही हैं। ड़िफैनस् ऐक्ट 1903 के तहत यह भारत सरकार का आदे ा हैं। यू ही आवे ा में आकर डाक्टर सहाब ने ऐसा सवाल पूछ लिया। उन्हें जरा ठण्डे दिल से सवाल पूछना चाहिये थे ताकि हम उनको स्पश्ट स्थिति बताते। सही इंफर्मे ान पब्लिक तक पहुंचनी चाहिये और आप की काई बात ही नही हैं। डाक्टर साहब का हना कि यह सरकार इस तहर की मिली जुली सरकार हैं। अगर डाक्टर साहब को यहां भी सजि ा नजर आ रही हैं तो फिर मैं और क्या कर सकता हू?

श्री क्रांति प्रका ा भल्लाःअध्यक्ष महोदय, पंचकूला के अन्दर बहुत सारी जमीन हुड्डा द्वारा ऐक्वायर की जा रही हैं और उस जमीन पर बहुत से छोटे दुकानदार मजदूर जमींदार बैठे हुए

हैं। क्या सरकार पहले उन लोगों को कहीं और बसाने का प्रबन्ध का विचार रखती हैं ताकि उन लोगों को उजड़ने से बचाया जा सके?

(11:00 बजे)

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, यह सवाल पंचकूला के बारे में तो नही हैं लेकिन मैं इनके पास पंचकुला चला जाऊंगा और जो इनकी तकलीफ होगी उसे दूर करेंगे।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं उपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनाधिकृत निर्माण के बारे में सवाल था और बताया गया कि 53 ि ाकायतों इनकी मिली थी। उनमें से 28 निपटारा कर दिया गया था। यह स्वाभविक और अपेक्षित था कि जो 28 ि ाकायतो का निपटारा किया गया, उसके ारे में सउदन कीो मालूम होता कि क्या निपटारा किया गया लेकिन वह जानकारी यहां नही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों की यह जिम्मेदारी होती हैं कि वे इस बात की निगरानी रखें कि अनाधिकृ त निर्माण न हो, उनके रहते हुए अगर ऐसी ि ाकायतें उनकी ओर से दर्ज नही करायी जाती बल्कि पब्लिक की ओर से की जाती हैं, तो क्या उन अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई हैं या की जा रही हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः ये जो 53 ि ाकायतें मैंने बताई, ये सारी पब्लिक की तरफ से आई। हुड्डा औफिसर्ज के सुआ मोटो ऐक ान पर भी ऐक्ट करता हैं। हमारे पास बहुत कम्पलेंट्स हैं और एफ0 आई0 आर्ज0 मौजूद हैं जिनमे कुछ पर ऐक ान हो चुका हैं और कुछ पर अभी होना हैं। यह जो अनाधिकृत निर्माण की बीमारी फैलती जा रही हैं हम इसको रोकने के लिए इसी सत्र में बड़ा सख्त कानून बना रहे हैं ताकि इस बीमारी को रोका जा सके।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब के साथ आपकी सेवा में रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र ने कहा कि यह बी0 जे0 पी लोकदल की मिली जुली सरकार हैं। उन्होंने मुझे यह याद दिलाया, भाायद मै ंभूल चला था, इसलिए मै ंउनका धन्यवाद करता हूं। मैं इनका आभारी हूं कि ये समय समय पर मुझे याद दिलाते रहते हैं। ठीक हैं जी, उम्र की भी बात हैं और हालात की भी बात हैं। आदमी कई बार भूल जाता हैं। मै अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे मित्र साजि ा भाब्द के अर्थ को समझे। I Still stand by the word conspiracy' क्या यह गवर्नमैंट आफ इंडिया की साजि ा हैं या ब्योरोक्रेसी की साजि ा है? ऐडवरटाईजमैंट करे गुड़गांव में लोगों को प्लाटर दिए गए जिन पर लोगों ने मकान बनाए, अब उनको तोड़ने की बात क्यों की जा रही हैं? अगर यह गवर्नमैंट औफ इंडिया का स्टैप है तो इसको रोकने के लिए स्टेट गवर्नमैंट ने क्या किया हैं?

श्री वीरेन्द्र सिहः स्पीकर साहब, भाुक्र है कि डा0 मंगल सैन हरियाणा से गवर्नमैंट औफ इंडिया की साजि ा पर पहुंच गए बडी मेहरबानी हैं इनकी कि He has correctd him self जहां तक गवर्नमैंट औफ इंडिया का ताल्लुक हैं, 1903 का पुराना डिफैस ऐक्ट हैं। आपको याद होगा, जब मारूति का कारखाना लगने जा रहा था तो मामला पार्लियामैंट में बड़े जोर भाोर से उठाया गया था। बड़ा भारी एतराज किया गया था और इस पर पार्लियामैट में बडी डिबेट हुई थी। हमने भी यही टेक अप किया हैं कि जब मारूति की बिल्डिग बनी थी उस समय विपक्ष ने एक मत होकर कहा था कि यह ऐक्ट की वयाले ान हैं, पडौस में जो डिफैस को इंस्टोले ाज हैं उसके पास यह बिल्डिग बनाना गलत हैं। उस समय गवर्नमैंट आफ इंडिया ने सइ तरफ ध्यान नहीं दिया और अब जबकि वहा पर सैक्टर आबाद हो गया हैं और मकानात बन गए हैं, उनको गिराने से लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हमने कहा हैं कि इस मैअर को टेक अप न किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह ाममला ठीक ढंग से सुलझ जाएगा।

चौधरी महेन्द्र प्रतापः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने एक सवाल के जवाब में बताया हैं कि फरीदाबाद के अन्दरी कुछ दुकानें तोड़ी गई हैं। फरीदाबाद मे जो सैक्टर्ज आबाद हुए हैं, उनके अन्दर सैकड़ो की तादाद मे दुकानें तोड दी गई हैं। यह कानूनो की अवमानना की गई है। सरकार ने जहा पर नागरिको को मकान बनाने के लिए पलाट्स दिए थे, वहां पर ऐग्रीमैंट के

मुताबिक उनको मार्किट ीाी प्रोवाइड की गई थी। लेकिन आज उन मार्किट्स में कोर्ट चल रही हैं और उनमें स्कूलों की जा`बिल्डिंज मुहैय्या की गई थी, उनमें अनेंकों सरकारी दफ्तर चल रहे हैं, कया ययह कानूनों की अवमानना नहीं हैं? इस तरह से वहां पर कानूनों की अवमानना की जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां पर 10–10 साल से जो दुकाने चल रही हैं, उन पर पेनल्टी बगैरह लगा कर क्या सरकार उनो रैगुलर करने के बारे में कोई विचार करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब,महेन्द्र प्रताप सिंह जी ने सवाल पूछा हैं कि वहां पर अदालत क्यों खुली हुई है? मै अपने मानीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वहां पर अदालत बहुत पुराने समय ने खुल हुई हैं और भाायद वह अदालत उस समय की खुली हुई हैं जिस समय मै और महेन्द्र प्रताप जी इस हाउस में नही आए थे। अब हम आहिस्ता–आहिस्ता अदालत की बिल्डिग बाहर बना रहे हैं और काम चालू हैं।

Low Lying areas Flooded by Rains

*626. Shri Lachhman Dass Bajaj: Will the Minister for Revenue be pleased to state whether any area of Karnal or its surrounding has been flooded during the recent rains; if so, the details there of together with the steps, if any, takne or proposed to be taken to dewater the flooded area?

राजस्व मंत्री (श्री सूरज भान): जी हां। हाल ही की बाढत्र से करनाल जिला के 56 गांव प्रभावित हुए। बाढ़ का पानी

काफी मात्रा में उतर गया है और निचले क्षेत्रों में खड़े हये पानी निकालने का कार्य प्रगति पर हैं।

श्री रतन लाल कटारियाः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि करनाल ओर कुरूक्षेत्र जिलों में बाढ़ के कारण कितने व्यक्तियों की मौत हुई हैं? इसके अलावा, मै यह भी जानना चाहूगा कि सारे प्रदे ा के अन्दर कितने किसानों की ट्यूबवैल्ज की खराब मोटरें कुओं से बाहर निकालने पर जहरीली गैस से मौत हुई हैं?

श्री सुरज भानः स्पीकर साहब, यह सवाल तो करनाल जिले के बारे में हैं और सब्जैक्ट पर एक काल अटैं न मो ान भी हैं, उसके जवाब में मैं सारी स्थिति बता दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता देता हूं कि बाढ़ के कारण हरियाणा के अन्दर 15 व्यक्तियों की मौत हुई हैं।

श्री जय सिंह राणाः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि करनाल जिले में जो 56 गांव बाढ़ग्रस्त पाए गए, वे कौन–कौन से गांव हैं? इसके अलावा, मै यह भी जानना चाहूंगा कि जो 56 गांव बाढग्रस्त पाए गए, उन गांवो के लोगों को बाढद्य के दौरान क्या सहायता दी गई और अब सरकार क्या राहत कार्य करने जा रही हैं?

श्री सुरज भानः स्पीकर साहब, उन सभी 56 गांवो की लिस्ट मेरे पास हैं लेकिन इस को पढ़ने में काफी देर लग जाएगी।

यह लिस्ट यदि ये चाहें तो इन्हें दी जा सकती हैं। बहरहाल मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि 28 गांवों की फसले खरबा हुई हैं। सभी 56 गावों की फसलें खराब नहीं हुई हैं। अगर माननीय सदस्य चाहे तो मैं इन 28 गांवों की लिस्ट पढ़ कर सुना देता हूं लेकिन इसमें काफी समय लगेगा। इसलिए अगर मानीय सदस्य चाहे तो मैं इनको लिस्ट सप्लाई कर दूंगा। जहां तक बाढग्रस्त गांवों के लोगों को सहायता देने का ताल्लुक हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा कि लोगो को रहने के लिए सहायता देने का ताल्लुक है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि लोगों को रहने के लिए कही कहीं पर सिरकियां दी गई, आटा भी दिया गया ओर दवाईया भी दी गइग। इसके आलवा और भी काफी चीजों का प्रबंध किया गया और दवाईयों भी दी गई। इसके अलावा, और काफी चीजों का प्रबंध किया गया था। जिन गावों में अभी भी पानी खड़ा हैं और धान और जीरी की फसलें खराब हो गई, उन खेतों में तोरिये की अगली फसल के लिए बीज और खाद सबसिडाइज्ड रेट पर देने का विचार हैं। इसके अलावा, और तरह की उन गावों के किसानों को मदद दी जा सकती हैं।

श्री रणजीत सिंहः स्पीकर साहब, यहां र बताया गया हैं कि फलड् आने की वजह से अधिक नुकसान हमारे यहां पर हुआ हैं। ऐसा नुकसान पहले कभी हमारे प्रदे ा का नहीं हुआ था क्योंकि अब यू0 पी0 की सरकार ने यमुना नदी पर चैक या ठोकरें अधिक बना दी है जिससे यह नुकसान हुआ हैं। इसी वजह से

यमुना का पानी पलबल के एरिया में ओर हरियाणा के दूसरे एरिया में अधिक आ गया हैं। क्या इसकी जानकारी सरकार के नोटिस में है दूसरे, क्या भविश्य में इस प्रकार के पानी को राकेन के लिए कोई कदम उठाये जा रहे है ताकि आईन्दा ऐसा नुकसान हमारा न हो पाए?

श्री सूरज भानः अध्यक्ष महोदय, इन्होनें बिल्कुल ठीक कहा हैं कि ठोकरे बगैरा उत्तर प्रदे ा की सरकार द्वारा अधिक बनाये जोन से यह नुकसान हुआ हैं। सैन्ट्रल सरकार ने कुछ नौमेज तय किए हुए हैं कि कटाव को रोकने के लिए इतने फासले पर ठोकरे बनाई जानी चाहिए और इतनी ऊंचाई और इतनी ऊंचाई तक बनाइ जानी चाहिए। हमारी जानकारी के मुताबिक यू0पी0 सरकार ने नौर्मज से अधिक ही ठोकरे बनाई हुई हैं जिससे हरियाणा का नुकसान हुआ हैं। यह सप्लीमैटरी वैसे तो इस सवाल से संबंधित नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं बता दू कि हमारी कोि ा ा होगी कि भविश्य में नुकसान कम हो। अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब सिंचाई मंत्री जी डिटेल में दे सकते हैं।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): स्पीकर साहब, जमुना रिवर के एक तरफ हम हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदे ा हैं। उत्तर प्रदे ा की सरकार के महकमा ड्रेनेज ने यमुना के किनारे पिछले 9–10 सालों में बहुत मजबूत किए हैं। उन्होंनें अपने ऐरिया में स्टेंड्ज और स्परज बहुत अधिक बनाए हैं। 1977 में पहली बार हमारी सरकार बनी थी तो उस समय ये स्परज और

स्टेड्ज बनाने का काम भ्रारू किया गया था। 1978 से 1980 तक यह काम चला। लेकिन उसके बाद ठप्प हो गया। परन्तु उत्तर प्रदे ा सरकार लगातार यह काम करती रही जिसकी वजह से उन्होनें अपने स्टेड्ज और स्परज बहुत मजबूत बना दिए। स्पीकर साहब, गवर्नमैंट औफ इंडिया की एक यमुना कमेटी बनी हुई हैं। उस कमेटी ने यह डायरेक ान दी हैं कि करनाल से दिल्ली तक यमुना के किनारों पर स्टेड्ज तो बनाये जा सकते हैं लेकिन स्परज काफी लम्बे–चौड़े बनाये जा जा सकते हैं। यमुना कमेटी की डायरेक ान हैं कि यमुना के किनारों पर स्प्र नहीं बनने चाहएि लेकिन उत्तर प्रदे ा सरकार ने ये स्परज बनाये हैं जिसकी वजह से यमुना का वाटर कोर्स चेन्ज हो गया हैं। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस मामले पर सरकार बहुत चिन्तित हैं और हम कोि ा ा करेंगे कि इस समस्या का कोई न कोई हल निकाला जा सके।

श्री महा सिंहः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यमुना नदी के साथ लगते हुए एरिया की जमीन कटी है, यदि कटी हैं तो वह एरिया कितना हैं? दूसरे , क्या उस कट का मुआवजा दिया जायेगा? तीसरे इस कट से जो फसल तबाह हुई हैं, वह कितनी हैं और क्या तबाह हुई फसल का भी मुआवजा दिया जायेगा?

श्री सुरज भानः आप इसके लिए अलग से नोटिस दें।

श्री टेक चन्दः मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हरियाणा में कितना रकबा बाढ़ की वजह से बरबाद हुआ हैं? क्या बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी के लिए स्पै ाल गिरदावरी के आदे ा दिए गए हैं? दूसरे, जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ हैं, उनको मुआवजा कब तक मिल जाएग?

श्री सूरज भानः स्पै ाल गिरदावरी के आदे ा पहले ही दे दिये हैं। कितना नुकसारन हुआ हैं यह तो गिरदावरी होन के बाद ही पता चल पाएगा। अभी तक मुआवजा देने को कोई प्रोवीजर नहीं है, वैसे तारे हम लोगों की मदद अव य कर रहे हैं। 3करोड़ 5 लाख 75 हजार रूपये हरियाणा में इस परपज के लिए दिए हैं। मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट अम्बाला को 5 लाख , जिला कुरूक्षेत्र को 9 लाख, जिला हिसार को 12लाख, जिला सिरसा को 13 लाख रूपये और इसी प्रकार मुख्तालिक जिला में मुख्तलिफ मद, वहां पर हुए नुकसान को देखते हुए, दी गई हैं।

चौधरी सतवीर सिंह कादयानः अध्यक्ष महोदय, अत्याधिक बारि ा के कारण बाढ़ से जो नुकसान हुआ हैं, उसके लिए कम्पनसे ान दिया जा रहा हैं। पानीपत थर्मल प्लांट की दीवार गिर जाने के कारण कालसा और सुताना दो गावों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या इन दोनो गावो के लोगों को राहत देने के लिए कोई पग उठाए जा रहे हैं?

श्री सुरज भानः इन दोनो गावों को भी अन्य बाढ़ग्रस्त गांवों के साथ जोड़ लिया जाएगा।

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, बरसात ज्यादा होने की वजह से काफी फसले खराब हुई हैं। जिला सिरसा में रानियां के आस–पास लगभग 4–5 हजार एकड़ जमीन ऐसी हैं जहां पर 3–3 या 4–4 फी पानी खड़ा हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार किसानों को अगली फसल की बुवाई करवाने के लिए इस पानी को निकालने के लिए विचार कर रही हैं?

श्री सूरज भानः केवल सिरसा जिला ही नही, सारे हरियाणा में जिन क्षेत्रों मे पानी खड़ा हैं, उसको डी–वाटर करने के लिए पम्प सैट वगैरा लगाए जा रहे हैं। हम यह कोि ा ा कर रहे हैं कि किसान कम से कम तोरिये की फसल की बिजाई तो कर ही ले।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हू कि या बाढ़ राहत कार्यो के लिए सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा हैं या नही, यदि लिखा हैं तो क्या केन्द्र से काई सहायता या ए योरैन्स प्राप्त हुई?

श्री सूरज भानः हमने केन्द्रीय सरकार को बाढ़ राहत कार्यो के लिये 20 करोड़ की तदर्थ सहायता प्रदान करने हेतु लिखा हुआ हैं। अभी तक तो काइर्ग सहायता प्राप्त नहीं हुई हैं लेकिन हमें पूरी उम्मीद हैं कि सहायता अव य ही प्राप्त होंगी।

श्री सुरेन्द्र कुमार मदानः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ आई हैं। जिला कुरूक्षेत्र बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ हैं। नुकसान को देखते हुए जिला कुरूक्षेत्र को दूसरे जिलों के मुकाबले मे सहायता कम दी गई है।

श्री अध्यक्षः सब से कम सहायता तो जिला अम्बाला को मिली हैं।

श्री सूरज भानः बाढ़ राहत कार्यो के लिए जिला कुरूक्षेत्र को नौ लाख रूपये दिए गये हैं, जो कम नहीं हैं।

चौधरी कि ान सिंह सागवनाः अध्यक्ष महोदय, यह सवाल वैसे तो करनाल जिला के बारे में हैं लेकिन मामला सारे हरियाणा से सम्बद्ध हैं। पिछले 3–4 दिनों से मूसलाधार वर्शा के कारण जिला सोनीपत और रोहतक के कई गावो में जबरदस्त बाढ़ आ गई हैं। क्या यह बात सरकार के नोटिस में हैं। यदि हैं तो सरकार इन जिलों को काई सहायता दने बारे विचार कर रही हैं?

श्री सूरज भानः वर्शा तो आजकल लगभग सभी जगहों पर खूब हो रही हैं। ज्यों–ज्यों दिक्कतें हमारे नोटिस में आती रहेंगी, हम दूर करने की पूरी कोि ा ा करते रहेंगे।

कामरेड हरपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिन गावो में फ्लड आया हैं, वहां करोड़ो रूपये की फसलें बरबाद हो गई है। किसानों को धान की बुबाई में 900/ रूपये से 1000/ तक प्रति एकड़ खर्चा करना पड़ता हैं दूसरे गांवों मे इस समय चारे की

भारी समस्या हैं और तीसरे, वे खेतीहर मजदूर जिन्हें खेतों में काम मिलना था, उन्हें काम नहीं मिला। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किसानों तथा खेतीहर मजदूरों को काम नहीं मिल रहा उनको राहत देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री सूरज भानः इस बारे में स्पै ाल गिरदावरी करवाई जा रही हैं। गिरदावरी हो जाने के बाद नुकसान का जायजा लिया जा सकेगा। हम कोि ा ा करेंगे कि डिवैल्पमैंट और वैलफेयर के कुछ काम भुरू किये जाए जिससे खेतीहर मजदूरो को काम मिल सके।

श्री रणजीत सिंहः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मंत्री महोदय ने बताया हैं कि स्पै ाल गिरदावरी की जा रही हैं लेकिन लोगों को स्पै ाल मुआवजा देने को कोई प्रावधान नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यदि मुआवजा दिया ही नही जाना है ंतो फिर गिरदावरी क्यों करवा रहे हैं?

श्री सूरज भानः हम स्पै ाल गिरदावरी इसलिए करवा रहे हैं ताकि हमें नुकसान का पता चल सके। नुकसान का पता चलने पर ही उसके अनुसार सहायता दी जाएगी।

Market Committee, Kharkhauda

***635. Shri Mohinder:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state-

(a) whether there is nayu proposal under consideration of the Govrnment to open a sep[arate Market Committtee at Kharkhauda in District Sonipat; and

(b) if so, the time by which the aforesaid Market Committee is likely ot be opened?

कृशि मंत्री (श्री तैयब हुसैन):

(क) नहीं जी।

(ख) प्र न उत्पन्न नहीं होता।

श्री मोहिन्द्रः स्पीकर साहब, मेरे सवाल के जवाब में मंत्री महोदय जी ने कहा हैं। स्पीकर साहब खरखौदा सब–मार्किट कमेटी हैं और यह सोनीपत मार्किट कमेटी के अन्डर आती हैं। वहां पर लाखों रूपया खर्चा हुआ हैं इसलिए मैं आपके जरिए मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सैपरेट मार्किट कमेटी बनाने के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया हैं ताकि हम उसे अनुसार प्रोपोजल बना कर सरकार को भेजें?

श्री तैयब हुसैनः स्पीकर सर, खरखौदा सब–यार्ड में तकरीबन हमने सारी फैसेलिटीज दी हुई हैं। 16 फैसेलिटीज होती हैं, वे सारी दी हुई हैं। यह सब यार्ड सोनपत मार्किट के अटैचड् हैं। खरखौदा की आमदनी कम है इसलिए उसे अलग कर दे तो खर्चा बढ़ जायेगा। अग माननीय सदस्य उस घाटे की कोई व्यवस्था बता दे तो सोच लेंगे।

श्री जगन्नाथः स्पीकर साहब, कई मार्किट कमेटियों में दूसरे जिले के गावों भी होते हैं, जैसे हांसी मार्किट कमेटी में सिवानी वाले इलाके के गावों भी भाामिल हैं। हांसी हिसार जिले की मार्किट कमेटी के गांव को पैसा नहीं देते जिसके कारण उन गांवों को दिक्कत पे ा होती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के विचारधीन हैं कि जिस जिले के गावं हैं, उसी जिले की मार्किट कमेटी के साथ लगायें जायें?

श्री तैयब हुसैनः इसके लिए सैपरेट नोटिस दे दे, पता करके बता देंगे।

House Rent Allowance

***622. Shri Harnam Singh:** Will the Deputy Chief-Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to enhance the limit of House Rent Allowance admissible to avarious categorties of the Haryana Government employees;and

(b) if so, the time by which the decision is likely to be taken?

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

(क) इस समय मकान किराया भत्ते की सीमा को बढ़ाने से संबधित कोई मामला सरकार के विचारधीन नहीं हैं।

(ख) जैसा कि ऊपर भाग (क) में दिया गया है।

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत उप मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चण्डगढ़ पंजाब और हरियाणा में हाउस रैंट कितना–कितना हैं और क्या उसमें अन्तर भी हैं? अगर फर्क हैं तो सरकार उसे खत्म करने के लिए विचार क्यों नही करती?

श्री बनारसी दास गुप्ताः चण्डीगढ़ और पंजाब का मुझे पता नहीं। अगर डाक्टर हरनाम सिंह जी हरियाणा का पूछना चाहते हैं तो मै बता सकता हूं।

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, अभी उप मुख्य मंत्री महोदय ने फरमाया हैं कि मकान किराया भत्ते की सीमा को बढ़ाने से सम्बन्धित कोई मामला सरकार के विचारधीन नहीं हैं। मैं आपके द्वारा उप मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी की हाउस रैंट के अलावा कोई और भी मांग हैं?

श्री बनारसी दास गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, सवाल किराये भत्ते के बारे में इसलिए और बातों का मूल प्र न से कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत उप मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हरियाणा अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को चण्डीगढ़ मे जो मकान किराया भत्ता दे रही हैं, क्या उस दर से सिर ढकने को यहां पर किराए

पर जगह मिल सकती हैं? अगर नहीं मिल सकती तो फिर इसको बढ़ान`पर सरकार विचार क्यों नहीं करती?

श्री बनारसी दास गुप्ताः यह बात ठीक हैं कि चण्डीगढ़ मे मकानो के किराये बहुत हैं और जितना किराया भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाता हैं उसमें मकान नही मिल सकता। हमारी कोि ा ा हैं कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सरकारी आवास उपलब्ध कराये जायें लेकिन फण्डज की कमी होन की वजह से यह सुविधा नहीं दे पाते हैं।

Construction of New Canal Rest House at Sardhana

***618. Shri Ved Singh Malik:** Will the Minister for Irrigation Power be pleased to state-

(a) whether the Government is aware of the fact tha tthe existing building of the Canal Rest House at Village Sardhana of Tehsil Gannaur in district Sonepat is in a dilapidated condirtion; and

(b) if so, time by which a new builidng for the said Rest House is likely to be constructed?

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह):

(क) हा जी, इस विश्राम गृह की हालत सन्तोशजनक नहीं हैं।

(ख) फिलहाल नया भवन बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

श्री वेद सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब आदमी इस विश्राम ग्रह में दब कर मर जायेंगे, क्या तब सरकार विश्राम गृह बनाने के लिये विचार करेगी?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, मै वेद सिंह मलिक जी से यह कहूंगा कि वे उधर जाते ही क्यों हैं? (हंसी)

Arrangements to Save Villages in Faridabad From Floods

***558. Shri Udai Bhan:** Will the Minister for Revenue be pleased tos tate whether it is a fact the villages adjacent toYamuna River in District Faridabad are frequently flooded by the said River; if so, the steps, if any, taken or proposed to be taken to save these villages from the damages causd by such floods in future?

Irrigation and Power Minister (Shri Verender Singh): Yes. For the protection of villages situated along river Yamuna, several protection works have been provided.

श्री उदय भानः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि फरीदाबाद जिले मे कितने स्थानों पर यमुना का कटाव हो रहा हैं या कटाव होने का खतरा हैं और उसको बचाने के लिये क्या उपाय किये गये है?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, फरीदाबाद जिले में जो गांव यमुना के किनारे पर आबाद है, जब भी एक लाख क्यूसिक से अधिक पानी यमुना में आ जाता है, ये गांव अफैक्टिड हो जाते हैं। ये हमे ाा से ही होते रहे हैं। लेकिन 1977 से 1979 तक इन गावों के चारों तरफ चौधरी देवी लाल की सरकार ने रिंग बांध बनवाये थे। अब आबादी में पानी कहीं नहीं जाता। लेकिन जो गांव बिल्कुल ही यमुना के किनारे पर हैं, उनके चारो तरफ पानी जरूर भर जाता हैं। श्री सूरज भान जी जब जवाब दे रहे थे तो मैंन भी तफसील में बताया था कि यू0 पी0 सरकार ने यू0पी0 की साईड पर जो यमुना का तट हैं, उसको बहुत मजबुत कर दिया हैं। हम ऐग्जामिन कर रहे हैं कि उस कोर्स को रोकने के लिये हम क्या स्टैप्स लें?

श्री योगे ा चन्द्र भार्माः स्पीकर साहब, मैं आदरणीय मंत्री जी से कुछ जानना चाहता हूं। प्दिले दिनों में आदरणीय मंत्री श्री पूनिया साहब को अपने खदर के इलाके में जो कम्पलीटली हरियाणा से कटा हुआ हैं, ले गया था।उन दिनों अखबारों में भी इनकी जान को हुए खतरे के बारे में छपा था। उस इलाके के लिये वहां पर हैलीकौप्टर से असै ियल चीजें सप्लाई करने के लिये सरकार ने कुछ सोचा था क्योंकि वहां र मोटर बोट्स के अलावा सप्लाई को काई दूसरा साधन नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री और डी0 सी 0 जो वहा पर दौरा करने के

लिये गये थे, की रिपोर्ट पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, पूनिया जी ही इस बारेक में बता देंगे क्योंकि इनकी जान को ही खतरा हुआ था।

उद्योग मंत्री (डा0 किरपा राम पूनिया): स्पीकर साहब, यह बात दरूस्त हैं कि 13–14 गांव खादर के ऐसे हैं जो जहर लाला और यमुना रिवार के लिक कार्स के बीच में स्थित हैं। वह सारे कट–आफ हैं। जिस दिन मै ंवहा ंपरगया था, उस दिन ये सारे गांव ही कटे पड़े थे। हमने उस दिन कोि ा ा की कि सारे गावों में पहुंच सके। उसके बाद हमने डी0 सी0 को यह हिदायत दी कि वहां पर लोगों की सहायता के लिये किि तयां वगैरा भेज और रा ान सप्लाई किया जाये। आटा, तेल, नमक, चीनी आदि सारी की सारी चीजे भेजने का प्रबन्ध किया जा रहा हैं। उसके बाद हमने मिलिटरी के तकरीबन 8 मोटर बोट्स लेकर उन सब गांवो मे रा ान पहुंचा दिया हैं।

Mr.Speaker: Question Hour is over.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये ताराकित प्र नों के लिखित उत्तर

Supply of Sub-standard Sprinkler Sets to Farmers

***569. Shri Hira Nand Arya:** Will the Minster for Agriculture be pleased to state whether any compaint/represntation regardi9ng the supply of sub standard Sprinkler Sets to the farmers in the State has been received by the Government duing the period from 1st Jaunary, 1998 to date; if so, the action, if any, taken or proposed to be taken thereon?

कृशि मंत्री (तैयब हुसैन): जी हां। इस समय के दौरान इस विशय पर दो पत्र प्राप्त हुए है। पहला पत्र भ्रश्टाचार विरोधी बोर्ड को भेज दिया गया हैं जिसके निश्कर्श प्रतीक्षित हैं तथा आगामी कार्यवाही इसके निश्कर्श की रो ानी मे की जाएगी। 10—8—1988 को प्राप्त हुए दूसरे पत्र में दिए सुझावों तथा टिप्पणीयों का निरीक्षण किया जा रहा हैं। तथा उपयुक्त कार्यवाही कर ली जाएगी।

Loan to Farmers

***573. Shri Vasu Dev Sharma:** Will the Minister of State for Cooperation be pleased to state-

(a) whether the Government isa ware of the fact that the farmers are facing great hadship in getting the loans sanctioned from Land Development Banks in the State;

(b) if so, the steps, if any taken or proposed to tbe taken by the Government to remove the said harship;

(c) whether there is any taken proposal under consdieration of the Government to make payemtn of the loan

sanctioned by the raid Bannksa direct to the farmers instead of to the dealers concerned?

सहकारिता राज्य मंत्री (डा0 रघुबीर सिंह):

(क) कृ ाकों को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंको से ऋण लेने में कोई असुविधा नहीं हो रही हैं।

(ख) उपरोक्त ''क'' को देखते हुए, प्र न पैदा नहीं होता।

(ग) नहीं।

Construction of Patwar Offices

***565. Shri Kailash Chand Sharma:** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) whether any working hous for the patwaries to work in their offices have been specified; if so, the timings so fixed;

(b) the districtwise number of places in the Stae where Patwar-Khanas have not so far been contructed; and

(c) the number of Patwar-Khanas out of these as referred to in part (b) above, likely to be constructed during the year 1988-89?

राजस्व मंत्री (श्री सूरज भान):

(क) जी हां, सभी उपायुक्तों को दिनांक 23–3–88 को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि पटवारी कार्यालय समय के दौरान जो भी सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया गया हो, अपने दफ्तर में रहेगा लेकिन गिरदावरी महीनों को छोड़ कर।

(ख) तथा (ग) विवरण सदन के पटलन पर रखा जाता हैं।

विवरण

राज्य में पटवारखानों जिनकी आव यकता हैं, की संख्या उपलब्ध पटवारखानों की संख्या तथा जिन स्थानों पर पटवारखानों का निर्माण नहीं हुआ हैं, की संख्या सम्बधी विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	जितने पटवारखानों की आव यकता हैं की कुल संख्या	उपलब्ध पटवारखानों की सख्यज्ञ	जिन स्थानों पर पटवार खानों का निर्माण नहीं हुआ की	वर्श 1988–89 के दौरान बनाए जाने वाले जिलावार पटवारखानों की संख्या

				संख्या	
1	2	2	4	5	6
1	अम्बाला	237	38	199	10
2	कुरूक्षेत्र	267	14	171	11
3	करनाल	264	93	137	5
4	सोनीपत	161	24	237	11
5	रोहतक	285	48	427	14
6	हिसार	489	62	268	17
7	सिरसा	328	60	306	3
8	भिवानी	337	31	201	3
9	जीन्द	246	45	147	17
10	गुडगावां	169	22	174	11
11	महेन्द्रगढ़	209	35	115	6
12	फरीदाबाद	144	29		5
	कुल जोड़े	3136	501	2635	113

विभिन्न विशयों का उठाया जाना

कामरेड हरपाल सिंहः स्पीकर साहब, पींग अखबार ने हमारे उप मुख्य मंत्री के ऊपर करप् ान के अरोप लगाए हैं। मैंने इस बारें में एक प्रिविलेज मो ान दिया हैं। यह मामला बहुत गम्भीर हैं इसे वि ोशधिकार समिति को सौंपा जाए और सम्पादक के खिलाफ लिया जाए।

Mr. Speaker: I am considering it. Please sit down.

श्री मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, कल मैंने आपकी सेवा में अन–औथोराइज्ड कालोनीज के बारे में एक ध्यानकर्शण प्रस्ताव दिया था और संसदीय कार्य मंत्री ने कहा हैं कि हम सब को बेनकाब करेंगे। मुझे इस बात की बड़ी खु ाी हैं कि वे बेनकाब करेंगे। मै इस बारे में जानना चाहता हूं कि उस ध्यानकर्शण प्रस्ताव का क्या हुआ?

Mr. Speaker: I have received the reply of the Government just now. I am considering it.

श्री मंगल सैनः मैंने व्यापारियों के बारें मे आज सवेरे ही एक काल अटैन् ान मो ान दी थीं। सरकार ने कच्छों पर, बतिनयानों पर और कम्बलों पर टैक्स बढ़ा दिया हैं। मै जानना चाहता हूं कि मेरी काल अटैन् ान मो ान क्या हुआ?

Mr. Speaker: It has been received in the offices and is being examined.

श्री रतन लाल कटारिया: स्पीकर साहब, मैंने दो काल अटैन्शन मोशन दिए हैं। एक तो जमुना में जयादा पानी आने के कारण हरियाणा प्रदेश की जीन कट गई हैं और दूसरा काल अटैन्शन फ्लड के बारें में हैं। मैं जानता चाहता हूं कि उनका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष: जमुना के बारें मे आपका काल अटैन्शन मोशन गवर्नमैंट को भेज दिया हैं। दूसरे के बारें मे जवाब आ रहा हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: मेरा नाम भी उसमे जोड़ दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आपका नाम उसमें नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि वह गवर्नमैंट को भेज दिया हैं। उसमें पांच एम0 एल0 एज0 के नाम हैं। पांचो को सप्लीमैंटरीज करने की अपरच्युनिटी दूंगा।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह: अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद मे गरीब आदमियों की झुग्गी झौंपड़ियों को उजाड़ दिया गया। इस बारे में मैंने काल अटैन्शन मोशन दिया था। उसका क्या हुआ ?

Mr. Speaker: It is under consideration.

चौधरी महेन्द्र प्रतापः क्या तीन चार दिन में उसका फैसला हो जाएगा?

श्री अध्यक्षः हो जाएगा।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय मुख्य मंत्री जी के टेलीफोन टेप होते हैं। यह आरोप इस सदन में 32 सम्मानीय सदस्यों ने भी सर्वाजनिक रूप से लगाया हैं। इस बारे में मैंने एक काल अटैन् ान मो ान दी थी। उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः कमैन्टस के लिए गवर्नमैंट को भेज दी हैं।

श्री रघु यादवः दूसरा ध्यानकर्शण प्रस्ताव, रिबाड़ी उप–मण्डल में 82–82 साल के बुजुर्गो का नाम पैन् ान लेने वालों की लिस्ट में से काटे जाने के बारें में हैं। मै जानना चाहता हूं कि उसका क्या हुआ?

Mr. Speaker: That is under consideration.

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैंने एक वि ोशाधिकार हनन प्रस्ताव दिया था। भिवानी के राजेन्द्र चौधीरी ने मुझे टेलीफोन पर धमकी दी हैं कि या तो सदन मैं बोलने से चुप हो जाओं वरना तुमको बाहर चुप करा दिया जाएगा। उसने यह भी कहा कि सीता राम जिन्दल की जेब में चूंकि मुख्य मंत्री हैं इसलिए जिन्दल का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसेन कहा हैं कि विधान सभा को हम कुछ नहीं समझतें। उसने मुझे बड़ी भद्दी

गाली भी दी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रिविलेज मो ान का क्या हुआ?

श्री अध्यक्षः मैं आपकी बात समझ गया हूं। That is under consideration.

Shri Mangal Sein: Mr. Speaker, It si a very serious matter if a Capitalist therat3ens. and hon. Member of the House. अध्यक्ष महोदय, किसी का यह कहना कि ''मुख्य मंत्री मेरी जेब में हैं बहुत खराब बात हैं। इस बारे में सख्त ऐक ान होना चाहिए।

Mr. Speaker: That is why I have said that it is being condiered serously.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव

हरियाणा में वर्शा तथा बाढ़ से फसल तथा सम्पति को हुई सम्बन्धी

श्री अध्यक्षः आनरेबल, मैबर्ज, मुझे श्री हीरा नन्द आर्य की आरे से कालिंग अटैन ान मो ान न0 2 और श्री हरनाम सिंह की ओर से कालिंग अटैन ान मो ान नं0 4 (ध्यानाकर्शण संख्या 2 के साथ वैकेटिड) regarding damage to crops and property in Haryana by rains and floods मिले हैं। I admit it. श्री हीरा नन्द आर्य अपना मो ान पढ़ दें और उसके बाद यदि सम्बन्धित मंत्री स्टेटमैंट देना चाहें तो दें दे।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सं0 2

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान एक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हाल ही की वर्शा तथा बाढ़ के परिणामस्वरूप जिला सिरसा, हिसार, कुरूक्षेत्र, फीदाबाद आदि के अनूक गांवो में फसलों और मकानों को क्षति हुई हैं। विभिन्न स्थानों पर जल व धन की क्षति होने से प्रभावित लोगो के लिए जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया हैं। कुछ गांव पीलिया तथा मलेरिया आदि बीमारियों से प्रभावित हुए हैं। इसलिए, सरकार को चाहिए कि प्रभावित लोगों को मुआवजा दे तथा राहत कार्य प्रारम्भ करके अन्य सहायता दे। मेरा यह निवेदन हैं कि संविधित मंत्री इस संबंध में कार्यवाही करने के बाद चालू सत्र के दौरान सदन को सूचित करें। इसके साथ–साथ, मेरा मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है कि वे सइ सदन मे बताएं कि वे इस विशय मे क्या कार्यवाही कर रहे हैं और लोगों को क्या राहत दे रहे हैं ताकि लोगों का जीवन ठीक प्रकार से गुजर सके।

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सं0 4

ध्याानाकर्शण 2 के साथ ब्रैकेटिड

श्री हरनाम सिंहः स्पीकर साहब, मैं इस महान सदन का घ्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जुलाई–अगस्त, 1988 में हुई भारी वर्शा तथा नदियों में

आई बाढ़ से हरियाणा में लाखों एकडत्र फसलों, हजारों मकानों तथा सम्पति की हानि हुई हैं। बाढ़ के बहाव से जमीन का कटाव हुआ हैं। नहरों, सड़को तथा बाढ़ नियन्त्रण के उपाय भी प्रभावित हुए हैं। हजारों नलकूपों के खड्डे तथा मकान गिर गए हैं ता ईजन व मोटरे उनमें दब गई हैं बाढद्य उपाय पूरी तरह असफल हो गए हैं। बाढ़ नियन्ण उपायों की कार्यकु ालता तथा खेती की बहाल तथा लोगों के स्वास्थ्य के लिए तुरंत सहायता देने पर पुनः विचार करने की अत्यन्त आव यकता हैं। यदि आव यक कार्यवाही तुरंत न की गई तो इससे हरियाणा की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य दे।

राजस्व मंत्री (श्री सूरज भान): स्पीकर साहब, मैं कल इनका जवाब दे दूगा।

श्री अध्यक्षः ठीक हैं।

वर्श 1983–84 के लिए अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगो पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः अब वर्श 1983–84 की ऐक्सैस डिमांडज ओवर ग्रांन्टस ऐप्राप्रिऐ ांज पर डिसक ान होगी। हाउस का टाइम सेव करने के लिये आर्डर पेपर पर रखी गयी All the demands for the yuear 1983&84 Will be deemed to have been read and moved. आनरेबल मैम्बर्ज किसी भी डिमांड पर

डिसक ान कर सकते हैं लेकिन डिसक ान स्टार्ट करने से पहले वे उस डिमांड का नम्बर बता दें जिसको वह डिसकस करना चाहते हैं। डिसक ान के बाद डिमांड्ज वोटिंग के लिए फुट की जायेगी।

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 393012** be made to regularise the charges already incurred in ecesss of the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of **2-General Administration.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 4231271** be made to regularise the charges already incurred in ecesss of the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of 4-**Revenue.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs.24824736** be made to regularise the charges already incurred in ecesss of the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of 6-**Finance.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 14004882** be made to regularise the charges already incurred in ecesss of the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of **10-Medical**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 411000** be made to regularise the charges already incurred in ecesss of the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of **13-Socail Welfare& rehabilitation.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs.220493** be made to regularise the charges already incurred in ecesss of the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of **14-Food and Supplies.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 153314203** be made to regularise the charges already incurred in ecesss of the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of **15-Irrigation.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs.2872280** be made to regularise the charges already incurred in ecesss of the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of 17-**Agriculture.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 1341740** be made to regularise the charges already incurred in ecesss of the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of 18-**Animal.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs.7806716** be made to regularise the charges already incurred in ecesss of

the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of 21-**Community Development.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs.10149912** be made to regularise the charges already incurred in ecesss of the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of **23-Transport.**

That a grant of a sum not exceeding **Rs. 669**be made to regularise the charges already incurred in ecesss of the grant voted by the Legislati Assembly ofr the year 1983-84 in respect of **24-Toursim.**

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आपकाा बहुत–बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ऐक्सैस डिमांडज के बारे में बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्षः डा0 साहब, जरा ध्यान रखें कि ये वर्श 1983–84 की ऐक्सैस डिमांडज हैं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, गाईड करने के लिए बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं। ये मेरे बड़े आदरणीय मित्र हैं क्योंकि वे जिन गलिंयो में रहे हैं, मैं भी उन गलियों में घुमा हूं। अब ये आदरणीय उप मुख्य मंत्री हैं। कभी

इन्हें मास्टर जी के नाम से लोग पुकारते थे और अब भी पुकारते हैं।

उप–मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): डा0 साहब, आप किसी नाम से पुकारिये मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं आप भी मास्अर कहलवाने में गर्व महसूस करता हू।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, सब से पहले डिमांड आपकी विधान सभा से सम्बन्धित हैं उस पर तो मैं कमैंट नहीं करूंगा क्योंकि जब से मैं विधान सभा में चुनकर आता रहा कि विधान सभा के किसी भी मसले पर यहां हूं तब से ही यह चलता आ रहा हैं कि विधान सभा के किसी भी मसले पर यहां हाउस में चर्चा नहीं हो कती। केवल इस सम्बन्ध मे एक ही वाक्य कहूगा कि यहां * * * * * । इससे ज्यादा न कहते हुए अपनी बात आगे बढ़ता हूं।

श्री अध्यक्षः ये भाब्द रिकार्ड न किये जायें।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, यू ही गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या लाभ? वही पुरान किस्से पुरानी यादें ताजा करने का क्या फायदा? कहते हैं कि मुख्य मंत्री महोदय बाहर इलाज के लिये गये, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बाहर ईलाज के लिये गये, इसलिये इतना खर्चा उन पर हो गया। पास्ट में जो खर्चा हो चुका हैं उसको हमसे पास करवाना चाहते हैं। वह तो हमें पुरानी परम्पराओं के मुताबिक पास करना ही पड़ेगा। लेकिन हमें भूत

भविश्य और वर्तमान सीभी की और देखना होगा। पास्ट में जो खर्च हो गया, सो हो गया, अब आगे के लिये पैसा खर्च करते समय ध्यान रखना होगा।

स्पीकर साहब, मैं आपको वर्तमान की एक बात बतलाना चाहता हूं। मैं पिछले दिनों फरीदाबाद में गया। वहां का बुरा हाल हैं कुन्दन लाल भाटिया जी के घर के पास गन्दगी के ढेर थे। मैंने इस तरह की हालत देखकर उसी वक्त डी0 सी0 महोदय से टेलीफोन मिलाया कि यहां पर सफाई नहीं हो रही हैं। गन्दगी के ढेर ही ढेर लग रहे हैं। डी0 सी0 महोदय आगे से जवाब देते हैं कि मेरे पास सफाई का महकमा नहीं हैं। मैने कहा कि हमने सिविक्स में यह पढ़ा हैं कि डी0 सी0 ही सारे जिले का हर लिहाज से माकलक होता हैं, इंचार्ज होता हैं। यह सारा काम डी0 सी09 का ही होता हैं कि वह देख ले कि नगर मे सब ठीक प्रकार से चल रहा हैं, सफाई वगैरह का अच्छा प्रबन्ध हैं कि नहीं। डी0 सी0 साहब ने कहा कि यहां के लोकल बौडीज के जो चीफ ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं महाराश्ट्र का रहने वाला हूं। बस दिन काट रहा हूं। मैं गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि इस मामले की और सीरियसली ध्यान दे और इसको टेक अप करें ताकि उस नगर की हाल त को सुधारा जाए। कुछ पैसे का सदृपयोग उस नगर पर कर दें तो बेहतर रहेगा। स्पीकर साहब, क्या यह कोई तरीका हैं सरकार चलाने का? कैसे आदमी को वहां पर यूं ही बैठा रखा हैं जो नगर की सफाई की और लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के सुख

दुख की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा हैं? ऐसे आदमी को वहां से उखाड़ा जाना चाहिये।

श्री बनारसी दास गुप्ताः डाक्टर साहब, यह खर्चा तो 1983–84 का हैं आप कहां से कहां पहुंच गये?

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब ने मुझे गाइड किया था कि यह 1983–84 का खर्चा हैं और मैंने उनका आभार प्रकट किया था। गुप्ता जी लगता हैं उस समय आप हाईकोर्ट की पैटी ान में होगे या भिवानी कोर्ट में होगे। कृपया आप मेरी बात पर ध्यान कीजिए। (विघ्न)

श्री बनारसी दास गुप्ताः डा0 साहब पता नहीं किसी ने कहां पहुंचना हैं (विघ्न)

श्री मंगल सैनः सब ने एक जगह पहुंचना हैं, निगम बोध घाट पर ही जाना हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि उस समय का खर्चा हमारे से रेक्टभ्फाई करवाया जा रहा हैं संविधान में प्रावधान हैं कि अगर ऐक्सैस खर्चा हो जाए तो उसे असैमम्बली में लाना पड़ता हैं। डैमोक्रेसी मे गवर्नमैंट वाई डैलीब्रे ान रन करती हैं और यहां पर चर्चा होनी स्वाभाविक हैं, अतीत4 की भी और वर्तमान की भी। तो मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि इन्होंनें उस समय का हुआ ज्यादा खर्चा मांगा हैं। ठीक हैं उसमैं क्या किया जा सकता हैं? मैं मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा आकर्शित करना चाहता हूं कि इन्होंनें बड़ी कृपा की।

1983–84 में ही एक बड़ी बिल्डिग बना दी। गुप्ता जी और बिल्डिग तो बाद मे बनाए लेकिन पहले रोहतक का पुलिस स्टे ान जरूर बनाव दे। आप कहेंगे कि पुलिस स्टे ान से आपका क्या संबंध हैं? तो स्पीकर साहब, मै ंकहना चाहता हू कि एक डिवैल्पिग कन्ट्री में डिवैल्पमैंट के काम होने चाहिए। चाहे वह सड़को का काम हो, सिंचाई का हो या ि ाक्षा के लिए भवन बनाने कास काम हो। लाएड आर्डर को मजबूत रखने के लिए ला एडं आर्डर मेनटेन करने वाली एजेंसी भी ठीक ढंग से रहे। मेरा यही सुझाव हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि प ाु पालन का महकमा था जो अब भी हैं। मेरे लायक बुजुर्ग दोस्त बैठे हैं। इनके महकमे ने 1983–84 में 9 करोड़ 48 लाख 40 हजार रूपए मंजूर करवाए और उसके बाद भाायद एक बार सप्लीमैंटरी के जरिए भी पैसे लिए। मैं चाहता हूं कि इस महकमें की कोइ जुडि ाियल इन्कवायरी होनी चाहिए। उस समय के जो मंत्री महोदय थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वे हाउस मे मौजूद नहीं हैं। इस महकमे की थौरी प्रोब होनी चाहिए। आदरणीय मुख्य मंत्री जी इस समय बैठे नहीं हैं, उप मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, यह महकमा वाकई स्क्रूटेनाइज करने के काबिल हैं। यहां पर क्या कुछ होता रहा हैं, बड़ी भाका हैं। एंटी पोल्यू ान बोर्ड के चैयरमैन मेरक लायक दोस्त श्री जगपाल सिंह चौधरी जी यहां बैठे हैं वे मेरी बात ताइद करेंगे कि वे कैसे महानुभाव थे। स्पीकर साहब, मद संख्या 23 में देखें। इसमें 10149912 रूपये मांग जा रहे हैं। भाई रघु यादव यहां बैठे हैं, वे मेरी बात को

तस्दीक करेंगे कि उस समय के ट्रांसपोर्ट मंत्री कितने कलाकार मंत्री थे।

श्री अध्यक्षः आप सैकंडर बनाते जांए। (विघ्न)

श्री मंगल सैनः मुझे तो संतोश हैं कि डैमोक्रेसी में ऐसे होनहार नव युवक विधायक होने चाहिए।

स्पीकर साहब, मै जानना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैट का 1983–84 का मामला 1988 में ही क्यों आया हैं इस बारे में गुप्ता जी बताएं? इस डिपार्टमैंट मे वही कर्मचारी हैं, वही अधिकारी हैं। गुप्ता जी यह तो हो सकता हैं कि बदल भी जाएगें और दूसरे आ जाएगे लेकिन ये वहीं के वहीं हैं। स्पीकर साहब, उस समय उनको ख्याल आया कि उन्होनें बैरियर्ज बना दिए और वहां पर स्टाफ लगा दिया। एक दिन मैं रिवाड़ी से बस से आ रहा था तो एक बैरियर पर मैंने पूछा कि यह किस खु ाी में फाटक बनाय हुआ हैं तो मुझे बताया गया कि यह कि यह ड्राइवर्ज और कंडक्टर्ज को चैक करने के लिये बनाया हुआ हैं। स्पीकर साहब ऐसा करके तो फालतू आदमी सर्विस में लगान वाली बात हैं। ऐसा करके यह सोचा गया कि अपने हल्के के आदमियो को राजी करें मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा अन–प्रोडक्टिव अनकाल्ड फार ऐंक्सपैंडरचर हुआ है। इस बारे में ऐसा कोई प्रोवीजर बनाया जाए जिसके तहत जिन लोगों की कलमे से यह काम हुआ हैं, उनको कुछ दण्ड दिया जा सके क्योकि यह उन्होनें

अनाप– ानाप खर्चा कर दिया और भुगतान हम लौगो को पड़ रहा है। इसी तरह से टूरिज्म डिपार्टमैंट मे भी खर्चा किया गया हैं, खैर उसका पैसा तो थोड़ा ही हैं। यह जो ऐक्ससैस खर्चे का सिस्टम हैं और बाद में सप्लीमैंट करने का सिस्टम हैं, यह होना स्वाभाविक हैं क्योंकि यह रियालाइज नहीं कया जा सकता। पिछले दिनों सूखा पड़ा था, अब बाढ़ आ गई ईं वर के काम में किस का हाथ हो सकता हैं, किसी का नही हो सकता। इसका रिलीफ तो देना ही पड़ता हैं। अगले साल का बजट आ जाएगा। उसके बाद कभी हेल्स्टोर्म आ गए कभी बाढ़ आ गई। हमारी सरकार की यह व्यवस्था है ंकि ओलावृश्टि से हुए नुक्सान के लिए किसान की मदद की जाए। इन भाब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोदय, वित्त एवं उप–मुख्य मंत्री महोदय ने वर्श 1983–84 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे जो कुल 219771085 रूपये की हैं, हाउस के सामने पे ा की हैं। इस पैसे को रैगुलेराइज करने के लिए हाउस से मंजूरी ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इनमें कुछ मांगे ऐसी भी हैं, जो कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने के लिए पैसा दिया गया है। किसी को पै न देने की बात है, यह इसी प्रकार का खर्चा हैं। लेकिन कुछेक बातें ऐसी है जिससे साफ जाहिर होता हैं कि उस समय के प्र ाासन की जो दूर–दार्ि ता होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई जिसके कारण्एा यह ऐक्सैस खर्चा हुआ हैं। अगर उस समय के प्र ाासन का ऐस्टिम ठीक होता तो इस पैस का

इतने दिन तक पैडिग होने का सवाल ही पैदा नही होता और इस पैसे को इतने दिनों तक पैडिंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता पैसा सदि रैगुलराइज हो जाता तो आज एक्सैस नही होता। । मैं यह कहना चाहूगा कि जो हो गया, वह हो गया, लेकिन भविश्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे फाइनैस मिनिस्टर श्री बनारसी दास गुप्ता जी बहुत काबिल मिनिस्टर हैं मैं समझता हू कि आयदा ये ऐसा नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मै ंसामान्य प्र ाासन की मांग के बारे मे ंअपने विचार प्रकट करना चाहूंगा कि जोकि डिमांड नम्बर 2 हैं अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त 1983–84 के माध्यम से 8368459 रूपए की रा ि ा मंत्रियो के आयकर की अदायगी और मुख्य मंत्री और खाद्य मंत्री की विदे ा में चिकित्सा करवाने, के अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की अदायगी, वातानूकूलक ओ0 एल0 प्रभारों की अदायगी करने और नए पद बनाने, हरियाणा मण्डप का नवीकरण और विज्ञापन बिलो की अदायगी करने के संबंध में हुए खर्च को पूरा करने के लिए द ार्यी गयी हैं अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं अपनी सरकार से यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार जो जो खर्चा है ंइसयको रोकने के लिये मुख्य रूप से ध्यान देना होगा। आगे के लिए यह ध्यान दनेा होगा कि हमारे स्टेट डिवैलपमैटके काम रूक जाएं। आज के दिन बजट का 42 प्रति ात हिस्सा कर्मचारियों की पे और भत्ते आदि पर ही खर्चा हो रहा हैं। चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को पै ानल का ली देना हैं, उसको मिला कर यह खर्चा 42 प्रति ा4 से बढत्रकर 50 प्रति ात हो जाएगा।

कहने का मतलब यह है ंकि टोटल बजट का आधा पैसा ऐडमिनिस्ट्रे ान पर ही खर्च हा ेजाएगा। इन हालता मे हम अपने प्रान्त की भलाई के लिए क्या कर पांएगे? इतनी भारी बोझ प्रान्त की तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी रूकावट हो सकती हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना हैं कि इतने भारी खर्चे का कम करने के लिए कोई न कोई कदन उठाये जाने चाहिए ताकि हम अपने प्रानत कीकुछ तरक्की कर सके। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूगा कि यू0पी0 हरियाणा से 10–12 गुणा बढ़ा हैं। वहां पर आई0 ए0 एस0 की 216 पोस्टें हैं, यदि में गलती पर नहीं हू तो इसके विपरीत छोटे हरियाणा में 214 पोस्टें आई0 ए0 एस0 की है। इसमें साफ पता चलता हैं कि हमारा सारा पैसा तो ये उच्च अधिकारी ही खा जाएंगे। जब ये लोग ही आधा बजट खा जाएंगे तो फिर हम गरीब लोगों कै लिए, मजदूरों के लिये और अपने किसानों के लिए क्या काम कर पांएगे। स्पीकर साहब, इसी प्रकार दूसरी सर्विसिज का भी यही हाल हैं। इस बारे में मैं चाहूंगा कि हमारही सरकार केन्द्र सरकार को कहे कि आने वाले कुछ सालों के लिए नई आई0 पी0 एस0 की पोस्टें देखने के एि एक ऐडमिनिस्ट्रटिव रिफार्म कमी ान नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि आल इझिउया सर्विसिज की पोस्टों की लिमिट फिक्स करके यहां की पोस्टों को कम कर सकें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि टैक्नोक्रेट अपने विभाग में काम करने का 20–25 साल का अनुभव होता है। जब कोर्ठ फाईल उनके यहां से सचिवालय में आती है तो कलर्क से ऊपर जो असिस्टैन्ट होता हैं, वह इन्जीनियार फाईल को वापस कर देता हैं।

मरे कहने का मतलब यह हैं कि वह आदमी अपने विभाग मे ऐक्सपर्ट हैं लेकिन उसकी प्रपोजल को यहां का असिस्टैन्ट टर्न डाउन करके फाईल को नीचे भेज देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सारे मामले को दुबारा से देखा जाना चाहिए और एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमी ान बनाया जाना चाहिए और इस कमी ान का कोई चेयरमैन बनाया जाये ताकि नए सिरे से प्र ाासन का खर्चा घटाया जा सके और बचे हुए पैस को प्रानत की तरक्की के कामों के लिए यूज कर लिया जाये।

स्पीकर साहब, अब मैं मांग संख्या 13 पर चर्चा करना चाहूंगा। इस मांग के तहत 4 लाख 11 हजार रूपया मांगा गया हैं। जिस तरह से यह पैसा खर्च किया जाता हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इस पैसे से बिलो पावर्टी लाईन के लोगों को लोन व सबसिडी के रू प में सहायता दी जाती हैं और यह सहायता कई ऐजैन्सियों के थ्रू देते हैं। ये एजैन्सियां हैं ग्रामीण एजैन्सी, हरिजन कल्याण निगम पिछडद्ये वर्ग कल्याण निगम और वीकर सैक ान निगम। इन एजैन्सियों में जो लोग लोन सबसिडी के लिए एप्लाई करते हैं, उनमें चालाक किस्म के लोग ऐसे भी हैं जो एक ही आदमी इन चारों जगहों से सबसिडी और लोन ले जाते हैं। लेकिन जो जैनुअन व्यक्ति हैं वे वंचति रह जाते हैं। इस बारें में मैं यम सुझाव दूंगा कि डी0 आर0 डी0 के थ्रू वे चारों एजैन्सियां एक एजैन्सी निर्धारित कर ले जिसके थ्रू ये लोन और सबसिडी दी जाए और जैसे कि मैंने ऊपर कहा हैं, एक ही आदमी जो चारों

एजैन्सियों से लोन और सबसिडी ले लेता हैं, यह बन्द हो जाए। हमारी सरकार का सलोगन हैं ''भ्रश्टाचार बन्द–बिजली पानी का प्रबन्ध''। तो इस भ्रश्टाचार को बन्द करने के लिए इन एजैन्सियों को एक ही जगह से रूटिड किया जाए ताकि जो दलाल टाईप के लोग इसमें इन्वाल्ब हैं, उन पर रोक लगाई जा सके।

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, अब आप वाईन्ड अप करिये।

श्री हीरा नन्द आर्यः स्पीकर साहब, मैं केवल दो मिनट का समय और लूगा। स्पीकर साहब, अगली आइटम मांग संख्या 15 हैं जो सिचाई के विशय में हैं। इस मद में कुछ खर्च लिफ्ट इरिगे ान स्कीम के सिलसिले में दिखाया गया हैं और इसकी रैगुलेराईजे ान के लिए कहा गया हैं। मैं उप मुख्य मंत्री साहब का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाऊंगा कि नहरों में पानी जाये या न जाए लेकिन मिट्टी निकालने के लिए पिछले साल 62 लाख रूपये खर्च किया गया हैं जब कि मिट्टी एक आध जगह से ही निकाली गई हैं। बाकी जो खर्च दिखाया गया हैं वह केवल कागजी ही हैं और बोगस मामले हैं। ऐसे मामलो में भ्रश्टाचार पिछली सरकार के समय में भी होता था और जहां तक मैं समझता हूं वर्तमान सरकार में भी भ्रश्टाचार में कोई कमी नही हुई हैं। वास्तव में पानी के लिये केन्द्रीय सरकार से हमारा संघर्श आज भी जारी हैं। एस0 वाई0 एल0 के पानी के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी । इस नहर के कम्पलीट होने से हरियाणा के रेतीले इलाकों को पानी मिल सकेगा।

श्री अध्यक्षः आर्य साहब, आपका समय हो गया हैं अब आप बैठिए।

श्री हीरा नन्द आर्यः अध्यक्ष महोदय, बस मै ंएक मिनट मे खत्म कर रहा हूं। मै ंइस विशय में खासतौर पर जोर इसलिए दे रहा हूं ताकि सरकार का खजाना जनता का खजाना सही रूप से इस्तेमाल हो। जो दोशी कर्मचारी हैं उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए ताकि बोगस बिल न बन सकें।

मांग संख्या 23 ट्रांसपोर्ट के बारे में हैं। इस बारे में बौडी बिल्डिंग वर्क ाप गुडगांव में बनी वीडियों सैमी डीलैक्स बसों का जिक्र करना चाहूंगा। जब ये बसें सड़क पर चलती हैं तो यह इतनी ज्यादा खड़खड़ करती हैं कि वीडियो और खड़खड की आवाज में मुकाबला सा होता दिखाई देता हैं। बस के खड़के में वीडियो की आवाज तो सुनाई ही नहीं देती। इस बारे में जाचं पड़ताल करवाई जाए कि बसों में घटिया मैटीरियल तो नहीं लगा हैं। इन बौडियो के लिए वर्क ाप में जो चादरें लगाई जाती हैं वे घटिया क्वालिटी की होती हैं और रिकार्ड में जो मैंटीरियल दिखाया जाता हैं वह अच्छी किस्म का दिखाया जाता हैं। इस के इलावा भी बहुत सी और बातें हैं जिनकी जांच–पड़ताल किये जाने की जरूरत हैं। व्यवधान इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की जो बातें हैं उनके बारें में विस्तृत जांच की जाए और दोशियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। इन भाब्दों के साथ

मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रंहण करता हूं। इस समय उपाध्यक्ष पदासीन हुए।

(11:बजे)

श्री महासिंह (राई): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में सन् 1983–84 की ऐक्सैस डिमान्डज ओवर ग्रान्ट्स पर चर्चा हो रही हैं। मैं सब से पहले डिमान्ड नम्बर 10 के बारे में अपने विचार सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। डिमान्ड नम्बर 10 मैडिकल एन्ड पब्लिक हैल्थ के बारे में हैं। इस डिमान्ड के लिए 14004882 रूप्या मांगा गया हैं, जो बहुत थोड़ा हैं। मैडिकल और पब्लिक हैल्थ दोनो ही जरूरी विभाग हैं। देहातों के एरिया मे बेचारे गरीब और मजदूर हैं कि वे दवाई कहीं से ले सकें। आजकल अबरसाम के मौसम में गांवों में मच्छर रात को जिस बेरहमी से काटते हैं वह ब्यान नहीं की जा सकती। बच्चे भी बिलबिलाते हैं और प ाु भी चैन से नही बैठ पाते। यह पैसा बहुत ही कम हैं। जितना धन इस आइटम पर खर्च कर सकें करना चाहिए। इसके साथ–साथ मेरी यह भी गुजारि ा हैं कि आयुवैंर्दिक पद्धति सस्ती और सही हैं इसलिए इस पद्धति से लोगों का ज्यादा भला हो सकता हैं। कम पैस से ज्यादा लोग फायदा उठा सकते हैं। इसी प्रकार से मैं डिमान्ड इरीगे ान के विशय में हैं। इस डिमान्उ के लिए 153314203 रूपया मांगा गया हैं। इस बारे में मैं उप मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा के अन्दर दो महीने पहले भयंकर कहत पड़ा हुआ थ और अब दो महीने से

बहुत ही भयंकर बाढ़ आने के कारण काफी नुकसान हुआ हैं। अगर सरकार इरीगे ान का प्लान ठीक बना ले तो हम बाढत्र और कहत से भी बच सकते हैं। बाढ़ के पानी को इकट्ठा करके इरीगे ान के लिए यूज करें तो हरियाणा को बहुत लाभ हो सकता हैं। अगर इस पानी का प्रबन्ध मुस्तिकल तौर पर हो जाये तो बाढ़ का पानी रूक सकता हैं और जो हमारी सूखी धरती प्यासी हैं उसकी प्यास भी बुझ सकती हैं। इसलिये मैं आपके जरिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस पानी को रोकने के लिए रिजवीयर बनाये जाये और जो बाढ़ का पानी प्रलय करके निकल जाता हैं, उसे इरीगे ान के परपज के लिए चैलन बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता हैं। यह बात हरियाणा सरकार के लिए जरूरी हैं।

अब मैं डिमान्ड नम्बर 17 के विशय में कहना चाहूगा। यह डिमान्उ ऐंग्रीकल्चर के बारे में हैं। इसके लिए 2872280 रूपया खर्चा करना चाहिए था, चाहे किसी दूसरी मांग से धन डाइवर्ट करे खर्च करना पड़े। इस बारे में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जमना रिवर के एरिये में काफी फरटाइल जमीन हैं लेकिन उस जमीन को जमीन के पानी ने बुरी तरह से काट दिया हैं। सारी बैलट की जमीन को काट दिया है और जो वहां पर ट्यूबवैल्ज लगे हुए थे वे भी जमना में चले गये हैं इसलिए इस बारे में सरकार को वि ोश प्रबन्ध करना चाहिए।

डिमान्ड नम्बर 18 ऐनीमल हस्बैन्डरी के बारे में हैं। इस डिमान्ड के लिए 1341740 रूपया रखा गया हैं, यह बहुत कम हैं। ऐनिमल हस्बैन्डरी के बारे में सरकार से एक दरखास्त करना चाहता हूं। हमारी सरकार को क्रौस ब्रीडिंग का प्रोग्राम अपनाना चाहिए। हरियाणा की मुर्रा भैंसे बड़ी अच्छी नस्ल की हैं और हरियाणा की गाय भी बहुत ही म ाहूर हैं। उनकी भी क्रौस ब्रोडिग होनी चाहिए। हमारे हरियाणा का इतिहास हैं कि ''दे ाों में दे ा हरियाणा जहां दूध दही का खाना'' क्रौस ब्रीड के प्रोग्राम से दूध की बढ़ौतरी होगी और बेरोजगार लोगो ंको रोजगार भी मिलेगा। हमारे बच्चों की परवरि ा भी अच्छी हो सकती हैं। बेरोजगार को रोजगार भी मिल सकता हैं। जितने हमारे बैटर्नरी हस्पताल हैं या ए0 आई0 सैन्टर्ज हैं, इनमें अगर फूल प्रूफ तरीका अख्तियार कर लें तो मिल्क आउट पुट बढ़ान मे ंय कारगर सिंद्ध होगा। इन भाब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी) उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सदन के समक्ष अनुदान तथा विनियोजन वर्श 1983–84 के मुताबिक जो मांगे की गयी हैं, उनकी चर्चा हो रही हैं। मैं भी उन पर चच्र करते हुए माननीय उप मुख्य मंत्री एव वित्त मंत्री महोदय का ध्यान मांग क्रमांक 2–सामान्य प्र ाासन की और दिलाना चाहूंगा। इसमें कहा गया हैं कि अनुमान से अधिक खर्चा हो हुआ हैं, वह मुख्य मंत्री और खाद्य एवं पूर्ति मंत्री की विदे ा में चिकित्सा करवान के वास्ते हुआ हैं। यहां अगर यह भी उल्लेखित

होता कि उस समय मुख्य मंत्री और खाद्य एंव पूर्ति मंत्री की यह जो चिकित्सा विदे ा में हुई हैं, यह इस दे ा में सम्भव नहीं थी तो ज्यादा अच्छा होता। क्या उसी परिस्थिति में विदे ा में यह चिकित्सा हुई थी? इसी में आगे कहा गया हैं कि राजभवन में बिजली की तारों को बदलने और वातानुकूलों की तारें लगाने के लिये यह अतिरिक्त खर्चा हुआ हैं। इसी तरह यह भी कहा गया हैं कि राज्यपाल और अन्य अधिकारियों के अधिक दौरे, अति वि ाि श्ट व्यक्तियों यानी वी0 आई0 पीज0 के मनोरंजन पर तथा हरियाणा राज भवन के बिजली तथा पानी प्रभारों के बिलों आदि के कारण अतिरिक्त खर्चा हुआ हैं। मैं अपने उप मुख्य मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि प्र ाासनिक खर्चो में कटौती करके ही विकास का मार्ग खोला जा सकता हैं। पिछले सत्र में भी मैंने यह कहा था कि जो सरकारी वाहन हैं, उनका सरे आम दुरूपयोग हो रहा हैं। 1983–84 में अधिक दौर जो दिखाये गये हैं, यह यही द ार्ाते हैं कि जो वाहनें सरकारी अधिकारयों को दे रखी हैं, उन वाहनो ंका वे सरकार काम के लिये ही नहीं बिल्क निजी काम के के लिये भी दुरूपयोग करते हैं। साहब के बच्चों ने स्कूल में जाना है तो वाहन छोड़ने जाता हैं। साहब की बीवी ने अगर बाजार जाना हैं तो सरकार बाहन में ही जाती हैं। मनोरंजन के लिये सिनेमा जाना हैं तो वहां पर भी यही वाहन जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर आ यर्च होगा कि हिन्दुस्तान में पैट्रोल और डीजल किसी दे ा के मुकाबले सबसे मंहगा मिलता हैं । यह सरकार पैट्रोल और डीजल की कीमत

इसलिये बढ़ाती हैं ताकि इसकी खपत कम हो। लेकिन यह एक तथ्य हैं कि इस दे ा में जितना भी ज्यादा पैट्रोल और डीजल खपत होता हैं, उसका 70 प्रति ात सरकारी वाहनों में खर्च होता हैं। सरकारी वाहनों में पेट्रौल और डिजल का दुरूपयोग होता हैं। उसकी सजा निजी वाहनो के मालिकों को ज्यादा कीमत देकर भुगतनी पड़ती हैं। पिछले सत्र में मैंनक मांग की थी कि सरकारी वाहनों का दुरूपयोग सख्ती से रोका जाये और हमारे वित्त मंत्री जी`न यह आ वासन दिया था कि सरकारी वाहनो के दुरूपयोग को रोकने के लिये हम कड़े उपाय करेगें। मैं अपने उप मुख्य मंत्री महोदय ये यह कहना चाहूंगा कि जब वे जवाब देने क लिय खड़े हो तो यह भी बताये कि इन 5 महीनों के अन्तराल में सरकारी वाहनो के दुरूपयोग को कितना रोक पायें हैं, और कितनों को इस बाबत की सजा दी हैं? इसी तरह से अरिकत स्थानों पर नियुक्ति और उसके वेतन के खर्चे का जहां तक ताल्लुक हैं, मैंने कहा था कि अधिकारियों के घरों पर, चाहे वह पी0 डब्ल्यू डी0 हो , चाहे इरीगे ान हो चा फूड एण्ड सप्लाईज हो, कोई भी महकमा हो, उसके चतुर्थ श्रेणी के जो ऐडहाक पर या दिहाड़ीदार कर्मचारी होते हैं, उनका घरेलू कामों के लिए इस्तमाल किया जाता हैं। उनकी तनख्वाह सरकार के खजाने से दी जाती हैं। इससे ऐस्अिमैट बढ़ जाता हैं और उसको पास करने के लिए सदन के सम्मुख रख दिया जाता हें। माननयी वित्त मंत्री जी ने भ्रश्टाचार से लड़ने का आ वासन दिया था मैं चाहूंगा कि वे बताने की कृपा करें कि इस दुरूपयोग को रोकने के लिये उन्होनें कितने छापे

मारे और कितने अधिकारियों के घर पर काम करते हुए मजदूर कर्मचारी मिले जिन्हें सरकारी मस्टर रोल से तनख्वाह दी जा रही थी?

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य एवं पूर्ति विभाग के बारे में मांग नं0 14 आयी हैं। उस पर जिक्र करते हुए मैं कहूंगा कि अतिरिक्त खर्च के लिये इसमें यह कहा गया हैं कि यह इसलिये हो गया कि वितरण केन्द्र के निरीक्षण हेतु अधिकारियों के अधिक दौरे हुए। नयी पड़ताल चौकियों के लिये दैनिक मजदूरी पर अमले की नियुक्ति के सम्बन्ध में हुए खर्च को पूरा करने के लिये जो खर्चा अनुपूरक अनुमानों दूसरी किस्तों 1983–84 के माध्यम से प्राप्त किया गया था, वह बढ़ गया। साथ ही पी0 ओ0 एल0 वाहनो के अनुरक्षण, यात्रा भत्ते की अदायगी और अन्य आकस्मिक मदों सम्बन्धी खर्च और दिल्ली में सम्पर्क कार्यलय की स्थपना के कारण खर्च बढ़ गया। उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग निरीक्षण के लिए अधिक नाके स्थापित करता हैं और अधिक दौर पे करता हैं। मैं आज फिर इस सदन में कहना चाहता हू कि विविल सप्लाई विभाग कम से कम 1983–84 मे तो करप्ट सप्लाई विीाग था। यहां तो डिस्ट्रीब्यू ान प्वायंट पर हो करप ान भाुरू हो जाता हैं। इसमें दौरास करने की काई जरूरत नही हैं। मै आज सदन से उप–मुख्य मंत्री महोदय के समक्ष और सरकार के समक्ष कह रहा हूं कि आज रिवाड़ी को ले, नारनौल को लें, अम्बाला कैटं को ले लें या भिवानी को ले लीजिए और इन

जगहों पर किसी भी रा ान की दुकान पर चले जाएं, उस रा ान की दुकान का रजिस्टर ले लीजिए और उस रजिस्टर में दर्ज सारे रा ान कार्ड मंगवा लीजिए। डिपो होल्डर के रिजस्टर में रा ान लेने वालों को जो रा ान दिया दिखाया गया हैं वह रा ान कार्डो में दर्जे नहीं मिलेगी।(ाोर एवं व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मसला हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इसलिए खोला गया था कि जन साधारण को सस्ती दरों पर उपभेग की जरूरी चीजें जैसें गेहूं चावल, चीनी मिट्टी का तेल और कपड़ा आदि मिले सके। लेकिन होता यह हैं कि गेहू, चावल चीनी मिट्टी का तेल ओर कपड़ा आदि मिल सके। लेकिन यह होता हैं कि गेहूं चीनी चीनी, मिट्टी का तेल जब रा ान डिपोहोल्डर को दिया जाता हैं तो अधिकारी हर बोरी में से दो किलो चावल निकाल लेते हैं, हर बोरी में से गेहूं निकाल देते हैं। मिट्टी के तेल में पन्द्रह लीटर लेकर रा ान होल्डर को तेल को दिया जाता हैं मेरे कहने का मतलब यह हैं कि भ्रुरू में ही अधिकारी खा जाते हैं तो अधिकारी हर बोरी में से दो किलो चावल निकाल लेते हैं, हर बोरी में से गेंहूं निकाल देते हैं। मिट्टी के तेल में पन्द्रह पैसे प्रति लीटर लेकर रा ान डिपो होल्डर को दिया जाता हैं। मेरा कहने का मतलब यह हैं कि भ्रुरू में ही अधिकारी खा जाते हैं। सारा कुछ आरम्भ में ही जाता हैं। लेकिन कहते हैं कि निरीक्षण करने के प्रति लीटर लेकर रा ान होल्डर को दिया जाता हैं तो अधिकारी मतलब यह हैं कि यह भ्रुरू किया जाता है अध्यक्ष महोदय बेमियानी बात की जा रही हैं। मैंने पिछली बार एक बहुत

गम्भीर मामला करप्ट सप्लाई का उठाया था और पूछा था कि कितने रा ान डिपोज को चैक किया गया? मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज के दौरान एक एक व्यक्ति को चार– चार पांच–पाचं फर्जी नामो से डिपों दे दिये गए। आज हालिजत यह है कि कई डिपो समय पर नहीं खोला जाता।कोई चीज उचित दर पर नह मिलती। पाम,आयम गेहू कपड़ा मिट्टी का तेल और चीनी सारा माल खुल बाजार में बेचा जाता हैं। उपाध्यक्ष्ज्ञ महोदय मैं मिट्टी के तेल के बारे में कहना चाहता हूं। उप मुख्य मंत्री जी, आपके पास तो सरकारी वाहन हैं लेकिन हमारे पास निजी गाडियां हैं। इन गाडियों में यही मिट्टी का तेल पैट्रोल में मिलकर आता हैं। दूसरा कोई तेल नही हैं। यही तेल मिलाया जाता हैं। हम जानना चाहेंगें कि खाद्य आपूर्ति विभाग में पिदले बजट सत्र से लेकर इस मानसून सत्र. के दौरान कितना करप ान कम किया गया हैं कितने रा ान के डिपुओं को चैक किया गया और वितरण प्रणाली को ठीक करनें में कितने सफलता प्राप्त की हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 15 सिंचाई विभाग से सम्बन्धित हैं। इसमें कहा गया हैं कि अतिरिक्त मंहगाई भत्ते कीअदायगी और उठान सिंचाई स्कीमों के सामान्य जल मार्गो के अनुरक्षण के कारण्ध अधिक खर्च हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि जो कैनाल्ज सिस्टम हैं उसको चुस्त दुरूस्त करने के लिए हमें ज्यादा खर्च करना पड़ा हैं। मैं सदन में पूरी गम्भीरता से कह रहा हूं कि जब इरीगे ान डिपार्टमैंट और कैनाल डिपर्टमैंट

में सुरजेवाला मंत्री थे तो उनके समय में रिमुवल आफ सिल्ट अर्थात नहरों में जो मिट्टी जमा हो जाती हैं, उसको निकाले का काम और दूसरे स्ट्रेन्थनिंग औफ बैंक्स अर्थात नहरों के किनारों का मजबूत करना, इन दो कामों की भरमार थी। ये काम हर जिले में और हर क्षेत्र मे होते हैं और इस पर लाखों रूप्या डकारा जाता हैं और काम कुछ नहीं होता। फर्जी और झूठे मस्टर रोल बनाए जाते हैं और एक आदमी द्वारा उस पर अपने हाथ और पैर की उगंलियों के दस दस नि ाान टेक दिए जाते हैं। इस तरह से डिप्टी स्पीकर साहब, झूठे मस्टर रोल्ज से पैसा ले लिया जाता हैं।

Revenue Minister (Shri Suraj Bhan): These are wild allegations unless these are supported by facts.

Shri Raghu Yadav: I had iven a memorandum to the Hon'ble Irrigation & Power Minister during the last session of the Vidhan Sabha. The inquiry is on I am making these allegations very specifically and with full responsibility that on the name of desilting of canals and strengthening of banks, they are making fraud and looting the public money. We must be very watchful and must see that we stop the corruption.

चौधरी बलबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, पिछले काफी अर्से से इन कामों के लिये कोई पैसा नहीं दिया गया हैं न ही कोई पैसा मन्जूर ही किया गया हैं, यह जानकारी सबको हैं। इस तरह की धांधली पहले चलती होगी लेकिन आजकल नहीं चलती वाटर कोर्सिज की मुरम्मत के लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा हैं।

इस तरह की झूठे ऐलिगे ान्ज लगाना और ऐडमिनिस्ट्रे ान को झूठा कहना सरासर गल्त बात हैं।

श्री रघु यादवः उपाध्यक्ष– महोदय मुझे नहीं पता कि चौधरी बलवीर सिंह जो सिचाई मंत्री हैं कि नहीं लेकिन हो सकता हैं 1983–84 में वे रहे हों और कांग्रेस राज्य के दौरान ऐसा हुआ हो। लेकिन सवाल यह हैं कि कांग्रेस राज के दौराना जो खर्चा हुआ हैं,उसका अनुमोदन आज ये हमसे करवाना चाहते हैं। असल बात तो यह हैं कि कांग्रेस राज के दौरान जिन्होनें नहर से मिट्टी निकालने के नाम पर या नहर के किनारों को पक्का करने के नाम पर पैसा खाया हैं, उनको सजा देने का क्या इंतजाम किया गया हैं। हमारी सरकार 15 महीनों से सत्ता में हैं। इन 15 मास के दरमियान भ्रश्टाचार के और अनियमितताओं के कितने केसिज उजागर हुए हैं, कितने केसिज की जांच पड़ताल की गयी है। और भ्रश्टाचार व अनियमितताएं करने वाले कितने अधिकारियों को इस सरकार ने दण्ड दिया हैं मैं तो यह जानना चाहूंग? उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के आरोप मैंने पिछले सत्र में भी लगाये थे, अब भी लगा रहा हूं और सिंचाई एवं बिजली मंत्री जी को इस बारे में एक लिखित ज्ञापन भी दे चुका हूं। मेरा तो केवल यही कहना हैं कि वास्तव में जमीन पर कोई खर्चा नहीं होता और खामखाह जनता के ऊपर इसका बोझा डाला जाता हैं। इस तरह केवल अप–व्यय हो रहा हैं। इसके प चात उपाध्यक्ष्ज्ञ महासेदय, मैं डिमांड नम्बर 23 पर कुछ कहना चाहूंगा । डाक्टर मंगल सैन जी

ने अपने विचार सइ पर पहले ही व्यक्त किये हुए हैं। इसमें कहा गया हैं कि–

''विविध नाका स्थलों पर कर संग्रहण एजेन्सियो के लिये अपेक्षित नये पद बनाने, नाका स्थलों के अमले के लिये फर्नीचर की खरीद करने और 9 प्रति ात से 10 प्रति ात ब्याज दर में वृद्धि के कारण पूंजीगत निवे ा पर अधिक ब्याज की अदायगी करने के लिये प्राप्त की गई थी।''

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली बोर्डर पर ही नाका खड़ा करने का खर्चा हुआ था और वह नाका अतिरिक्त वसूली के लिये नहीं था। उस समय के रोडवेज के मंत्री की कोठी हरियाणा और दिल्ली के बौर्डर पर, कापासेड़ा गांव के पास थी, इसलिये वहा पर नाका खड़ा करवा लिय गया। उस मंत्री ने अपने चहेते स्टाफ की यह ड्यूटी लगा रखी थी कि जो हरियाणा रोडवेज की बस उस मार्ग से हरियाणा में आये और हरियाणा छोड़ कर दिल्ली में प्रवे ा करें, उससे वह 15–20 रूपये के हिसाब से वसूली करे। सवाल यह हैं कि उन्होनें अपनी निजी वसूली के लिये, अपनी आय को बढ़ाने के लिये सरकारी खर्च पर एक नाका खड़ा किया और स्टाफ यूज किया गया। आज हम सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं, पुरारी परम्पराओं के अनुसार हमें इन को पास करना ही पड़ेगा। यह खर्चा तो हो चुका हैं। हमें तो कहना कि इसको मंजूर किया जाए लेकिन उपाध्यक्ष महोदय मैं परिवाहन मंत्री से इतना अव य कहूंगा कि दिल्ली से चण्डीगढ़ या चण्डीगढ़ से दिल्ली, हरियाणा

रोडवेज का सब से महत्वपूर्ण रूट हैं। इस रूट पर कई ए0 सी0 बसें चलती हैं लेकिन उनमे से अधिकां ा का एयर कंडी ानर नहीं चलता। ए0 सी0 बसें हो और उनका एयर कंडी ानर काम न करें, यह बड़ी अजीब सी बात हैं क्योकि ए0 सी0 बसें चारो तरफ से बन्द होती हैं। सरकार यात्रियों से पूरा भाड़ा लेती हैं लेकिन उनको पूरी सहूलियते प्रदान नही करती। बहुत से लोग ऐसी बसों से ट्रैवल करते हैं। हमें भी उन बसों में ट्रैवल करने का अधिकार हैं। अगर ए0 सी0 बसिज में एयर कंडी ानर नही चलेगा तो पब्लिक के लिये ए0सीव बसें चलाना व्यर्थ हैं। इसी तरह से जो वीडियो कोच हैं उनके वीडियो नहीं चलते। अगर वीडियो चलते हैं और फोटो दिखती हैं तो आवाज नहीं सुनाई देती और आवाज सुनाई देती हैं तो फोटो नहीं दिखती। जो सामान्य बसें हैं, जिनमें हरियाणा के कर दाता, जिनके टैक्स पर हम सग लोग, यह सारा विकास का काम और सारे प्र ाासन का खर्चा चलता हैं, जिन बसों में ट्रैबल करते हैं, उन बसों की हालत यह हैं कि सिवाए हार्न के उनमें सब कुछ बजता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, परिवाहन विभाग के लिए जो अतिरिक्त खर्चा मांगा गया हैं, उसको तो हम मन्जूर करते हैं लेकिन यह बात गलत हैं कि हम ऐस्टीमेट तो करते हैं 20 मिनी बसें खरीदने का लेकिन खरीद लेते हैं 60 मिनी बसें। इस वजह से यह सारी गड़बड़ हो जाती हैं। तो हम उतना ही ऐस्टीमेट करें जितनी हमको खरीदनी हैं। इसलिए मै माननीय उप मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि प्र ाासनिक खर्चे को चैक यिा जाए। जैसे वाहनो के दुरूपयोग की बात मैंने कही थी,

कर्मचारियों से घरेलू बेगार लेने की बात कही थी, खाद्य एवं पूर्ति विभाग में डिस्ट्रीब्यू ान के प्वायंट पर ही करप ान की बात कही थी और सिंचाई विभाग में डी– सिल्टिग एंड स्ट्रैन्थनिग आफ बैंकस में बड़े भारी भ्रश्टाचार और घोटाले की बात कही थी, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी उसके बारे में भी सदन को जानकारी देंगें कि उन्होनें इस 15 महीने की सत्ता के कार्यकाल के दौरान उस समय के कितने भ्रश्ट और दोशी अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच की, पकड़ा और सजा दी तथा घर बैठाया। धन्यवाद

श्री कैला ा चन्द भार्मा (नारनौल): उपाध्यक्ष जी, अनुदानों तथा विनियोजन से अधिक मांगे यद्यपि 1983–84 की मांगे हैं फिर भी एक वैधानिक आव यकता को पूरा करने के लिए हमारे सामने ये चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हैं। वर्श 1983–84 में जो अधिक खर्चा हो गया था, वास्तव में इन मांगों के द्वारा हमने उसका अनुमोदन करना है। परन्तु इसकी चर्चा का लाभ यह हो सकता हैं कि जो गलती भूत काल में जिन कारणों से हुई हैं, उस पर हम विचार करे ताकि वर्तमान में जिन मंत्रियो पर यह दायित्व है, जो भूल हो गई हैं, वह कम से कम हमारे काल मे न हो। मुख्य रूप से मैं आदरणीय वित्त मंत्री से कहना चाहूंगा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जानबूझ कर या गगलतती से हो जाती हैं और उस कमी को दूर करने के लिए लोग कोर्ट का सहारा लेते हैं। जैसे अभी ताजा घटना हुई हैं। कुछ प्रिसिपल हमारी सराकर ने परीमोट किए हैं। मुझे पता लगा है ंकि उनमें से 10 प्रिसिपल

ऐसे है जो प्रिसिपल की सीनियोरिटी के हिसाब से बुहत पुराने हैं क्यांकि वे डायरैक्ट प्रिसिपल बने, लेकिन वे 25 साल की सीनियोरिटी पूरी नहीं करते। कल समाचान पत्रों मे ंविस्तार से बात आई थी कि वे कोर्ट में जाएगे और आज जो हमने अनुमान लगा रखा हैं, दो तीन साल के बादे मान लो यदि कोर्ट ने फैसला कर दिया कि नीछे से उनको तनखाह दो, पीछे से बढ़े हुए ग्रेड दो, तो स्वाभाविक रूप से बाद में आने वाले समय में वे मांगे फिर पास करनी पड़ेगी। इसलिए इस प्रकार की गल्तियां न दोहराई जाएं और उन पर विचार किया जाए ताकि भविश्य में जो अनुमान लगाए हैं, वे गलत न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग संख्या 8 पृश्ठ सं0 5 और 6 जो भवन तथा सड़को से संबधित हैं, के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। उस समय भवन तथा सड़को के काम पर 20563 रूपए अधिक खर्च किए गए। मैं समझता हूं कि इस का कारण यह हो सकता हैं कि भवनो ंया सड़को के लिए जो जमीन ऐक्वायर की जाती है उसका ऐस्टिमेट कभी बनता हैं और उसका निर्माण कई साल के बाद होता हैं। ऐसा करने से स्वाभाविक हैं कि आज जिस चीज की जो कीमत हैं वह आने वाले पांच साल के बाद काफी बाद काफी बढ़ जाएगी। इस बारे में मैं अपने हल्के की बात कहना चाहूंगा कि आज से पांच साल पहले एक सड़क बनाने के लिए ऐस्टिमेट बनाया गया था लेकिन आज तक वह सड़के प्रारम्भ नहीं हुई हैं। जिन किसानों की जमीन उस सडत्रक के लिए

ऐक्वायर की गई थी,उनको भी आज तक मुआवजा नहीं मिला है। वे किसान आज भी मआवजे के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कोर्ट ने भी इस बारे में जो डिसीजन देना हैं, स्वाभाविक हैं वह पांच साल के बाद की बढ़ी हुई कीमतों के हिसाब से देगी। इस तरह से सारे काम गलत हो जाते हैं। इस समय हमारे लोक निर्माण मंत्री महोदय हाउस में मौजूद नहीं हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस कसमय हमारी सरकार ने जो काम सड़को को बनाने के लिए या भवनों को बनाने के लिए हाथ में लिया हैं, उसको पूरा करने में गति आनी चाहिए और वह कार्य तुरंत पूरा होना चाहिए। किसी काम को करने में ज्यादा समय लागने से आपत्तियां पैदा हो जाती हैं और काफी दिक्कते पैदा हो जाती हैं तथा हमारे अनुमान से ज्यादा पैसा उन कामों पर खर्च हो जाता हैं।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य श्री रघु यादव जी ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के बारे में काफी विस्तार से बाते सदन में रखी है लेकिन आदरणीय सुशमा जी सदन में उपस्थित नहीं हैं। यह बात बिल्कुल ठीक हैं कि हमारी सरकार के आने के बाद लगभग सभी विभागों में काफी सुधार हुआ हैं, परिवर्तन हुआ हैं और भ्रश्टाचार कम हुआ हैं लोगों ने यह महसूस किया हैं कि इस सरकार के आने के बाद भ्रश्टाचार में कुछ रूकावट पड़ी हैं। लेकिन एक बात कहते हुए मुझे कश्ट हो रहा कि हमारे खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पर अब भी कोई वि ोश असर नहीं पड़ा हैं, उसमें अभी भ्रश्टाचार हैं। यद्यपि आदरणीय

बहन जी ने पिछले सै ान के दौरान काफी आ वासन दिए थे कि हम इस विभाग से भ्रश्टाचार खत्म करने के लिए पूरी पूरी कोि ा ा कर रहे है और करते रहेंगे। मैं कहता हूं कि इस विभाग में कर्मचारियों की एक फौज बनाई हुई हैं। उनके पास जो सामान जाता हैं इस बारे में मै कहना चाहूंगा कि औफिस खुद उनको भ्रश्टाचार सिखाता हैं। जो भी डिपो होल्डर उनके पास सामान लेने के लिए जाते हैं, उनको इंस्पैक्टर्ज कहेंगे कि आप पहले हमारा पांच रूपए बोरी के हिसाब से कमि ान दे कर जाए। डिपो होल्डर की चीनी बिके या न बिके, यह उनकी कोई गारटी नही। डिपो होल्डर इंस्पैक्टर से कहेगा कि साहब चीनी में तो कोई मार्जिन ही नहीं हैं, बहुत कम मार्जिन हैं, इसमें तो हमें कुछ बचता ही नही, खाली बोरी ही बचती हैं, तो इस बात का जवाब तहोता हैं कि चीनी की मंउी में बेच जाओ और मंडी से सल्फर उठा कर ले आओ और कंज्यूमर्ज को सल्फर बेच दी। उपाध्यक्ष्ज्ञ महोदय, वास्तव में होता भी ऐसा ही हैं। गांवो के आदमी अनजान होते हैं, वे चीनी और सल्फर में कोई अन्तर नहीं निकाल सकते। गावों के लोगों को यह पता नहीं होता कि चीनी और सल्फर में क्या डिफरैंस होता हैं। गांवों की आम जनता को चीनी की जगह सल्फर खिलाई जाती हैं। पिछले दिनों हरियाणा में सूखा पड़ा था और प्रदे रूा में गेहूं की कमी थी। उस समय हरियाणा सरकार ने बार बार यह कहा कि आम किसानों को, मजदूरों को जहां पर खेती नहीं हैं यानी फसल नहीं हैं, जहां अनाज पैदा नहीं हुआ हैं, वहां पर गेहूं दी जाए लेकिन गेहूं वहां पर ठीक प्रकार से नही

पहूंची। डिपसे हजोल्डर्ज ने गेहूं वही की वही बेची दी। इंस्पैक्टर्ज ने भी उसमें काफी पेसा कमाया। एक बोरी पर इंस्पैक्टर्ज ने पांच रूपए पंद्रह पैसे का कमि ान रखा हुआ था, जैसे बाटा कम्पनी अपने जूते पर 99 रूपए 95 पैसे रेट लगाती हैं, ठीक उसी प्रकार से इंस्पैक्टर्ज ने तय किया हुआ हैं। एक बारी पर 5 रूप्ए 15 पैसे लेंगे 14 पैसे नहीं लेंगे। इंस्पैक्टर्ज डिपो होल्डर्ज से कहते ह कि तुम्हे कंज्यूमर्ज को गेहूं बेचने की कोई जरूरत नहीं, जाओ किसी मंडी में बेच दो या कही बाहर बेच दो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि कम से कम इस विभाग में जरूर चैकिंग होनी चाहिए। इस बात की जांच भी होनी चाहिए कि उनकी इतनी मामूली तनख्वाह में किसी भी कर्मचारी का गुजारा नहीं चलता? उपाध्यक्ष मजहोदय, यह बहुत ही चिन्ता करने के बावजूद भी इस विभाग में जो सुधार होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है। इसलिए मैं आदरणीय उप मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विभाग की और वि ोश रूप से ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 15 सिचाई विभाग से संबधित हैं। इसके बारे में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। मेरा जिला महेन्द्र गढ़ हैं और उस जिले में इस सरकार की कृपा से पहली दफा नहरी पानी पहुंचा हैं। पहली बार उस जिले के लोगों ने यह अनुभव किया हैं कि नहर के पानी का क्या स्वाद होता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि उस क्षेत्र के अनके पम्प हाउस ऐसे ही पड़े हुए हैं, जिनमें बिजली की मोटरे

अभी तक फिट नहीं की गई हैं और न ही उनके लिए वहां बिजली पहुंची है। इसका परिणाम यह हुआ कि जिन खेतों के अन्दर पानी पहुंच गया हैं और बिजली की मोटरों के अभाव के कारण पप्प हाउस नहीं चल सके हैं, उन किसानों को बहुत पीड़ा हैं। जिन किसानों के खेतों में पानी पहुंच गया हैं लेकिन बिजली की मोटरों के अभाव के कारण पम्प हाउस न चलने से पानी नहीं मिल रहा हैं, उनको इस बात का बहुत भारी दुःख हैं। जब भी चौधरी देवी लाल जी मेरे जिले महेन्द्रगढ़ में गए हैं तो उन लोगों ने बार–बार यही कहा कि आप हमारे पम्प हाउसिज को चालू करवांए ताकि इस पानी का स्वाद हम भी ले सकें। मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस वित्त वर्श में इस काम के लिए, चाहे सरकार को अतिरिक्त पैसा जुटाना पड़े, जुटाया जाए ताकि वहां पर पम्प हाउसिज चल सके। केवल महेन्द्रगढ़ जिला एक ऐसा जिला हैं जो राजस्थान के बोर्डर पर हैं और नहर के टेल पर हैं। वहां पर पम्प हाउसिज बने हुए हैं, और पक्की नहरे बनी हुई हैं लेकिन पम्प हाउसजि चालू करने के लिए पैसे की कुछ अधिक आव यकता हो सकती हैं। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि बरसात के कारण भाहरों की गालियां और सड़के काफी खराब हो गई हैं। लोगों की नजरें सरकार की तरफ लगी हुई हैं कि इनको जल्दी से जल्दी ठीक करा दिया जायेगा। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अगर म्यूनिसिपल कमेटियों को नई सड़कों के लिए पैसा नहीं दिया जा सकता तो पुरानी गालियां या सड़के

टूट चुकी हैं, उनकी मुरम्मत के लिए वि ोश अतिरिक्त अनुदान दिया जाये ताकि बरसात से हए नुकसान को पूरा किया जा सके।

श्री भाग माल (सढ़ौरा–अनुसूचित जाति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 15 और 17 पर एक साथ बोलना चाहता हूं। यह ठीक हैं कि ये डिमांड्ज 1983–84 की हैं। यह बात भी सही हैं कि जाने अनजाने में जो खर्चा बढ़ा वह पूरा कर रहे हैं यानी उसकी इजाजत देनी पड़ रही हैं, लेकिन मैं उनके मायण्यम से वित्त मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि आगे के लिए इस किस्म की कोई व्यवस्था करें ताकि सारे काम ठीक समय पर पूरे हो सके। पिछले साल हमारे यहां पर भी सूखा पड़ा था अब बरसात की वजह से नुकसान हुआ हैं। इन दोनों आपत्तियों से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए हमें बजट की सप्लीमैंटरी डिमांड्ज अलग से लानी पड़ेंगी। उपाध्यक्ष्ज्ञ महोदय, मेरे हल्के की जो समस्याएं हैं, उनके बारे में मै उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूगा। पीछे बरसात ज्यादा हो गई जिससे ड्रैनेज को काफी नुकासान अधिक हुआ हैं क्योंकि मेरा हल्का हिमाचल की पहाड़ियों के साथ लगा हुआ हैं। यहां पर तेज बारि ा आने से जमीन पर कटाव भाुरू हो जाता हैं। इस बार भी अधिक बारि ा होने की वजह ेस जमीन पर कटाव भाुरू हो जाता हैं। इस बार अधिक बारि ा होने की वजह से तीन चार गांव रून, संगरानी, मियापुर राऊमाजरा के लोगों को आदे ा दिए गए हैं कि वे गावों को खाली कर दें क्योंकि कटाव ज्यादा हो रहा हैं। इस कटाव को

रोकने के लिए जब मैं डिपटी कमि नपर से मिला और कहा कि वहां पर आप कोई टैम्परेरी प्रबंध कर दें ताकि लोगों का अधिक नुकसान न हो सके तो डी0 सी0 साहब कहने लगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। मारकण्डा नदी ीाी काफी पुरानी नदी हैं। इस नदी पर एक छोटा सा रसूल गांव बसा हुआ हैं। यह गांव मारकण्डा नदी के कटाव से सिर्फ 100 फीट भी नहीं रह गया हैं। वहां पर लोगों ने अपने पक्के मकान बनाये हुए हैं। वे सब कभी भी गिर सकते हैं। वहां के लोगों ने अपने पकके मकान बनाये हुए हैं। वे सब कभी भी गिर सकते हैं। वहां के लोगों को भी अलटीमेटम दे दिया गया हैं कि गांव को खाली कर जाओ। अगरवहां पर थोड़ा सा पैसा खर्च करके कोई इन्तजाम कर दें तो इसकटाव को रोका जा सकता हैं। पैसा खर्च न होने की वजह से ही नुकसान हो सकता हैं। आज राजस्व मंत्री जी बता रहे थे कि बाढ़ से प्रभावित हुए अम्बाला जिले को 5 लाख रूपये की सहायता दी गई हैं। इतने बड़े जिले के लिए जिसमें काफी पहाड़िया आती हो, 5 लाख रूपये कोई ज्यादा नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय मेरे हल्के में पहाड़ीपुर गांव में एक 66 के0वी0 लाईन का टावर हैं। पानी के बहाव के कारण इस टावर कौ भी खतरा बना हुआ हैं। यदि यह टावर भी पानी की चपेट में आ गया और गिर गया तो मेरे हल्के के लोगों को कम से कम एक महीने के लिए बिजली नहीं मिल पायेगी। इस को बचाने के लिए बिजली और ड्रेनेज महकमे वाले दिन–रात लगे हुए हैं। करीब 100आदमियों कारे इसकी देखभाल के लिए रखा हैं। वहां पर दिन रात काफी ट्रक पत्थर ला कर

डाल रहे है लेकन बरसात की वजह से तेज पानी आ जाता हैं। और सारे पत्थर बह जाते हैं जिसकी वजह से इसके गिरने का भय बना हुआ हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस चालू योजना में वहा पर यानी मारकंडा नदी पर पुल बना दिया जाये तो यह समस्या हल हो सकती है। पानी के बहाव को ध्यान में रखते हुए ही पड़ेल माजरा और मंगत माजरा को खाली कराने का अल्टीमेटस दिया हुआ हैं। मैं अपने उप मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि मेरे इलाके में पानी के बहाव से तोड़–फोड़ ज्यादा होती हैं क्योंकि पानी ठहरता नहीं बल्कि तेजी के साथ बहता है। लोगों की हजारो एकड़ जमीन नदियां से बह गई हैं। हमारा दुर्भाग्य यह हैं कि पहले तो वहां पर बारि ा नहीं हुई और सिचाई के लिए नहरों आदि की कोई व्यवस्था नही हैं और न ही नहर के बारे में सोचा ही जजा सकता हैं।जो ट्यूबवैल्ज लगते हैं वह बहुत ही ज्यादा गहराई पर लगते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले पड़ते हैं। इस समय लोगो ंके पास सिचाई का कोई साधन नहीं हैं। इस इलाके मे सिचाई का सिर्फ एक ही साधन हो सकता हैं ओर वह यह हैं कि इन बरसाती नदियों पर छोटे–छोटे बांध लगा कर पानी रोकना। इस रूके हुए पानी से थोड़ी बहुत सिचाई हो सकती हैं। इन नादियों मं हजारों एकड़ जमीन कटाव के कारण मिट्टी रेत मे बदल चुकी हैं जिस में फसल नहीं हो सकती। सरकार यदि चाहे तो इन छोटे–छोटे नालों पर बांध बनवा सकती हैं जैसे कलका के इलाके में बने हुए हैं। इन बाधों से काफी पानी रोका जा सकता हैं जिससे कुछ सिंचाई हो सकती हैं। सूखे के

दिनों में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं था इसलिए इन छोटे मोटे बाधों से मवे ि ायों के लिए पानी का काम चलाना पड़ा और बाद में इन्हीं से लोगोकं को अपने पीने के लिए भी पानी इस्तेमाल करना पड़ा। इस इलाके में कोई नहर तो नहीं जाएगी क्योंकि इसका कोई जरिया नहीं है, कोई साधन नहीं हैं। इस लिए लोगों को राहत देने के लिए एकमात्र साधन छोटे–छोटे बान्ध बनाना ही हैं। ड्रेनज से सिंचाई करने के लिए छोटे–छोटे बांध बनाए जाने चाहिए ताकि लोग थोडी बहुत सिंचाई कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि आगे के लिए कोई समूचित प्रबन्ध किया जाए ताकि लोगों को कुछ रिलीफ मिल सके।

इसके साथ ही मैं ऐग्रीकल्चर के बारे में कहना चाहूगा। मेरे हलाके में पहले तो सूखा पड़ा, बरसात न होन के कारण लोग फसल नही बो सके और जो फसल मु ि कल से बोई थी, वह नदियौं के तेज बहाव से पानी में बह गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे इस इलाके में कोई ऐसे साधन पैदा किये जाएं जिससे किसानों का जो लाखों रूपये का नुकसान हो गया हैं उसकी पूर्ति हो सके जिन लोगों के पास अगली फसल बोने के लिए पैसा नहीं होगा, उनको मुआवजा दिया जाए। इसके इलावा, हजारों मकान गिर गये हैं, उन बेघर लोगो ंको दोबारा बसाने के लिए तत्काल मुआवजन या कुछ सहायता दी जाए। इन भाब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जगपाल सिंह चौधरी (नारायणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जो डिमांड्ज हाउस में प्रस्तुत की गई हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2–4 मिनट में ही अपनी बात कह दूंगा। मेरी राय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम इरीगे ान हैं। इरीगे ान के क्षेत्र में हमारे जिला अम्बाला की तरफ से अन्य जिलों के मुकाबले में काफी कम ध्यान दिया जा रहा हैं। इस लिहाज से सारा ऐरिया पिछड़ा हुआ हैं। यहां पर छोटी–छोटी नदियां जैसा बेगना, रूण, टांगरी आदि बहती हैं और नीचे जा कर फल्ड का रूप धारण करती हैं और हमारे इलाके में कटाव बहुत ज्यादा करती है। इस साल भी कई आदमी बह गये और मर गये। कई हजार एकड़ जमीन खराब हो गयी। पहले इरीगे ान डिपार्टमैंट की घग्गर डैम बनाने की प्रोपोजल थी लेकिन अब ज्यासपुर में टांरी नदी के ऊपर डैम बनाने का ऐस्टीमेट बना हुआ हैं, उसके ऊपर अधिक से अधिक ध्यान दे कर जल्द से जल्द पैस का प्रवधान किया जाये। इस डैम के बन जाने के बाद नीचे के इलाकों को काफी फायदा होगा और जो हमारा सब–मांउटेनियस एरिया हैं उसको भी काफी फायदा होगा।

एक बात मैं एम0 आई0 टी0 सी0 के बारे में कहना चाहता हूं। एम0 आई टी सी ने बिजली के पैसे भी सरकार को काफी देने हैं। इस कार्पोरे ान के पास पैसे की बहुत कमी हैं और एम0 आई0 टी0 सी0 को ज्यचादा काम कर रही हैं, वह अम्बाला में काम कर रही हैं इसलिए वहां पैसा देना बहुत जरूरी

हैं। एम0 आई0 टी0 सी0 ने अम्बाला जिले में बहुत ज्यादा ट्यूबवैल्ज लगाये हैं, इसलिए वहां जरूर पैसा दिया जाये।

पिछली दफा कहा गया था कि इरीगे ान डिपार्टमैंट की तरफ से हथनी कुण्ड बैराज बनाने की स्कीम हैं। यू0 पी0 और हरियाणा के बीच में हय मामला सैट भी हो गया हैं। इसके लिए एक करोड़ रूपया रखा गया हैं। यह एक करोड़ की बजाए पांच करोड़ किया जाये ताकि सब–माउन्टेनियस एरिया में इरीगे ान के साधन बन सकें क्योंकि एरिया में टूयूबवैल्ज कामयाब नहीं हैं।

एक और भी बहुत जरूरी बात मैं हाउस के सामने रखना चाहती हूं। ऐग्रीकल्चरल डिपार्टमैंट सायल कन्जर्वे ान का काम करता हैं जिसे बट–बन्दी भी कहा जाता हैं। यह बहुत जरूरी हैं, क्योंकि पानी के कटाव के कारण सारे इजलाके की सायल नदियों में बह–बह कर चली जाती हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा नुक्सान होता हैं। इस जमीन के कटाव को रोकने के लिए ऐग्रीकलचर डिपर्टमैंट काम करता हैं। इसलिए सालय कन्जर्वे ान के लिए अधिक फन्डज दिये जाये। इससे जीचे के इलाके को भी फायदा होगा और हमासरे इलाके की जमीन भी खराब नहीं होगी।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के बारे में भी अर्ज करना चाहूंगा। सढौरा, छछरौली और नारायणगढ़ का सब–माउन्टेनियम एरिया हैं जहां पर मिनी बस सर्विस बडी कमायाब हो सकती हैं, इसलिए मिलनी बसें ज्यादा से ज्यादा चलायी जायें। इसी प्रकार सढौरा

मुलाना और नारायणगढ़ एरिया में चूकि कोई भी टूरिस्ट कम्पलैक्स नहीं हैं इसलिए वहां पर टूरिस्ट कम्पलैक्स भी खोला जाये। धन्यवाद।

श्री भगवान सिंह रावत (हथीन): उपाध्यक्ष महोदय, आज फाईनैि यल ईयर 1983–84 के अनुदानों तथा बिनियोजनो से अधिक जो मांगे थी, वैधानिक पूर्ति के लिये वित्त मत्री महोदय ने विधान सभा के सामने रखी हैं। भारतीय संवधिान के अनुच्छेद 205 के तहत स्वीकृत रा ि ा से अधिक धन यदि खर्च हो जाता हैं तो वह नयी स्वीकृत के लिये राज्यपाल मजहोदय, महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट तैयार करने के बाद विधान सभा के सामने रखते हैं और वह हमारे सामने आती हैं। इस वित्तीय वर्श में जो अधिक रा ि ा खर्च हो गयी हैं और जिसे इन मांगो द्वारा सदन की स्वीकृत के लिए रखा गया हैं, उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। लेकिन हमें नि ि चत रूप से इसकी स्थिति में जाना होगा या नहीं या उस फिजुलखर्ची से बच करके अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता था या नहीं इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं विभिन्न मांगो पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। मांग संख्या 10–चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य, में भी अधिक रा ि ा की मांग की गयी हैं। यह सही हैं कि आजादी के 41 साल के बाद जिससे थोड़े से समय को छोड़ कर, हमे ाा कांग्रेस भाइयों के हाथ में सत्ता रही हैं, ग्रामीण और भाहरी क्षेत्रों में आम आदमी को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध

नहीं हैं। जहा ंतक हथीन क्षेत्र का सवाल हैं, जिसका प्रतिनिधित्व मैं करता हूं, वहां पर एक भी बड़ा अस्पताल नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति गांव में बीमार हो जाये तो वहां पर डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। कई कई मील दूर तक असामयकि मौत हो जाती हैं। कभी मलेरिया तो कभी दूसरी बीमारी चलती रहती हैं। मेरा कहने का मतलब यह हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में यह अपर्याप्त चिकित्सा सुविधा रही हैं, इसको दूर करने के लिये अगर कुछ किया जाए तो अच्छा होगा। खर्च की मांग तो हमे ाा बढ़ती रहेगी लेकिन इससे नि चत रूप से सारी जनता को लाभ मिल पायेगा। इसकी हमें व्यवस्था करनी होगी। आज उदाहरण के रूप में मैं एक बात आपके सामने रखूंगा। स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों के समय से आज तक इस 8–10 हजार की आबादी के गांव औरंगाबाद में, जहां पहले कम्युनिटी हैल्थ सैंटर होता था और बाद में डिवैल्प करके पी0 एच0 सी0 बना दिया गया, उसकी बिल्डिग जीर्ण सीर्ण अवस्था में हैं। मरीज तो क्या, वहां पर प ाु भी नहीं बैठ सकते। उसको कभी किसी जगह ि ाफ्ट कर दिया जाता हैं तो कभी कहीं आज तक भी वह जीर्ण भीर्ण अवस्था में ही हैं। बार बार कोि ा ा करने के बाद भी, हरियाणा बनने के बाद से आज तक वहां पर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं हैं। दूसरा उदाहरण मैं हथीन क्षेत्र के साथ लगते हुए एक गांव का देना चाहता हू जहां पर एक प्राइमरी हैल्थ सैटर स्वीकृत हो चुका हैं लेकिन अब तक उसकी बिल्डिग कील कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। डाक्टर भी चौपाल में बैठते हैं। आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र मे जहा डाक्टरों के बैठने

की व्यवस्था न हो, वहां परी कैसी हालत होती हैं? मै ंनि चत रूप से यह कहूा कि इन मांगों को स्वीकृत करने को साथ साथ हमें भीयह स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करवायी जायेगी। एक मांग संख्या 13 हैं जो समाज कल्याण तथा पुनर्वास के लिये अधिक रा ि ा की हैं। हमे इस बात की खु ाी हैं कि चौधरी देवी लाल के नेतृत्व मेंसरकार आर्थिक दृश्टि से कमजोर वर्गो, हरिजनो पिछडी जातियों तथा दूसरे पिछड़े वर्गो के उत्थान के लिए प्रयत्न ाील है। अगर इसके लिये और ज्यादा रा ि ा दे दें तो हमे कोई ि ाकायत नहीं होगी। लेकिन मैं इसके साथ ही एक निजी सुझाव देना चाहूंगा। 41 साल के बाद मेरा अपना अनुभव है कि जातिगत आधार के अलावा आर्थिक वर्ग से या जति से सम्बन्ध क्यों न हो, अगर वह व्यक्ति या परिवार आर्थिक दृश्टि से कमजोर हैं, तो उसको नि चत रूप से सहायता देने की जरूरत हैं, चाहे वह ब्रह्मण हैं या चाहे किसी दूसरी जाति से सम्बन्ध रखता हैं। कोई भी भाई आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो , उसको सहायता दी जाये। इस 41 साल के अर्से में बजट बनते रहे हैं, पैसे खर्च होते रहे हैं, टैक्सिज सब के ऊपर समान लगते रहे हैं लेकिन उसका लाभ आर्थिक दृश्टि से कमजोर वर्ग को नहीं मिल पाया हैं। जहां से यह यात्रा भुरू की गयी थी, आज भी वह वर्ग वही पर खड़े दिखाई देते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकारसे यह अनुरोध करूंगा कि जहा तक कमजोर वर्गो को ऊपर उठाने की बात हैं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसकी

सहायता दी जाये। इसके लिये कोई माप दण्ड बनाकर सहायता दी जाये।

इसके साथ ही मांग संख्या 14 खाद्या तथा पूर्ति विभाग की हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पैदा होने और रहने के बाद मैं यह बात अच्छी तरह से जानता हूं कि खाद्य तथा पूर्ति विभाग किस तरह से लोगों की सुविधा जुटा पाया हैं जो हर सरकार के सामने सिर झुकाते है ंऔर दरबारो की भाोभा बढ़ाते हैं। परम्परागत तरीके से चीनी के लिए डिपो–होल्डर बनते चले आ रहे हैं। वह साठ–गाठ करे हमारे अधिकारियों से मिलकर, मैं तो यहां तक कहूगा कि हमारे प्रतिनिधियों से मिलकर वह लूट बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। आज भी एक ग्रामीण आदमी को, जो 400 ग्राम या 200 ग्राम की नि चत मात्रा को चीनी या आव यकता की दूसरी वस्तुएं जैसे मिट्टी का तेल आदि, आधा महीने तक बांट करे डिपो होल्डर ब्लैकमेलिग करता है। आज हमारे वह अनजान तथा अ ाक्षित भाई हक अनुसार रा ान तथा अपनी आवय यकता की दूसरी चीजें लेने में भी कमायबा नहीं हो पाते। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस जर्जग्र व्यवस्था को पूरी तरह से सुधार करनके गावो और सभी भाहरों में इस व्यवस्था के तहत जितनी भी वस्तूए अथवा सुविधायें हैं, वह उपलब्ध करवायी जाये।

अगली मांग संख्या 15 हैं जो सिंचाई के विशय में हैं। उपाध्यक्ष्ज्ञ महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है

कि आज अकेला हथीन क्षेत्र नही नहीं, इसके साथ लगता हुआ नूह, फिरोजपुर झिरका, आपका पलबल और हसनपुर क्षेत्र हैं जो सिचाई की दृतश्ट से पीछे हैं। हमारा पूरा जिला फरीाबाद और गुड़गावां के अधिकां ज्ञ भागों में सिचाई का एक मात्र साधन आगरा कैनाल हैं। पिछले विधान सभा सै ान में मैंने एक काल अटैं ान मो ानल देकर आपेन आदरणीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री जी कायधन आकर्शित करना चाहा था कि हरियाणा के इस क्षेत्र में नहर का पानी उपलब्ध नहीं होता। आर्थिक दुश्टि से यह क्षेत्र तब तक उन्नति नही कर सकेगा जब तक पानी उपलब्ध नहीं होगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ एक बात आपके द्वारा सरकार के नोटिस में लानी पड़ रही हैं कि इस इलाके में चिाई की दर हरियाणा के दूसरे भागों से ज्यादा हैं। फरीदाबाद और गुडगावा मे और दूसरे भागों मे सिंचाई की दरें दो गुना या तीन गुना अधिक हैं। उदाहरण के रूप मै ंहमे ईख की सिचाई के लिए 98 रूपया प्रति एकड़ देना पड़ता हैं जबकि हरियाणा के हमारे दूसरे किसान भाइयों को 40 या 48 रूपया प्रति एकड़ देना पड़ता हैं। इसी तरह से सभी जिन्सों मैं सिचाई दरों में जो असमानता हैं, इससे हम पर डबल बोझ पड़ता हैं। सारी नरहे उत्तर प्रदे ा सरकार के अन्तर्गत होने के कारण हमारी नहरों में छटाई नहीं हो पाती। वां पर पुल ठीक नहीं बने हुए हैं। मैं समझता हूं कि हमारे नौजवानों को रोजगार भी नहीं मिल पाता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हू3 कि सिुंचाई सुविधा उपलब्ण्ध कराने मैं इन मांगों को ध्यान8 में रखते हुए मेरे इस क्षेत्र का

अधिक ध्यान रखाा जाए। यह जो खर्चे की अधिक रााि हैं, यह ब्याज प्रभारों में वृद्धि, अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की अदायगी और उठान सिंचाई स्कीमों के सामान्य जल मार्गो के अनुरक्षण के कारण हैं। उपाध्यक्ष महोदय उदाहरण के लिए अपने क्षेत्र की मिसाल देना चाहूंगा। उटावड़ डिस्ट्रीब्यूटरी में लिफ्ट स्कीम के तहत पानी डाला जाता हैं लेकिन जब से वह नहर बनी हैं, आज तक टेल पर कभी पानी नहीं गया और उसके ऊपर छः इंच या एक फुट तक मिट्भ और घास जमी पड़ी हैं। उपाध्यक्ष्ज्ञ महोदय, जहां टैक्स और खर्च की बात आती हैं, हरियाणाा के नागरिकों को सामान्य रूप में देना पड़ता हैं लेकिन जहां हमारे हिस्से की बात आती हैं, हम कांग्रेस के चालीस साल के भाासन में उस हिस्से से वचिंत रहे हैं।उपाध्यक्ष महोदय, मै ंआपके द्वारा अनुरोध करूंगा कि इस बात की ओ भी ध्यान दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 17 जो कृशि से सम्बन्धित हैं, इसमे जो रााि मांगी गई हैं, यह प्रोसैसिग सीड प्लांट और हिस्सा पूंजी की अदायगी और उपनिवे ान विीााग द्वारा मण्डियों के लिए भूमि अभिगृहीत करने के कारण हैं। मै आपके माध्यम से दो बाते सदन में रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है ंकि किसानों का जो भी राहत दीह जाती है ंउसके लिए यह सिस्टम, जो परम्परात ढंग से चला आ रहा हैं, दोशपूर्ण है। अगर हमें खद पर सबसिडी दी जाती है तो यह पैसा एक ब्लौक या एक गांव को दे दिया जाता हैं ओर उसमें तथाकथित लोग बा।अक रह जाते हैं। मेरा कहना यह हैं कि यह सुविधा या सबसिडी या छूट जो किसानों को दी जाए, वह

सीधे किसानों को दी जानी चाहिए। जैस कि खाद का कट्टा सिप्लाई किया जाना हैं, उस पर दस रूपया या बीस रूपया हिस्से में आता है जो दिया जाना हैं, वह पहले ह कम करके दिया जाना चाहिए। अगर बीज दिया जाना हैं तो बीज को ही सबसिडाइज्ड रेट पर किसान को दिया जाना चाहिए। फिक्सड अमाउन्ट देकर, कुछ लिमिटेड आदमियों मे वितरित करने से लाभ लोगों को नहीं पहुचता।

इसके अतिरिक्त विकास से सम्बन्धित मांग संख्या 21 हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगा कि विधायक जो चुनकर आते हैं उनको अपने इलाके की समस्याओं को यहां रखने का अवसर मिलता हैं।

जो मुझें दो मिनट अधिक दे दीजिए, आपकी कृपा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह आग्रह हैं कि समुदायों विकास के लिए 1983–84 में और जैसा कि आज भी हुआ हैं, पंचो और सरपंचों का निर्विरोध चुने जाने ओर दूसरे खर्चो पर पुरस्कार देने के कारण यह अधिक खर्च हुआ हैं। लेकिन आज भी मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता हैं कि आजादी के गाद सारा युद्ध ग्रामीण और गरीब जनता के साथ लड़ा गया। जब भी कोई विकास की बात आती हैं तो उसके लिए युद्ध हमारी ग्रामीण जनता, मजदूर, किसान और छोटे दुकानदारों पर लड़ा जाता हैं लेकिन उनके उत्थान के जो परिणाम सामने आते हैं, वे बड़े खेदजनक हैं, उसके लिए हमारे भाई महेन्द्रप्रताप सिंह और उनकी

सरकार जिम्मेदार है। उपाध्यक्ष महोदय, हम जनता से वायदा करके आए हैं कि हमारी सरकार जिम्मेदार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम जनता से वायदा करके आए हैं कि हमारी सरकार, जो चौधरी देवी लाल, के नेतृत्व वाली सरकार हैं और जिसने 1977 मे कुछ विकास कार्य किए थे, वह उनके विकास की तरफ अधिक ध्यान देगी। आज ह यह संकल्प लेकर आए है ंकि पूरी की पूरी जो ग्रामीण और भाहरी गरीब जनता हैं, जो पिछड़ा हुआ तबका हैं, उसके उत्थान के लिए अगर हम काम करेगे तो हमें एक समग्र विकास के लिए काम करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं डिमांड नं0 23 पर अपने विचार रखना चाहता हूं जो कि परिवहन से सम्बन्धित हैं। इसमे कोई दो राय नहीं हैं कि आज हरियाणा परिवहन की प्रं ासा दूसरे राज्यों में होती हैं लेकिन इसके साथ मैं सरकार का ध्यान इस और भी दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं कि एक फस्ट क्लास औफिसर की आय एक छोटे कर्मचारी की निसबत बहुत अधिक होती हैं और एक बस कंडक्टर के पास किसी न किसी तरीक से अपार धन एकत्रित हो जाता हैं। यह सारा धन अन–फेयरमनीज से इकट्ठा किया जाता है। इस ओर सरकार को जरा खास चैक रखने की जरूरत हैं ताकि पब्लिक का पैसा सही जगह पर लग सके। भाहरों में बस सर्विस जो है। वह हर 10–10 मिन्ट के बाद की हैं और गावों मे इस की निस्ब्त आधे आधे घण्टे की सर्विस हैं। अगर गावों मे इस तरह 10–10 या 15–15 मिन्टों की सर्विस

चालू कर दी जाए तो लोगों का काफी सुविधांएण होंगी और सरकार कंडक्टर वगैरह की आमदनी पर, जो अन– फेयर मीनज द्वासरा इकट्ठी की जाती हैं, कोई न कोई चैक लगाए और इस पैसे की गावों में लोगों को ट्रांसपोर्ट की सुविधाए देने में प्रयोग करे।

इससे अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि स्टाफ को जो ओवर टाइम दिया जाता हैं , वह लगभग उसके वेतन से थोड़ा कम होता हैं। लालच मे आकर इम्पालाईज ओवर टाईम लगते हैं और बुरी तरह से बस ड्राइवर्ज वगैरह से ज्यादा काम न लिया जाए, क्योंकि चक्कर वगैरह लगाने से और थकान होने के कारण, नींद का झोंका आ जाता हैं और उससे ऐक्सीडेन्ट हो जाते हैं। इसलिये ओवर टाईम न लगा कर नई भर्ती क जाए ताकि जो बेरोजगान नौजवान, जो नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं उनको रोजगार भी मिल सके। इससे बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी और लोगों की जान माल की भी रक्षा हो पाएगी। ऐसा करने से ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था और बेहतर बन पाएगी। आमदनी भी डबल होगी।

इससे अगली बात मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बहबूदी के बारे में भी कहना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रौं में वाटर सप्लाई स्कीमज पहुचाने का जो प्रबन्ध इस सरकार ने किया, हैं, वह बड़ा ही सराहनीय हैं। लेकिन मैं फिर भी अपने नौजवान साथी श्री रामबिलास भार्मा जी का ध्यान इस ओर दिलाऊगा कि जहां पहले

ग्रामीण क्षेत्रों मैं, वर्शो से महिलाए मीलों मीलों से अपने सिर पर पानी लादकर लाया करती थी, अब सरकार ने उस दिक्कत को गावों में नलके लगवा कर थोड़ा सा दूर तो कर दिया हैं, लेकिन उन लको की संख्यश अभी बहुत कम हैं। 50–50 औरतें एक कए नल पर कई–कई घण्टे पहले इकट्ठी हो जाती हैं जिससे हर रोज झगड़े खड़े होते रहते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार किन्हीं सिलैकटिड गांवों मे लोगो की असुविधाओं के लिये घर–घर में पानी पहुंचाने का प्रबन्ध करे ओर नलकों का प्रबन्ध किया जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार का असुविधा न हो सके। इन भाब्दों के साथ मैं इन डिमांडज करता हुआ अपना स्थान लेता हूं।

श्री मनफूल सिंह (असन्ध अनुसूचित जाति): डिप्टी स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने के लिये टाइम दिया, इसके लिये मै आपकाा धन्यवाद करता हूं। यह जो ऐक्सैस डिमांडज हाउस के सामने रखी गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, मै ंएक दो डिमांडज पर ही कुछ कहना चाहूंगा। सब से पहले मैं सड़को व भवन निर्माण के विभाग से सम्बन्धित अपने विचार रखना चाहूंगा। डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे हल्के असन्ध में कुछक सड़के ऐसी हैं जो अभी तक नहीं बनायी गई, न ही सरकार का उस ओर कोई ध्यान ही गया हैं। पहली सडत्रक बला से पाड़ा तक की हैं ओर तीसरी सड़क जय सिंह पुरी से रंगरूटीखेड़ा तक

की हैं। इनके न बनने से लोगों को आने जाने में काफी असुविधा हो रही हैं। (ाोर)

मुख्य संसदीय सचिव (श्री धीरपाल सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, आन ए प्वायंट औफ आर्डर। यहां पर 1983–84 का जो खर्चा हुआ हैं, उस पर डिस्क ान हो रही हैं। आनरेबल मैम्बर को उसी आधार पर यहां बोलना चाहिए। खाहमखा हाउस का समय बारबाद करने का क्या फायदा?

श्री मनफूल सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, जो पैसा मांगा गया हैं उसी का तो मैं समर्थन कर रहा हूं और साथ मै ंयह रिकवैस्ट भी कर रहा हूं कि जो इस तरह के छोटे छोटे काम रह गये हैं, उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सड़कें स्कूलज और दूसरी जो सरकारी बिलडिंगे हैं, जिनका काम अधूरा पड़ा हुआ हैं, उनकी सरकार जल्दी से पूरा करे। सरकार इस ओर भाीघ्र ध्यान दें, यह मेरी प्रार्थना हैं।

अब मैं मांग नं0 17 पर बोलना चाहता हूं। आज कल बरसात से फसलों का काफी नुकसान हुआ हैं। मैं समझता हूं कि जमुना के किनारे कीसल और जमीन जमुना में चली गई है। सरकार को चाहिए कि उस जमीन के किसानों को डबल मुआवजा दे क्योंकि उनका काफी नुकसान हुआ हैं। मेरे हल्के असंध में बस–अड्डे की काफी दिक्कत आ रही हैं, यह पब्लिक की भलाई का काम हैं इसलिए इस और ध्यान दिया जाए।

श्री धीरपाल सिंहः यह मांग तो 1983–84 के ऐक्सैस खर्च से संबंध रखती हैं जो हो चुका हैं।

श्री मनफूल सिंहः ठीक हैं यह खर्चा तो हो लिया लेकिन आगे भी तो खर्चा करोंगे। आप तो पुराने सदस्य हैं। यह पैसा खर्च हो गया लेकिन गलत कर दिया था। मैं कहता हूं कि आगे के लिए ध्यान रखा जाए। मेरे हल्के की एक छोटी सी सड़क हैं जो रारे से आदाना तक हैं। मेरा निवेदन हैं कि उसको तुरन्त बनाया जाए। इन भाब्दों के साथ मैं इन मांगो का समर्थन करता हूं।

उप मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदय, कल सदन में सन् 1983–84 के जो कुछ अधिक खर्चे हो गए थे, उनकी मांगे स्वीकृत के लिए प्रस्तुत की गई थी। मैं नही समझता था कि इस साधारण सी बात पर इतनी लम्बी चौड़ी बहस होगी। संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार यह आव यक हैं कि जितने पैसे का बजट में प्रोविजन किया जाता हैं, यदि उससे अधिक खर्च हो जाए तो वह सदन के सामने स्वीकृत के लिए प्रस्तुत किया जाता हैं। संविधान की उस विधा को निभाने के लिएसंवैधानिक आव यकता को पूना करने के लिए ये मांगे सदन के सामने प्रस्तुत की गई थी। अभी माननयी सदस्य कह रहे थे कि हमसे यह पैसा अधिक मांगा जा रहा हैं और इस डिमांड में अधिक मांगा गया हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम कोई अधिक पैसा नहीं मांग रहे हैं। जो पैसा मांगा जा रहा हैं वह तो खर्च हो

चुका हैं, अब कोई नई मांग नहीं है। यह तो जो खर्चा हो चुका हैं उसे स्वीकृत देनी हैं, यह संधिवान का तकाजा हैं। जहां तक देरी होने का संबंध हैं, उसका कारण यह हैं कि यह प्रोसैस बड़ा लम्बा हैं। पहले मामला पूरी तरह से विचार होता है और उसके प चात् रिर्पोट प्रस्तुत की जाती हैं। फिर विधान सभा के लिए स्वीकृत के लिए पे ा किया जाता हैं। तो उन सभी विधाओं को निभाने के लिए ये मांगे पे ा की गई थी। लेकिन माननीय सदस्यों का यह प्रयास होता हैं कि जब भी कभी अवसर मिलें तो हर सदस्यय अपने क्षेत्र की कठिनाइयों और मांगो पर प्रका ा डाले। यह स्वाभाविक हैं, जनता ने अनकी चुन कर भेजा हैं। ये अपने क्षे? का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी उनको मौका मिले उनको अपनी मांगो की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए। यह उनका कर्तव्य हैं। मैं कोई नुक्ताचीनी नहीं करता। मैं माननीय सदस्यो की सराहना करता हूं कि अपने क्षेत्र की मांग के लिए, कठिनाई के लिए बड़े सजग हैं और हर वक्त चर्चा करते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई सदस्य बोले। डा0 मंगल सैन ने कुछ बातें कहीं, सुझाव तो कुछ प्रस्तुत नहीं किया लेंकिन फरीदाबाद के डी0 सी0 के साथ अपनी बातचीत का हवाला दिया। अगर कोई अधिकारी किसी माननीय सदस्य के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो उसका यह तरीका ठीक नहीं हैं, उसकी निन्दा की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि डा0 साहब के साथ यदि ऐसी कोई बात हुई हैं तो वे मुख्य मंत्री जी के और सरकार के नोटिस

में पूरा विवरण लाएं, उनकी ि ाकायत पूरी तरह से दूर की जाएगी।

श्री हीरा नन्द आर्य ने कुछ सुझाव दिए। यह बात ठीक हैं कि जब तक प्र ाासनिक खर्चे में कमी नहीं की जाएगी, तब तक विकास के कामों के लिए पैसा नहीं बचेगा। उनका यह कहना बिल्कूल सही हैं। दिन प्रतिदिन कर्मचारियों के वेतनों पर खर्चे का भार बढ़ता जा रहा हैं। यह ठीक बात हैं कि सारे बजट का 50 प्रति ात लगभग कर्मचारियों पर आहिस्ता आहिस्ता खर्च होने लग जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया हैं कि प्र ाासनिक ढां़चे में सुधार के लिए कोई प्र ाासनिक सुधार आयोग की स्थपना की जाए। उनका यह सुझाव बहुत अच्छा हैं और इस पर सरकार विचार करेगी। अगर आव यकता समझी जाएगी तो इस प्रकार का आयोग भी बनाया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंनें एक सुझाव यह भी दिया कि डी0 आ0 डी0 ए0 की दृार एजेंसियां विकास के कामों क लिए बनाई हुई हैं, उनको एक ही एजेंसी बनायी जाए। एक बात उन्होनें यह भी कही कि नहरों की सफाई के खर्चे के बोगस बिल बनते हैं। इसके अलावा, कुछ और माननीय सदस्यों ने भी अपनी बातें कही हैं। खस तौर पर श्री रघु यादव जी ने, रावत जी ने और दूसरे कई माननीय सदस्यों ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में भ्रश्टाचार के बारे में काफी जोर – ाोर के साथ चार्चा की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात मानता हूं कि भ्रश्टाचार अभी हैं। लेकिन एक बात मैं

दावे के साथ कहता हूं कि जब से चौधरी देवी लाल जी की सरकार हरियाणा प्रदे ा में बनी हैं, उस समय से हमने भ्रश्टाचार में काफी कमी लाने का पूरा प्रयास किया हैं और कर रहे हैं। इसमे काफी सफलता भी मिली हैं। पिछली सरकार के वक्त में कहा जाता था कि अगर कोई तहसीलदार भर्ती करवाना हैं तो 50 हजार रूपए लगेंगे, कोई सिपाही भर्ती करवाना हैं तो 10 हजार रूपए लगेंगे। इसके अलावा, उस सरकार के समय में अगर कोई तबादला करवाना होता था तो पैस लिए जाते थे और कहा जाता था कि तबादले के इतने हजार लगेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस लानत को चौधरी देवी लाल जी ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया हैं। चौधरी देवी लाल जी की सरकार ने ऐसा काई मौका नही आने दिया और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हरियाणा प्रदे ा का कोई भी आदमी हमें ऐसा उदाहरण दे कि उसने कहीं पर भर्ती में या तबादले के लिए कोई पैसा दिया हैं? हमारे सिचाई के विभाग के मंत्री जी हाउस में बैठे है। बहन सुशमा जी आज अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सकी। यदि वे आज हाउस में होती तो अपने विभाग के बारे में जवाब देती। लेकिन मैं यह बात वि वास के साथ कहता हूं कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में, नहरी विभाग में, बिजली विभाग में यानी हर विभाग में इस बात की पूरी कोि ा ा की जा रही हैं कि भ्रश्टाचार को खत्म किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बिजली के लिए कोई नया प्रोजैक्ट या नया थर्मल प्लांट या कोई हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजैक्ट तो नही लगाया, फिर भी

हरियाणा के अन्दर बिजली कहां से बढ़ गई? आज हरियाणा प्रदे ा के अन्दर बिजली सप्लाई में यह चमत्कार कैसे हो गया? जहां पहले किसानों को चार घंटे बिजली नहीं मिलती थी, कारखानों पर बिजली का कट लगाया जाता था और कारखाने बंद रहते थे वहां आज 24 घंटे कारखानों, किसानों और घरेलू कामों के लिए बिजली मिल रही थी। यह कहां से आई? यह बिजली इसलिए आई क्योंकि पहले बिजली बोर्ड में भ्रश्टाचार था और बिजली बड़े बड़े कारखानेदारों को बेच दी जाती थी और बिजली की चोरी होती थी। अफसर और कर्मचारी रि वत लिया करते थे, वह सब अब बंद हो गया हैं। मैं चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होनें बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी सख्ती के साथ काम करें बिजली बोर्ड में सारे भ्रश्आचार को बांद करे आज हर क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराई हैं, यह बहुत ही सराहनीय काम हैं। बहन सुशमा जी ने भी अपने विभाग में भ्रश्टाचार को खत्म करने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए हैं। सभी विभागों में भ्रश्टाचार खत्म करेन के लिए हम सब कोि ा ा रक रहे हैं लेकिन यह बहुत पुरानी बीमारी हैं, जल्दी खतम होन वाली नहीं हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूं जो हरियाणा के अन्दर दी जाती हैं। एक 60–70 साल का व्यक्ति था। उसने अपना धर्म बदल लिया और मुसलमान बन गया। वह मस्जिद में गया वहां पर मौलवी ने उसको बैठा दिया और कहा कि अल्ला अल्ला करो। जब वह व्यक्ति अल्ला अल्ला करने लगा तो उसके मुह से राम राम निकलने लगा। इतने मूं वह मौलवी उस व्यक्ति

के एक लात मारली और कहने लगा, क्यों वे मस्जिद में बैठ कर राम राम भजता हैं? इस पर उस व्यक्ति ने मौलवी से कहा कि मौलवी साहब 60–70 साल से घुसी हुई राम राम तीन दिन में आत्मा से कैसे निकल सकती हैं? तो यह भ्रश्टाचार एकदम खत्म कैसे हो सकता हैं यह तो अहिस्ता अहिस्ता ही खत्म होगा। यह बीमारी अहिस्ता ही निकलेगी। इतने सालों की घुसी हुई रि वत व भ्रश्टाचार एकदम नहीं निकल सकता लेकिन इसके लिए प्रंयास चल रहे हैं और कोि ा ा की जा रही हैं। चौधरी देवी लाल जी का जो नारा बिजली–पीन का प्रबंध और भ्रश्टाचार बन्द का हैं, उसो पूरा करने की तरफ प्रयास जारी हैं। हमारे दूसरे मेम्बरों ने भी कई बातें कहीं। डाक्टर महा सिंह जी ने अस्पतालो की बात बतालाई। यह ठीक हैं कि जितनी दवाई मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिलती लेकिन इसके लिए पिछले दिनो हमारी एक कमेटी बनी थी। हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं। उस कमेटी में इस बात का प्रयास किया गया हैं कि दवाइयों के लिए कुछ बजट बढ़ाया जाये ताकि इसमें सुधर लाया जा सके। आयुर्वेदिक के बारे में जो बाते ंयहां पर कही गई हैं, वे भी ठीक कही गई हैं। भाई रघु जी ने बाढ़ के बारे में या दूसरी कुछ बाते वही कहीं है जो इन्होंनें जनरल बजट पर बोलते हुए कही थी। श्री जगपाल सिंह चौधरी, श्री भगवान सहाय रसवत, और चौधरी मनफूल सिंह जी ने तथा दूसरे जिन साथियों ने जो बाते इन डिमांडो पर बोलते हुए रखी हैं, उनके बारे मे मैं प्रत्येक विभाग के मंत्री जी से कहूंगा और उनके नोटिस में लाऊंगा कि जो कठिनाइयां जिन जिन की हैं,

उनको दूर करने की कोि ा ा की जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इन भाब्दों के साथ मैं आपके द्वारासदन से यह प्रार्थना करूंगा कि 219771085 रूप्ये की जो ऐक्सैस डिमांडज हैं और जो सन् 1983–84 में अधिक खर्च किया गया था संविधान के अनुच्छेद 205 के मुताबिक स्वीकृत की जाए।

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding Rs. 393012 be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of 2-General

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding Rs.4231271 be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of 6-**Revenue.**

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding Rs. 14004882 be made to regulatise the chares already incurred in excess of

the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of 10-**Medical & Pulic Health.**

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding Rs. 411000 be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **13-Social We;fare &Rehabilitation.**

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding Rs. 220493 be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **14-Food and Supplies.**

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding Rs. 153314203 be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **15-Irrigation.**

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding Rs. **2872280** be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **17-Ariculture**

That a grant of aa sum not exceeding Rs. **1341740** be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **18-Animal Development.**

The Motion was carried.

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding **Rs.7806716** be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of 21-**Community Development.**

The Motion was carried

Mr. Deputy Speaker: Question is-

That a grant of aa sum not exceeding **Rs.10149912** be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **23-Transport.**

That a grant of aa sum not exceeding Rs. 393012 be made to regulatise the chares already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1983-84 in respect of **24-Torurism**

The Motion was carried.

बिल्ज

(i) दि पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा सैंकंड अमैंडमैंट) बिल, 1988

श्री उपाध्यक्षः अब मिनिस्टर साहब, दी पंजाब ऐग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा सैकन्ड अमैंडमैंट) बिल, 1988 को कंसिडर करने के लिए मो ान मूव करेंगे

Agriculture Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir, I beg to move-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री रघु यादव (रिवाड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय अभी हरियाणा के कृशि मंत्री चौधरी तैयब हुसैन जी ने पंजाब कृशि उपन मार्कीटिंग मण्डीकरण हरियाणा द्वितीय सं ाोधन) विधेयक, 1988 सदन के पटली पर रखा हैं। व्यवधान माननीय उपाध्यक्ष महोदय इस सं ाोधन विधेयक पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस दे ा में आजादी के बाद कोई भी व्यवस्था भाासन चलाने के लिए हो सकती थी। दे ा की जनता

ने, दे ा के लोगौं ने दे ाकी आजादी के लिए संघर्श किया था और अनेकों बलिदान दिये थे। जनता ने दे ा का भाासन चलाने के लिए लोकतन्त्र की व्यवस्था को चुना था। लोकतन्त्र का अर्थ हैं स्वराज और स्व ाासन। स्वराज और स्वा ाासन तभी सम्भव हैं जब छोटी से छोटी इकाई से ले कर बड़ से बड़े केन्द्र तक हम लोग जनता की मर्जी से अपने पदभार ग्रहण करें, जनता की इच्छा के अनुरूप आचरण करें, नीतियां निर्धारित करें और योजना बनाए। उपाध्यक्ष महोदय, इस सं ाोधन विधेयक में कहा गया हैं कि मार्किट कमेटियां के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, उनसे विवाद पैदा हो जाते हैं, गुटबाजी होती हैं और झगड़े पैदा होते हैं। मैं माननयी कृशि मंत्री जी की इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूं। जब चुनाव होते हैं तो जो निर्वाचक मझडलन होता हैं, चाहे वह 20 सदस्यों कीकमेटी ही क्यों न हो, उसमें खेमे बन जाते हैं। लोग पहले, दसूर या तीसरे उम्मीदवार के पक्ष में विभाजित हो जाते हैं। क्योंकि चुनावों में ऐसा होना स्वाभाविक हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात केवल मार्किट कमेटिया के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनने में ही नहीं हैं, गांवों में पंचायत के चुनावों में सरपंच और पच चुनने में गुटबाजी, धड़े बन्दी पैदा होती हैं। नगरपालिकाओं, विधान सभाओं और लोक सभा के चुनावों में भी ऐसा ही होता हैं। यह कहना कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्वाचक मण्डल में गुटबाजी और धड़े बन्दी पैदा हो जाती हैं, इसलिए मनोनयन कर लिया जाए उचित नहीं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का मनोनयन या नामिने ान करना उचित नहीं हैं।

फिर कौन सा निर्वाचक मण्डल हैं जो स्वंय मनोनीत हैं? मार्किट कमेटी के सदस्यों को मनोनीत किया जाता हैं और ये मनोनीत सदस्य, ये नोमिनेटिड मैम्बर्ज अपने मे से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लें यह भी स्वीकार नहीं, यह लोकतंत्र और प्रजातन्त्र की प्रक्रिया और भावनाओं के प्रतिकूल होगा, अनुकूल नहीं होगा। सदस्यों को तीन वर्श के लिए मनोनीत किया जाता हैं लेकिन इस विधेयक में कहा गया हैं कि ऐसी कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है जिन के कारण उन सदस्यों के बीच में से हटाने की जरूरत पड़ती हैं। इसलिये ऐसा अधिकार भी दे दिया जाए कि जो सदस्य मनोनीत हैं जब मर्जी आए या जरूरत पड़ जाए, मंत्री जी के भाब्दों में, उन्हें हटा दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सभी सदस्य एक नि चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए हैं और अपने इस कार्यकाल के दौरान काम करते हैं। मार्किट कमेटी के जो मैम्बर होते हैं, वे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से केवल इसी नीति बात कर सकते हैं तालमेल रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि मार्किट कमेटी का अध्यक्ष उनके वोट के द्वारा चुना जाता हैं। यह आपसी तालमेल यह सुझावों का आदानप्रदान और परस्पर सहयोग मार्किट कमेटी के सुचारू संचालन और मण्डी क्षेत्र के उत्थान व विकास के लिये बेहद जरूरी भी हैं। (इस समय अध्यक्ष पदासीन हुए) अगर अध्यक्ष उनके मत के द्वारा नहीं चुना जाता हैं तो अध्यक्ष मार्किट कमेटी के मनोनीत सदस्यों को कह देगा कि मेरे कमरे मं आने की जरूरत नहीं हैं और अगर कोई सदस्य फिर भी किसी बात के लिए इनसिस्ट करेगा तो वह कह देगा कि मैं अीी

चण्डीगढ़ जा रहा हूं और वहां से तेरे को हटवा कर आता हूं। Sir, he will not hol;d office at the pleasure of the members of the Market Committee. There for he will not be responsibly to them and Members will have no business to do in the functioning of their Market Committee. इस तरह से वह कमेटी वाली बात खत्म हो जायेगी, एक ऐडमिनिस्टेटर वाली बात रह जायेगी। वह समिति का अध्यक्ष नहीं रह जायेगा बल्कि वह एक अधिकारी के रूप में, केन्द्र के रूप में काम करना भुरू कर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमें खूब सोच समझ कर मनोनीत करना चाहिए और जो मनोनीत हो उन्हें अपने मण्डल में अपनी समिति में अपने पदाधिकारी को चुनने का मौका दिया जाना चाहिए। कल जब यह सं ाोधन विधेयक पे ा किया गया था तब भी हमने माननीय कृ शि मंत्री महोदय से गुजारि ा की थी कि इसे वापिस ले लें। अध्यक्ष महोदय हम सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं। जितनी आस्था निश्ठा किसी भी मेरे अन्य माननीय सदस्य को हमारे दल में, हमारे दल में नहीं हैं, पूरी निश्ठा और आस्था हैं हम लोग भी यहां पर जनता द्वारा चुन कर भेजे गये हैं इसलिये जो कुछ भी सदन के सम्मुख प्रस्तुत हो, उस पर हम लोगों की भावना के अनुरूप बोले यही उचित हैं। आपके पीछे भी जो सदन की दीवार पर लिखा हुआ हैं उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह): सर, मै, एक निवेदन करना चाहता हूं। हाउस के सामने छोटी छोटी दो अमैंडमैंट्स हैं। एक पर विचार हो रहा हैं और दूसरी पर होना हैं।

इसलिए आप टाईम का ख्याल रखे ताकि एक बजे तक बिजनैस समाप्त हो जाये।

श्री अध्यक्षः ठीक हैं, टाईम का ख्याल रखेंगे।

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, एक निर्वाचित प्रतिनिधि और इस महान सदन विधेयक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और भावना के अनुकूल नहीं हैं इसलिए माननीय कृशि मंत्री इसे वापिस ले लें और कोि ा ा यह करें कि मार्किट कमेटी के मैम्बर्ज भी बजाए नोमीनेट करने के कृ ाकों, व्यापारियों और पल्लेदारों में से उनके अनुपात के आधार पर इलैक्ट हों। हमें मार्किट कमेटी जल्दी से जल्दी खड़ी करनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल का सदस्य होने के नाते मै यह कहूंगा कि अगर कृशि मंत्री ने इसे विदड्रा नहीं किया और वोट के लिए सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया तो मेरी भी हां ही आपको सुनने को मिलेगी।

श्री महा सिंह (राई): अध्यक्ष महोदय, जो सं ाोधन विधेयक रखा गया हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक बहुत सोच समझ कर और लोगों के हितों के अनुरूप रखा गया हैं। आज हर जगह पर प्रजातन्त्र हैं। गांवो में पंचायत के चुनाव होते हैं और पार्लियामेंट के होते हैं लेकिन किसी कोई आपत्ति नहीं हैं। चुनाव होते हैं, सदस्य इलैक्ट होते हैं लेकिन कुछ जगहें ऐसी है जहां चुनाव का नाम ले कर प्रजातन्त्र और जनतंत्र की भावनाओं को लागू नहीं किया जाता हैं।

मिसाल के तौर पर, अगर कोई भाई यह कहे कि आई0 ए0 एस0 ओर आई0 पी0 एस0 अफसरों का भी चुनाव होना चाहिए तो मैं समझता हूं कि यह बात दे ा के लिएऔर ऐडमिनिस्ट्रे ान के लिए गलत होगी। जहां सदस्य मनोनत ही हों वहां पर पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह जरूरी हें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लाजमी तेार पर नौमीनेट किये जाने चाहिए। यह हमारी मार्किट कमेटियों के हित में होगा और यही प्रजातंत्र के भी हित मे होगा। मार्किट कमेटिया में किसान लोग भी आते हैं, तोला भी आते हैं और आढ़ती भी आते हैं। इन सब की रिप्रेजैन्टे ान होती हैं। यिद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को नौमीनेट कर दिया जाये तो वह सब सर्व–सम्मति से उन लोगों की भलाई का काम मार्किट कमेटी में करेंगे। उन में फ्रिक ान नहीं होगी और पार्टीबाजी नही होगी। अन्त में मैं तहेदिल से इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, कल जब इस विधेयक को सदन मैं प्रस्तुत किया जा रहा था तब भी मैंने अपना दायित्व समझते हुए इसके विरोध में बात कही थी और आज भी मैं इन भाब्दों में अपनी बात को दोहराना चाहता हूं। इस दे ा में हमने लोकतांात्रिक जीवन पद्धति स्वीकार की हैं। Sir, we have accepted democratic way of life. अब हम इससे इतना घबराते हैं कि गावों में तो चुनाव हो जायें, कमेटी में चुनाव हो जायें, असैम्बली में चुनाव हो जायें, लोक सभा के चुनाव हो जायें, लेकिन मार्किट कमेटिया के चुनाव न हो जिसके जिसके नुमायंदे

तोला, अनपढ़ मजदूरी आदमी हैं, जिनके नुमायंद आढ़ती और किसानों में से वहां पर बैंठेगे।

कोआप्रेटिव सोसाइटीज में से वहां पर बैंठेगे उनके चुनाव क्यों नहीं होने चाहिये? पहली बार जब यह विधेयक बनाया गया था,पंजाब असैम्बली में मुझे भी सौभाग्य से मैम्बर होने का मौका मिला था। मुझे याद हैं तब भी बड़े जोरदार भाब्दों में सरकारी बैंचों की तरफ से यह कहा गया था कि लोकतन्त्र होना चाहिए। चुनाव होते रहे हैं यह बता ठीक हैं कि अब चुनाव बहुत खर्चीले हो गये हैं। ओल्ड वैल्यूज भी अब नहीं रही हैं। यह बात भी ठीक है कि हमने ओवर आल रिफार्मज के लिए इलैक ान कमी ान को लिखा हैं। प्रधान मंत्री जी नें अधूरे मन से यह ककहा भी हैं कि हम इस बारे में कुछ करेगें। यह बात भी ठीक है कि वैल्यूज का इरोजन भी हुआ हैं। मुझे माफ करेंगे, जिनके हाथ में केन्द्र में सत्ता हैं, सबसे बड़े मुजरिम वे हैं जम्हूरियत का जनाजा निकालने में। कम से कम हमें उस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। मेरा तो सुझाव मात्र हैं। मै अपने मित्र और सम्मानित सदस्य डाक्टर महासिंह जी से हय कहना चाहूंगा कि यह बात ठीक हो सकती हैं कि उनका अनुभव इतना नहीं हैं। उन्होंनें संघर्श में हमारा साथ दिया हैं। उनकी इस ब्यूरोक्रेसी की बात कहां से याद आ गयी? अगर आई0 ए0 एस0 अफसर इतने अच्छे हैं तो हमारी यहां पर आने के क्या जरूरत हैं? आई0 ए0 एस0 अफसर इतने अच्छें प्र ाासक तो हो सकते हैं लकिन इनका काम

तो ऐक्जीक्यूट करना हैं, पालिसी बनाने वाले तो ये लोग तजुर्बेकार हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग के बेटे हैं, इनको कई पार्टियों का तर्जुबा भी हैं। चूंकि वह मेरे परम मित्र हैं, इसलिये मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उनको अल्ला और भगवान के नाम पर यह कहूंगा कि जम्हूरियत के साथ ऐसा मजाक नही होन दें। मै ंसइ अवार पर एक बात और कहना चाहूंगा। प्रोफैसर सम्पत सिंह जी बैठे है और वीरेन्द्र सिंह जी भी विराजमान हैं। होडल में अभी मार्किट कमेटी का चुनाव हुआ हैं आनरेबल मैम्बर भी यहां पर बैठे हैं। अगर वह चाहे तो जवाब दे दें। मैंने पुलिस कप्तान फरीदाबाद को भी कहा हैं। मुझे ऐसा पता लगा हैं कि दो एम0 एल0 एज0 की राइविलरी में एक एम0 एल0 ए0 ने एक संरपंच को अगवा कर लिया और उसके 11000 रूपये साथ चले गये। It is a very serous mater. He umst come out with his ansewer. यह हुआ हैं या नही हुआ हैं, यह पता लगना चाहिए। अगर हुआ हैं तोnobody is above law. अगर मैं कोई हिमाकत करता हूं तो मुझे भी माफ नही होना चाहिये। कम से कम किसी सदस्य को तो माफ होना ही नहीं चाहिये। हमे तो कानून की इज्जत करनी चहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डाक्टर साहब, इसीलिए तो नोंमीने ान कर रहे हैं ताकि अगुवा न हो।

श्री मंगल सैनः तो फिर एम0 एल0 एज0 भी अगुवा न हों, उनकी भी नौमिने ान होनी चाहिये।

श्री वीरेन्द्र सिंहः डाक्टर साहब, वह भसी हो गये थे।

श्री मंगल सैनः उनको टाईगर कहा करते थे और बंसी लाल जी ने ऐसे टाईगर को गीदड़ बना दिया था। वह सदन में मौजूद नहीं हैं। सकी मूंछे मुडवा दी। उस बेचारे को जयपुर के एक होटल में रखा गया था। वह डिस्कवालीफाई हो गया। नारनौंद की जनता ने उस आदमी को इस बार नही भेजा हैं, किसी दूसरे आदमी को भेज रखा हैं। इसलिए मेरा कहना यह हैं कि इसमें ऐसी बात न रखें तो अच्छा होगा। बस मैं यही बात कहूगा।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह (मेवला महाराजपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो अमैडमैंट पे ा की हैं, इस पर बहुत से साथियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं।

Mr. Speaker: It is a very limited matter.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः मैं केवल अपने विचार ही प्रकट कंरूगां। अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं रघु यादव और डस्0 साहब को बधाई देता हूं कि सात्ता में हेते हुए भी उन्होनें अपनी निश्पक्ष और सही राय दी हैं।

श्री रघु यादवः अगर आपयह करते तो यह नौबत ही नहीं आती।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमारा दे ा सदियों की ताना ाही के बाद आजाद हुआ और हमने प्रजातन्त्र को मान्यता दी और आज भी चालीस साल के बाद हमारी मान्यता प्रजातन्त्र में घटी नही हैं बल्कि मजबूत हुई है। अध्यक्ष महोदय, डा0 साहब ने जो कुछ मकहा मैं उसे इत्तफाक नहीं रखता। हो सकता है डा0 साहब ने यह बात पार्टीबाजी के असर के कारण कही हो कि प्रजातंत्र का जनाजा केन्द्रीय सरकार ने निकाला था। डास साहब को 1977 का समय याद होगा। 1977 के बारे में सारा दे ा जानता हैं।

श्री अध्यक्षः महेन्द्र प्रताप जी, ाप बिल पर ही बोले। आप कन्ट्रोवर्सी की बात न करें।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं कन्ट्रीवर्सी की बातन नही कर रहा हूं। डाक्टर साहब ने कुछ बाते कही हैं इसलिये मै कह रहा हूं। जब कोई गलत बात की जाती हैं तो उसाक उत्तर आना ही चाहिए। (ाोर एवं व्यवधान) 1977 में भी यही सरकार थी और उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने ही इलैक ान कराने का फैसला किया था। ऐमरजैन्सी की आड़ में बहुत लोगों ने कहा कि इलैक ांज को आगे किया जा सकता हैं लेकिन इंदिरा जी, जो उस समय प्राईम मिनिस्टर थी, ने कहा कि नहीं प्रजातंत्र का यही तकाजा हैं कि इलैक ांज अभी करवाए जाएं। उन्होंनें इलैक ांज करवाए। जहां तक ऐमरजैन्सी का ताल्लुक हैं.....(व्यवधान)

एक आवाज इस वक्त ऐमरजैन्सी पर बोलने की क्या जस्टीफिके ान हैं?

श्री अध्यक्षः महेन्द्र प्रताप जी, आप बिल पर ही बोले। आप कन्ट्रोवर्सी में न पड़े।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मै इस पर जयादा समय नश्यट नहीं करना चाहता। इस विशय पर बहुत बहस हो चुकी हैं कि ऐमरजैंसी क्यों लगी थी? भाोर

श्री अध्यक्षः आप सवाल करने के वक्त भी ऐसा ही बोलते हैं (व्यवधान) आप बिल पर ही बोलें।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः कभी भी इन्दिरा जी ने प्रजातन्त्र के खिलाफ काम नहीं किया। कल तक तो डा0 साहब कुछ और ही बोलते थे। फरीदाबाद में तो किसी और तरह के आसूं बहाते थे लेकिन यहां आकर पता नही क्या मजबूरी हो जाती हैं? भाोर

Mr. Speaker: This is not the way, Haehnder Partap Ji. I would not allow you to speak.You always o beyond the scope of the matter under discussion.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः इन्दिरा गांधी जी ने प्रजातन्त्र के विपरीत कभी कोई काम नहीं किया।अगर प्रजातंत्र के विपरीत काम करने की बात आप सुनना चाहते हैं जो मैं नही कह रहा हूं, सारा दे ा कह राह हैं, इस प्रदे ा की जनता भी कह रही हैं।

म्यूनिसिपल कमेटीज के इलैक ांज में कल तक तो डा0 साहब भी कुछ और ही कहते थे। आज पता नहीं डा0 साहब कौन सी भाशा बोलनेलगे हैं। फरीदाबाद मे जाकर तो किसी और तरह के आंसू बहाते थे लेकिन पता नहीं यहां आकर क्या मजबूरी हो जाती हैं कि कुछ और ही बोलना भुरू कर देते हैं। (ाोर) इलैक ान कमी ान का फैसला ताना ााही का सबूत है या प्रजातंत्र का सबूत हैं? भाोर

Mr. Speaker: Mr.Mahender Partap Singh, please have your seat. I willl not allow you to speak in this matter.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः मै तो इसलिए कह राह हूं कि यह लोग चाहते हैं। (ाोर)

Mr. Speaker: Mr. Mahender Partap Singh, I will not allow you to speak like this.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, आप मुझे एक मिनट दे दे। मैं अपनी बात एक मिन में खत्म कर देता हूं।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। इन्होंने कहा हैं कि ये बाहर कुछ आंसू बहाते हैं और अन्दर कुछ कहते हैं। हम तो जहां थे वही रहेंगे। मै ंवह नहीं हू कि लोकदल की टिकट लेकर इलैक ान जीतूं और फिर कांगेस में घुस जाऊ। हम तो जहां थे वही रहेंगे और अर्थी निकलेगी तो अपने घर से ही निकलेगी। (ाोर)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, मुझे कृपया एक मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्षः आप तो जानबूझकर कन्ट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। जब सवाल पूछते हैं तब भी कन्ट्रोवर्सी में फंस जाते हैं।

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः स्पीकर साहब, जब इन्होंने कुछ कहा है तो मेरा जवाब देना जरूरी हो जाता हैं।

Mr. Speaker: I Will not give you more than one minute.

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही खत्म कर दूगा। माननीय मंत्री महोदय ने कांग्रेस की परम्पराएं देखी हैं। पता नहीं इन पर क्या असर पड़ गया। पता नहीं सरकार को मार्किट कमेटीज में नौमिने ान की क्या जरूरत पड़ गई हैं? भाई रघु याद ने जो कुछ कहा मैं उससे इत्तफाक करता हूं कि पता नहीं सरकार ने क्यों लिख दिया कि नौमिने ान करने से मार्किट कमेटीज में धड़ेबाजी कम होगी और मार्किट कमेटीज अच्दी तरह से काम कर सकेंगी। अध्यक्ष महोदय जो व्यक्ति नौमिने ान से मैम्बर बनते हैं ओर इत्तफाक राय या बहुमत के आधार पर उन व्यक्तियों को धड़ेबाजी से अलग नहीं रख सकते ऐसे व्यक्तियो को नौमिनेट करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए यह तर्क न्याय संगत नहीं हैं। इस तरह तो पंचायत के मैम्बर्ज, एम0 एल0 ए0 और एम0 पीज 0 जो चुनकर आते हैं वे भी धड़ंबाजी पैदा करते हैं। अगर भ्रुरू से ही इस को

बन्द कर दिया जाए तो अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं नही समझता कि इसके पीछे सरकार की क्या मन ाा हैं? पंचायतों के इलैक ान हो चुके हैं। एम0 एल0 एज0 को नौमीनेट करना या न करना मैं तो सरकार की इस बात को समझ नहीं सका कि इस के पीछे मन ाा क्या हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से , सरकार से व मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि चूकिं पंचायत के इलैक ान हो चुके हैं, अगर ाप पुरानी परम्पराओं के अनुसार जिनपर आप की आस्था थी, अल्प संख्यक समुदाय के लोगों में से आप मार्किट कमेटी के मैम्बर्ज नौमीनेट करते तो ज्यादा बेहतर होता। मुझे पूर्ण आ ाा हैं कि सरकार अव य मेरे इन सुझावों पर विचार करेगी। इन भाब्दों के साथ मै इस अमैडमैंट का विरोध करता हुआ अपने स्थान लेता हूं।

श्री भगवान सहाय रावत (हथीन): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय कृशि मंत्री महोदय ने जो पंजाब कृशि उपज मण्डी (हरियाणा द्वितीय सं ाोधन) विधेयक, 1988 प्रस्तुत किया हैं, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हैं। मेरे से पहले आदरणीय डाक्टर साहब जो बड़े अनुभवी हैं और इस हाउस के विधायक चले आ रहे हैं, ने अपने विचार रखे। उनका अपना अनुभव हैं और मेरा पना प्रथम बार विधायक चुने जाने के बाद मार्किट कमेटी का थोड़ा सा निजी अनुभव हैं। इस सं ाोधन विधेयक की जो मूल आधार बात हैं, उसमें कोई सं ाोधन नहीं हैं। पहले भी परम्परागत ढंग से मार्किट कमेटियों के मैम्बर्ज

नौमिनेट होते रहे हैं और आज सं ाोधन केवल मात्र इतना हैं कि नौमिनेटिड मैम्बर्ज में से उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनो ही नौमीनेट होंगे। इस बारे में तो मै कृशि मंत्री महोदय और पअनी सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि वास्तव में उन्होंनें उस पुरानी प्रथा,ख जिससे हरियाणा का नाम कलंकित रहा हैं, खरीदो फरोखत के नाम से कलंकित रहा हैं, विधायकों का इधर–उधर जाने के नाम से कलंकित रहा हैं, यह बिल लाकर इन सब कलंकित बातों से प्रान्त को बचा लिया हैं। अध्यक्ष महोदय, मै तो भुगतभोगी रहा हूं। यह प्रैक्टीक्ली दिक्कत रही हैं कि प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में तीन–तीन, चार–चार विधायकों का क्षेत्र पड़ता हैं और आज जिस क्षेत्र का मै ंप्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसके प्रतिनिधियों को पिछले 41 सालों से मार्किट कमेटी का गांव हसनपुर क्षेत्र के पड़ते हैं। निजी रूप से जिन लोगों का प्रतिनिधित्व मै ंकरता हूं उनका हक मांगना मुझे न्याय संगत लगता हैं। क्योंकि जब इन कमेटियों के मैम्बर्ज को नौमीनेट किया जाता था, उसके बाद चेयरमैन और वाईस चेयरमैन की इलैक ान के लिए हफड़ा तफड़ी मचती थी और लड़ाई झगड़े की नौबत आतीथी। सामाजिक रूप से वहां के प्रतिनिधि को भी जिम्मेदार ठहराया जाता था, लेकिन मै सदन के सामने एक बात कहना चाहता हूं और डाक्टर मंगल सैन जी को आमंत्रि करता हूं कि जिस मार्किट कमेटी के बारे में उन्होनें रैफरेन्स दिया हैं उस सम्बन्धा में वह बाहर हम से अलग से बात कर लें और सारी बातचीत जानकर जो हमें आदे ा देंगे, हमें मन्जूर होगा। इस सं ाोधन की वजह से एक मार्किट कमेटी को

तीन चार लाख रूपया मिलेगा। यह तो सब को मालूम हैं कि यह अतिरिक्त रा ि ा विकास कार्यो के लिए प्रयोग होगी।

श्री मंगल सैनः स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर हैं। स्पीकर साहब, क्या कोई माननीय सदस्य किसी एम0 एल0 ए0 के बुजुर्ग पिता जी के बारे में कोई कमैन्ट कर सकता हैं? ये गया राम आया राम के बारे में कह रहे हैं। (भाोर)

श्री भगवान सहाय रावतः स्पीकर साहब, मैंने गया लाल व किसी व्यक्ति वि ोश के बारे में कुछ नहीं कहा हैं। (भाोर) मैंने आने वाले और जाने वाले के विशय में कहा हैं। (भाोर) मैंने उनका नाम नहीं लिया हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर सर, जब वीरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती जी आया राम गया राम की रिर्पोट लिख रहे थे, उस समय डाक्टर साहब अपने जमाने में विपक्ष मे सर्वेसर्वा हुआ करते थे। बड़े अफसोस की बात हैं कि इन्होंनें उस वक्त इस बारें में कुछ नहीं कहा था और आज डाक्टर साहब यहां पर तीर चला रहे हैं।

श्री भगवान सहाय रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहूगा कि जहां हम अतिरिक्त रा ि ा विकास कार्यो के लिए देते हैं वहां मार्किट कमेटीज का बजट 50 लाख रूपए का हैं। नि ि चत रूप से उससे विकास कार्य हो सकेंगे। इन भाब्दों के साथ मै इस सं ाोधन का स्वागत करता हूं।

श्री उदय (भान हसनपुर): स्पीकर साहब जो प्रस्ताव रखा है और मार्किट कमेटीज के बारे मे जो भावना डा0 साहब और रघु यादव जी ने रखी, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। मै कहना चाहता हूं कि कोई भी मैम्बर जो नौमिनेटड है, उनको अपनी मनमर्जी से चयन करना चाहिए और चेयरमैन सभी की सहमति से बनना चाहिए। इसमें हल्के वाली बात नहीं होनी चाहिए कि यह इस हल्के का हैं और वह उस हल्के का हैं। जहां तक खरीद–फरोखत की बात हैं, खरीद फरोखत तो वे आदमी करते हैं जो बन्दुक की नोक पर अगुवा करते हैं। (ाोर)

श्री अध्यक्षः ठीक हैं, आप कृपया बैठिए।

कृशि मंत्री (श्री तैयब हुसैन): मोहतरिम स्पीकर साहब, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बिल मैं कोइ इतनी लम्बी चौड़ी बात नहीं थी। यह तो एक बहुत जरूरी और मिनिमम अमैंडमैट हैं। ऐसी कोई खास बात नहीं थी जिसके लिए रघु यादव, डा0 मंगल सैन और खास तौर पर मेरे अजीज महेन्द्र प्रताप सिंह को कहने की जरूरत थी। इसमें सीधी बात थी। आज चौधरी देवी लाल का राज हैं। इसमें कोई जम्हूरियत की बात कहे तो वह अजीब सी लगती हैं। सरकार ने म्यूनिसिपल कमेटीज के चुनाव जल्दी करवा दिए और अभी पंचायतों के चुनाव भी करवाए हैं। ये सारी चीजें आपक `सामने हैं। इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं हैं। डा0 साहब ने एक तरफ तो होडल की मिसाल दी और दूसरी तरफ और कुछ कहा। फिर इन्होंनें मेरे वालिद मरहूम का जिक्र किया

और मेरा भी जिक्र किया। मैं अपने तजुरबे की बिनाह पर यह अमैडमैंट लाया हूं ताकि काम सही ढंग से और सुचारू रूप से चल सके। मैं बताना चाहता हूं कि मार्किटिंग बोर्ड की, 1984–85 में कुल 22 करोड़ रूपये की आमदानी हुई थी और इस साल 28 करोड़ रूपए की आमदनी हुई हैं और वह भी सूखे के बावजूद। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम करना चाहते हैं। ये असलियत से हट कर बात करते हैं। श्री रघु यादव जी आइडियो लिज्म की बात करते हैं। इनको असलियत के करीब रहने की कोि ा ा करनी चाहिए। हमारे नौजवान साथी हैं इनको प्रैक्टिकल नजरिये से करनी चाहिए। (भाोर)

श्री रघु यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेने ान देना चाहता हूं। (ाोर)

चौधरी तैयब हुसैनः स्पीकर साहब, मैंने तो यह कहा है कि ये हमारे नौजवान साथी हैं। मैं यह बात क्लीयर कर देना चाहता था और चौधरी महेन्द्र प्रताप की वाकफियत के लिए बताना चाहूगा कि पहली दफा 1970 में इस इस बिल में अमैंडमैंट लाई गई थी और उस समय चौधरी भजन लाल ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर होते थे। (भाोर)

चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंहः आप यह अमैडमैंट लाकर उससे भी आगे जा रहे हैं।

चौधरी तैयब हुसैनः स्पीकर साहब, इसी सिलसिले में 1978 में जब चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, इन्होंनें इसमें प्रोविजन किया था कि चुनाव हो लेकिन किसी वजह से चुनाव नहीं हो पाए थे। उसके बाद मार्च, 1980 में सरदार तारा सिंह ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर थे और चौधरी भजन लाल चीफ मिनिस्टर थे, उस समय भी नोमिने ान को प्रोविजन किया गया था। यह रिकार्ड की बात हैं और यह सही बात हैं। ये सारे मामलता उस सरकार के समय से भाुरू हुए हैं। मैंने यह बात चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह जी की वाकफियत के लिए कही है। इसमें तो कोई खास बात नहीं हैं इस अमैडमैंट में तो यह प्रविजन किया गया हैं कि अगर मार्किटिग बोर्ड में या मार्किट कमेटीज मे इस तरह क चीज की जहां जरूरत हो इसको इस तरह से इस्तेमाल कर लिया जाए। पहले यह था कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन उत्पादक सदस्यों और लाईसैन्सदारों में से चुने जाए। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया से मंडी समिति में धड़ेबन्दी और दू मनी हो जाती हैं। इसलिए ऐसी प्रवृति से बचने और विकास गतिविधियों को तेज करने के लिये यह अमैडमैट की जा रही हैं। चेयरमैन और वाईस चेयरमैन सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएगें इसमें कोई खास बात नहीं हैं। इन भाब्दों के साथ मैं हाउस से प्रार्थना करूंगा कि इस अमैडमैंट को युनानीमसली पास करें।

Mr. Speaker: Question is –

That the Punjab Agricultural Prodve Markets (Haryan Second Amendment) Bill be taken ino conideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House conder the Bill Clause by clause.

CLASUE 2

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 Stand part of the Bill

The motion was carried.

CLASUE 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 3 Stand part of the Bill

The motion was carried.

CLASUE 4

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 4 Stand part of the Bill

The motion was carried.

CLASUE 5

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 5 Stand part of the Bill

The motion was carried.

CLASUE 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 Stand part of the Bill

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried

Title

Mr. Speaker: Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the Agriculture Minster will move that the Bill be passed.

Agriculture Minister (Shri Tayyab Hussain): Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Bill be passed

The Motion was carried.

(ii) दि पंजाब न्यू टाउनि ाप (स्ट्रीट लाइटिंग एण्ड वाटर सप्लाई) फीस हरियाणा रिपील बिल, 1988

Mr. Speaker: Now the House Home Minister will move for the consideration of the Punjab New Townships (Street Lighting and Water Supply) Fees Haryana Repeal Bill, 1988.

ग्रह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि पंजाब नए नगर क्षेत्र (मार्ग प्रका ान तथा जल प्रदाय) फीस हरियाणा निरसन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker: Motion Moved-

That the Punjab New Townships (Street Lighting and Water Supply) Fees haryana Repeal Bil be taken into consideration at once.

श्री हीरा नन्द आर्य (लोहारू): अध्यक्ष महोंदय, जो विधेयक पे ा किया गया हैं,, मैं उसका समर्थन करने के लिय खड़ा हुआ हूं। यह बात ठीक हैं कि एक जगह बसते हो, एक

जगह व्यापार करते हों और सारा काम एक जगह पर होता हो तो किसी के साथ कोई भेदभाव नही होना चाहिए। आज हिन्दुस्तान को आजाद जहुए कई साल हो चुके है। सभी जानते हैं जब दे ज्ञ सन 1974 में आजाद हुआ था और कुछ लोग जो पाकिस्तान से यहां पर आए थे, उनको बसाने के लिए कुछ वि ोश प्रावधान किए गए थे और इन वि ोश प्रावधानों के तहत ही उन लोगों को रियायते दी गई थी, उस वक्त उनको रियायते देना भारू किया था क्योंकि जब एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर बसता ह। तो उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़तमा हैं। दे ा को आजाद हुए 41 साल के आस पास हो चुके है और अब हम नही समझते कि उन लोगों को नए भाहरों में मकान खरीदने के लिए गली में रो ानी तथा मकानों में पानी उपलब्ध करवाने की फीस की अधिकतम दर क्रम ाः 3.50 रूपये व 6.50 रूपए निर्धारित की गई थी। इससे ज्यादा पैसा इन लोगों से अब तक नहीं लिया जाता था। चूंकि इन लोगो का आए हुए काफी साल हो चुके हैं और वे यहा पर अच्दी तरह से बस चुके हैं इसलिए अब उनको दी गई रियायते वापिस लेनाा एक अच्दी बात हैं। अब वे यहां पर अच्छी प्रकार से सैटल हो चुके हैं इस अमैडमैट के जरिये यह पव्रावधान किया गया कि जो फीस लोगों से ली जा रही हैं वही फीस इन लोगों से भी ली जाएगी। जब ये यहां के बासिन्दे हो गए है तो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार हो, यह एक अच्छी बात हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हुए अपना स्थान लेता हूं।

श्री रघु यादव (रिवाड़ी) अध्यक्ष महोदय, पंजाब नए नगर क्षेत्र (मार्ग प्रका ान तथा जल प्रदाय) फीस हरियाणा निरसन विधेयक, 1988 जो सदन में विचार के लिए प्रस्तुत किया गया हैं, इसका मैं समर्थन करता हूं। इसमें यह कहा गया हैं कि पाकिस्तान के जो विस्थापित आजादी के समय यहां आये थे, उनको बसाने के लिये कई सुविधांयें दी गई थीं ताकि उनके पुनर्वास में उन्हें मदद मिल सके। उनके लिए एक सुविधा दी गई थी कि गलियों में रो ानी और मकानों में पीन उपलब्ध कराने के लिए 3.50 रूपये व 6.50 रूपए फसी निर्धारित की जाये। इस अधिनियम में पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो फीस 38 साल पहले निर्धारित की गई थी, बढ़ाई जा सके। आज इस सं ाोधन के जरिए सरकार को यह अधिकर मिल जायेगा कि वह वर्तमान दरों के अनुसार दूसरे नागरिकों की तरह ही इनसे भी फीस ले सकें। उनको आए दरों के अनुसार दूसरे नागरिकों की तरह ही इनसे भी फसी ल सके। उनको आए हुए काफी समय हो चुका हैं और अब वे यहां के बारबर के नागरिक बन गए हैं। यह बिल्कूल उचित और सही हैं कि समय के साथवह समजा के अंग बनें इन लोगों को हर दृश्टि से हर क्षेत्र में ाामिल करें यह अच्छी बात हैं। मे इस बिल का समर्थन करते हुए गुजारि ा करना चाहूंगा कि इस समय और भी बहुत से कानून ऐसे चल रहे हैं जिनके अन्तर्गत कर्ज लेने वालों को कर्ज लेते समय और बच्चों को स्कूल की फीस देते समय इस ब्यान पर दस्तख्त करने पड़ते हैं कि उसके परिवार की वार्शिक आय दो या तीन हजार से ज्यादा नहीं हैं। जिस मसय ये दो या

तीन हजार रूपये की वार्शिक आय काफी होती थी। लेकिन आज मंहगाई के इस जमाने में जब कि रूपए का अवमूल्यन हो चुका हैं, दो या तीन हजार रूपये की वार्शिक आय बहुत ही मामूली है, कम हैं। जिस भावना से यह सं ाोधन बिल यहां लाया गया हैं उसे ध्यान में रखते हुए मैं यह गुजारि ा करूंगा कि वार्शिक आय के सम्बन्ध में तथा विधायकों और अधिकारियों को उन झूठे आंकड़ो का सत्यापित न करना पड़े। इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं धन्यवाद

श्री बलवीर सिंह (फतेहबाद): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के जो एम्ज एण्ड औब्जैक्टस हैं, उस में कोई भाक नहीं किये तारीफ के योग्य हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो वाटर वर्कस न्यू टाउनि ाप के लिए बनाए जा रहे हैं, उनमे से ही पानी सारी भाहरों को सप्लाई किया जा रहा हैं। जिसके कारण हर न्यू टाऊनि ाप में पीने का पानी की समस्या बनी हुई हैं। हमारे फतेहाबाद टाऊनि ाप में पानी नहीं मिलता और बिजली की भी कोई व्यवस्था नहीं हैं। मैं यह निवेदरन करूंगा कि जहा ंएक तर ये पैसा बढ़ाने जा रहे हैं वहां लोगों की समस्याओं की तरफ भी डिपार्टमैंट्स और मिनिस्टर को ध्यान देना चाहिए और इसकी पूरी छानबीन की जानी चाहिए ताकि टाऊनि ाप में लोगों के लिए पानी और बिजली को सही व्यवस्था हो सके। टाऊनि ाप में कई जगहों पर सड़को पर नी–लैवल तक के गढ़े पड़े हुए हैं। इस बारे में मैं यह सुझाव दूगा कि खाली पैसे

बढ़ाने की तरफ ही ध्यान न दिया जाए बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाए। इसके साथ ही मैं फतेहाबाद टाऊनि ाप मे बिजली और पानी की व्यवस्था की ओर ध्यान देने क निवेदन करते हूए इस बिल का समर्थन करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, मेरे दो साथी इस विधेयक पर बोले और उन्होंनें इस का समर्थन किया हैं। श्री रघु यादव ने जो बात उठाई हैं वह इस विधेयक और महकमे से अलग हैं और सरकार इसे अलग से देखेगी। चौधरी बलवीर सिंह जी ने टाऊनि ाप से भाहरों में पानी की सप्लाई का जिक्र किया हैं। इस बारे में मैं कहना चाहूगा कि टाऊनि ाप में जो वाटर वर्कस बनाए जाते हैं वे सरकार के अनुदान से पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट द्वारा बनवाए गए हैं। जहां तक पानी की सप्लाई की दिक्कत का सम्बन्ध हैं, मेरे साथी मुझे अक्सर मिलते रहे हैं लेकिन उन्होनें इसका कभी जिक्र नहीं किया हैं। उनकी बात मेरे नोटिस मे हैं और इसे जरूर दूर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करूंगा कि इस बिल को पास किया जाए।

Mr. Speker: Question is –

That the Punjab New Townships (Street Lighting and Water Supply Fees Haryana Repeal Bill be taken into consideration at once.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the House will consider the Bill Clause by Clause.

Clause 2

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 2 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is-

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Forumla of the Bill.

The motion was carried.

Titel

Mr. Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now, the Home Minister will move that the Bill be passed.

गृह मंत्री (प्रो0 सम्पत सिंह): स्पीकर साहब, मै ंप्रस्ताव करता हूं–

कि बिल पास किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is-

That the Bill be passed.

The motion was carried.

श्री अध्यक्षः अब हाउस कल प्रातः 9:30 बजे तक के लिए ऐडजर्न किया जाता हैं।

(13:00 बजे)

(तत्प चात सदन बुधवार, दिनांक 24 अगस्त, 1988 को प्रातः 9:30 बजे तक के के लिए स्थगित हुआ)